

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वर्ष 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक वृद्धि सुदृढ़ थी। कई केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में गिरावट के जवाब में कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति रुख को अपनाया है। भारत में, उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि मोटे तौर पर पिछली तिमाही में हासिल की गई गति को बनाए रख रही है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के शुरुआती आगमन के साथ कृषि की संभावनाएं उज्ज्वल हो रही हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है, जो इसके मूल घटक की निरंतर कमी से प्रेरित है, हालांकि अवस्फीति का मार्ग अस्थिर और उच्च खाद्य कीमतों द्वारा बाधित है।

परिचय

कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1915 में सड़क के एक दोराहे के बारे में लिखा था जो एक पीले जंगल में विभाजित हो रहा है और वह दोनों रास्तों पर यात्रा करने में सक्षम नहीं है।¹ एक सदी और एक दशक बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गहरे निहितार्थों के साथ मौद्रिक नीति की लहरों पर सवार होकर एक "फ्रॉस्ट" विभक्ति का क्षण आ गया है क्योंकि यह आस्ति और मुद्रा बाजारों में परिलक्षित होता है। लगभग पाँच वर्षों में पहली बार, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के बीच में शामिल हो गया - बैंक ऑफ इंग्लैंड के शीघ्र ही अनुसरण करने की उम्मीद है - और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के मध्य ब्राजील, मैक्सिको, चिली, हंगरी और चेक गणराज्य ने अपनी नीति दरों को एक चौथाई अंक तक कम कर दिया और दरों में वृद्धि की ऐतिहासिक शृंखला को उलटना शुरू कर दिया। मुद्रास्फीति में

* यह आलेख माइकल देवब्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, शशि कांत, अर्पिता अग्रवाल, आकाश राज, सौमश्री तिवारी, कुणाल प्रियदर्शी, गरिमा वाही, रमेश कुमार गुप्ता, शेषाद्रि बनर्जी, हरेंद्र बेहेरा, के. एम. नीलिमा, अमित कुमार, रिग्जिन यांगडोल, मधुरेश कुमार, एलिस सेबेस्टियन, विजया अग्रवाल, खुशी सिन्हा, आयुषी खंडेलवाल, ऐडम अभिन्नू यादव, प्रतिभा केडिया, शैलजा भाटिया, मनु स्वर्णकार, सिन्धा योगिन्द्रन, योगेश राणा, अवनैश कुमार, कार्तिकेय भार्गव, प्रियंका सचदेवा, दिलप्रीत शर्मा, हिमानी शेखर, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहेरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और श्रीमती रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

¹ फ्रॉस्ट, रॉबर्ट, "द रोड नॉट टेकन" इन ए ग्रुप ऑफ पोयम्स, अटलांटिक मंथली, 1915, अगस्ता

2.5 प्रतिशत अंक से अधिक की गिरावट के जवाब में, 'डायलिंग बैक' शुरू हो गया है, लेकिन "जो अनिश्चित है वह यात्रा की गति और इसमें लगने वाला समय है"²। ईसीबी ने चेतावनी दी कि यह किसी विशेष दर को अपनाने के मार्ग पर चलने के लिए पूर्व-प्रतिबद्ध नहीं था और आगे की चाल प्राप्त होने वाले आंकड़ों पर निर्भर करेगी। अमेरिका की तरह यूरोप को वेतन और सेवाओं की कीमतों में समान गतिरोध का सामना करना पड़ता है - वास्तव में, यूरो क्षेत्र में हेडलाइन और मूल मुद्रास्फीति, दोनों में मई में वृद्धि हुई। ईसीबी के अपने पूर्वानुमानों के अनुसार, यूरो क्षेत्र की हेडलाइन मुद्रास्फीति के वर्ष 2025 में भी भली-भांति लक्ष्य से ऊपर रहने की संभावना है। फिर भी वर्ष 2024 की पहली तिमाही में क्षीण सुधार को छोड़कर, अटलांटिक के दोनों छोर पर रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि मजबूत रहने के बावजूद, 2022 के अंत से वृद्धि काफी हद तक रुक गई है। उस पृष्ठभूमि में, ईसीबी की कार्रवाई व्यावहारिक और एहतियाती प्रतीत होती है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधि पर क्रेडिट की उच्च लागत के प्रभाव बनाम भविष्योन्मुखी संकेतकों में मुद्रास्फीति की बदलती गतिशीलता में जोखिमों के संतुलन का पता लगाती है।

यह कार्रवाई यूएस फेडरल से विचरण के लिए मंच तैयार करती है, जिसके महीनों तक अनुसरण करने की उम्मीद नहीं है। हालांकि अप्रैल और मई की रीडिंग में अमेरिका में मूल मुद्रास्फीति कम हो गई, उपभोक्ता 'नो लैंडिंग' कथा में प्रमुख नायक बना हुआ है जो आर्थिक गतिविधि के अंतर्निहित समुत्थानशीलता को चिह्नित करना जारी रखता है। फिर भी, फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की घोषणा में देरी के बावजूद मंदी के संकेत मिल रहे हैं। इसका मुख्य प्रमाण अप्रैल में कमजोर निजी खपत व्यय है। उस महीने में खुदरा बिक्री भी स्थिर हो गई। सैन फ्रांसिस्को फेड के अनुसार, परिवारों ने मार्च में महामारी काल की अपनी 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त बचत खर्च कर दी, जिससे उन्हें क्रेडिट कार्ड पर अधिक से अधिक निर्भर होना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, खाते ऐसी गति से बकाया हो रहे हैं जो आखिरी बार वर्ष 2011 में देखी गई थी। जिन लोगों ने कार खरीदने के लिए ऋण लिया था, वे पुनर्भुगतान में पिछड़ रहे हैं, जिससे उन्हें अपने वाहन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है³। हालांकि मई के लिए

² प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौद्रिक नीति वक्तव्य, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, 6 जून 2024।

³ दि इकोनॉमिस्ट, 8-14 जून 2024।

गैर-कृषि पे-रोल ने उल्टा आश्चर्यचकित किया, नौकरी के अवसर भी महामारी-पूर्व के स्तर तक कम हो गए हैं और चिंताएं बढ़ रही हैं कि यह नौकरियों की समाप्ति का पूर्व संकेत है⁴। जैसे-जैसे परिवारों के तुलन-पत्र कमजोर होते हैं, मुख्य सर्किट ब्रेकर को मुद्रास्फीति में गिरावट और प्रयोज्य आय में नए सिरे से वृद्धि की बहाली शुरू करनी होगी। 2024 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट तथा मई में लगातार दूसरे महीने विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक के ऋणात्मक क्षेत्र में जाने से चिंताएं बढ़ गई हैं कि मौद्रिक नीति को सख्त बनाने के विलंबित प्रभाव हावी हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट अर्थशास्त्रियों के बीच तीखी आवाज़ें सुनी जा रही हैं कि हालात और खराब होने से पहले ही फेडरल रिजर्व को सहजता लाना शुरू कर देनी चाहिए। वित्तीय बाजार स्पष्ट रूप से विचलन को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। बॉन्ड प्रतिफल नई ऊंचाई पर पहुंच गए, और जोखिम-विमुख रुझान बढ़ने से स्टॉक इंडेक्स भी लड़खड़ा गए। यहां तक कि कम रेटिंग वाले बॉन्ड में भी वृद्धि देखने को मिली है। जैसे ही स्वैप करव में अंतर्निहित ब्याज दरों की बाजार प्रत्याशाएँ अलग हो जाती हैं, वैसे ही अटलांटिक के दोनों ओर वित्तीय स्थितियां होती हैं, हालांकि ट्रान्स-अटलांटिक मुद्रा में कम उतार-चढ़ाव होने की संभावना है। मुद्रा बाजारों में ब्याज दर के अंतर का फायदा उठाने के लिए प्रतिफल संवाहक व्यापार (कैरी ट्रेड) में कर्षण देखने को मिला है। कैरी ट्रेड के केंद्र स्थल यानी-उभरते बाजारों में - एक मजबूत वापसी हुई है, खासकर जहां ब्याज दरें अधिक हैं और केंद्रीय बैंक सतर्कतापूर्वक बात रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) ने भविष्यवाणी की है कि अगर वैश्विक वृद्धि जारी रहती है तो 2024 में उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह एक तिहाई बढ़कर 903 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है। पूर्व में, जापानी येन 34 वर्षों के निम्नतर स्तर पर आ गया है, जिसमें हस्तक्षेप का प्रभाव केवल अस्थायी है। बाजार का दबाव बढ़ने से रेनमिनबी कमजोर हो रहा है ताकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा सख्त दैनिक निर्धारण के बावजूद अमेरिका के साथ बॉन्ड प्रतिफल अंतर में अंतराल को प्रतिबिंबित किया जा सके। एक नया घटनाक्रम, जो पण्य (कमोडिटी) बाजारों पर विपरीत प्रभाव डालेगा, जिसमें धातु की कीमतें पहले से ही बढ़ रही हैं, ओपेक प्लस के सदस्यों ने कमजोर वैश्विक मांग और

दुनिया के अन्य हिस्सों से आपूर्ति में वृद्धि के बीच कीमतों को बढ़ाने के लिए 2025 के अंत तक तेल उत्पादन में अधिक कटौती का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। यह अगले साल के अंत तक बाजार से प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति बंद रखेगा। सऊदी अरब, रूस, इराक और संयुक्त अरब अमीरात सहित आठ सदस्य अक्टूबर से कुछ स्वैच्छिक कटौती करेंगे।

इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र ने जून 2024 की शुरुआत में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक जोखिमों और संरचनात्मक दुर्बलताओं, दोनों को छिपाने वाले समुत्थानशीलता के आवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया क्योंकि यह पिछली मौद्रिक नीति सख्ती के विलंबित प्रभावों के लिए बचाव करता है⁵। इस संबंध में, अंतर्निहित मूल्य दबाव अभी भी कई देशों में अधिक हैं। प्रतिकूल स्थितियों के और बढ़ने से, ऊर्जा बाजारों को बाधित करने और दुनिया भर में मुद्रास्फीति दबावों के दोहराने का जोखिम है। उच्च उधार लागत और तंग ऋण स्थितियों की दीर्घावधि, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत विपरीत परिस्थितियां पेश करती है जो पहले से ही उच्च स्तर के ऋण और निवेश की कमी से पीड़ित है - जिसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में सार्थक प्रगति करना शामिल है। इस बीच, वैश्विक व्यापार और औद्योगिक उत्पादन के लिए भू-राजनीतिक विखंडन एक बढ़ता जोखिम है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजार की स्थिति के बिगड़ने की प्रत्याशा की गई है। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही से खाद्य कीमतों में मजबूती, हाल ही में विकासशील देशों में खाद्य असुरक्षा का एक महत्वपूर्ण चालक बन रही है, जिससे जीवन-यापन की स्थिति बिगड़ रही है। अनुमानित 238 मिलियन लोगों ने वर्ष 2023 में गरीबी के बढ़ने के साथ-साथ तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया, विशेष रूप से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) में गिरावट का सामना कर रहे निम्न आय वाले देशों में। वैश्विक निवेश की कमजोर प्रवृत्ति के साथ-साथ ओडीए में और कमी से पिछले कई दशकों में कड़ी मेहनत से अर्जित विकास लाभों के पलट जाने का जोखिम होगा।

⁴ फेडरल रिजर्व प्रणाली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य श्री क्रिस्टोफर जे. वालर द्वारा न्यूयॉर्क शहर के इकोनॉमिक क्लब में 27 मार्च 2024 को भाषण।

⁵ विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ, संयुक्त राष्ट्र, जून 2024।

आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से निर्यात के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में पुनरुद्धार एक सकारात्मक पहलू है। देशों के इस समूह के लिए, भुगतान संतुलन की चिंताओं और ऋण स्थिरता जोखिमों से निपटना 2024 की चुनौती होगी। उन्हें पूंजी प्रवाह प्रबंधन, समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों और विनिमय दर प्रबंधन सहित साधनों की एक विस्तृत शृंखला की आवश्यकता होगी, ताकि अटलांटिक के तटों पर प्रकट होने वाले विचलन से प्रतिकूल प्रभाव-विस्तार (स्पिलओवर) जोखिमों को कम किया जा सके। बफर निर्माण को तदनुसार प्राथमिकता प्राप्त हो रही है, खासकर जब उच्च ब्याज दरों और सख्त चलनिधि के बीच राजकोषीय स्थिति संकुचित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संरचनात्मक चुनौती अकेले ऊर्जा संक्रमण के लिए 2050 तक जलवायु वित्त को किसी तरह 150 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें अकेले वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का रूपान्तरण करने के लिए सालाना 5.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह मानता है कि जबकि विश्व अर्थव्यवस्था 2023 में मंदी के सबसे खराब परिदृश्य में आने से बच गई, निम्न विकास की एक दीर्घावधि बरकरार है।

भारत में, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2023-24 में बढ़कर, 2016-17 के बाद से अपनी उच्चतम दर पर पहुंच गई, 2021-22 में कोविड के बाद के पलटाव को छोड़कर, और सभी पूर्वानुमानों को चौंका दिया। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि महामारी के बाद के वर्षों में, एक प्रवृत्ति में तेजी आ रही है, जो घरेलू चालकों द्वारा संचालित भारत के विकास पथ को 2003-19 के औसत 7 प्रतिशत से 2021-24 के औसत 8 प्रतिशत या उससे भी अधिक में स्थानांतरित कर रही है। हाल के संकेतकों से पता चलता है कि निजी खपत मांग के मुख्य चालक के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू कर रही है और ग्रामीण उपभोक्ताओं को शामिल करने के लिए व्यापक आधार प्राप्त कर रही है। तेजी से बढ़ता उपभोक्ता सामान क्षेत्र लोक कल्याण व्यय में तेजी की उम्मीदों पर एक मजबूत बदलाव के लिए कमर कस रहा है। वॉक-इन ग्राहकों में गिरावट की भरपाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा की जा रही है, खासकर हीटवेव की स्थिति में। निवेश ने स्थिर वृद्धि बनाए रखी है; हाल की अवधि में कुछ नरमी निवेश निर्णयों पर भार डालने वाली अस्थायी अनिश्चितता के कारण हो सकती है, लेकिन यह

समय भी बीत जाएगा। निजी निवेश में मजबूत पुनरुद्धार को आने वाले वर्षों में विकास को गति देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बनना होगा, विशेष कर इसलिए क्योंकि लोक वित्त मजबूत हो रहा है। सरकारी खपत व्यय में 2023-24 के अंत में मामूली वृद्धि हुई, जो पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की संभावनाओं और निवेशक भावना के लिए सकारात्मक है।

एक सुखद आश्चर्य में, निवल निर्यात ने जीडीपी, विशेष रूप से उच्च स्तरीय विनिर्माण में अपने योगदान में सुधार किया है। भारत ने निर्यात-संबद्ध योजनाओं द्वारा प्रोत्साहन-प्राप्त शुद्ध पिछड़ी वैश्विक मूल्य शृंखला (जीवीसी) भागीदारी में वृद्धि के माध्यम से तैयार माल के निर्यात में आगे बढ़ना और संलग्न होना शुरू कर दिया है। सेवा क्षेत्र में भी एक संरचनात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। सेवाओं में जीवीसी की भागीदारी ने कम मूल्य वर्धित व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं से उच्च मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे कि वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक धीरे-धीरे परिपक्वता दिखाई है, जो लागत-बचत संस्थाओं से नवोन्मेष और अत्यधिक-मूल्य वाली गतिविधियों के लिए हब तक विकसित हुए हैं और टियर-II शहरों में फैल रहे हैं। सेवाओं के निर्यात और कुशल कार्यबल का लाभ लेने पर ध्यान केंद्रित होने की तीव्र संभावना है। भारत का पर्यटन उद्योग देश में पर्यटन की सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। भारत में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पर्यटन और यात्रा क्षेत्र है। भारत को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाकर वर्ष 2047 के लिए पर्यटन के माध्यम से जीडीपी में यूएस \$1 ट्रिलियन जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उत्पादन के स्तर पर, विनिर्माण ने सकल योजित मूल्य (जीवीए) में विस्तार का नेतृत्व किया है, जिसमें निर्माण में वृद्धि बनी हुई है। दोनों के लिए, निकट अवधि की संभावनाएं उज्ज्वल दिखती हैं। वास्तव में निर्माण के मामले में, अनुषंगी और टियर-II शहरों में भारत का वाणिज्यिक भूसंपदा परिदृश्य सड़क नेटवर्क और मेट्रो कनेक्टिविटी, रणनीतिक शहरी नियोजन और अपेक्षाकृत कम निर्वाह-व्यय के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से प्रेरित एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सेवाओं ने महामारी-पूर्व की प्रवृत्ति दरों पर विस्तार बनाए रखा, तथा

इसमें वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाओं ने नेतृत्व किया। हालांकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में निराशा की स्थिति बनी रही, लेकिन 2024-25 में बेहतर प्रदर्शन के बारे में काफी आशावाद है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सही पूर्वानुमान लगाया – दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में अपने सामान्य आगमन से दो दिन पहले आ गया। मानसून की बारिश का समय पर आगमन, खरीफ फसलों की बुवाई और जलाशयों की पुनःपूर्ति के लिए अच्छा संकेत है, जिससे फसल वर्ष 2024-25 (जुलाई-जून) के लिए 340 मिलियन टन खाद्यान्न का लक्ष्य प्राप्त करने योग्य प्रतीत होता है। कम वर्षा संबंधी अल नीनो की स्थिति के कारण, मानसून की शुरुआत के दौरान ईएनएसओ के तटस्थ होने की संभावना है। जैसा कि जलवायु मॉडल पूर्वानुमानों द्वारा भविष्यवाणी की गई है, वर्तमान में प्रबल तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुवीय (आईओडी) की स्थिति मानसून के दौरान सकारात्मक हो जाएगी और प्रचुर वर्षा लाएगी।

यह मानसून की शुरुआत से पहले देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में व्याप्त गंभीर गर्मी की लहर के प्रभावों को भी कम करेगा, जिसमें तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक और उत्तरी क्षेत्र में उससे भी अधिक ऊपर तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक गर्मी लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई है। लू के चलने (हीटवेव) से श्रम उत्पादकता के लिए भारत पर विशेष रूप से खतरा मँडराता है, क्योंकि वर्ष के इस समय इसके कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि, निर्माण और खनन जैसे बाहरी काम में लगा हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान में प्रत्येक डिग्री की वृद्धि, श्रम उत्पादकता को 2-4 प्रतिशत तक कम कर देती है। ये प्रभाव तटीय प्रायद्वीप की तुलना में देश के उत्तरी भाग में अधिक स्पष्ट हैं। भारत बहुत गर्मी पड़ने वाले दिनों (ग्रीष्म-काल) में अपनी भौतिक श्रम आपूर्ति का लगभग एक चौथाई गंवा देता है। उत्पादन प्रभावों में जोड़ने पर, इसका परिणामी प्रभाव मुद्रास्फीति में तथा निर्माण और रसद के लिए निवेश में दिखाई देता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रति समुत्थानशीलता को बढ़ावा देने के संदर्भ में, भारत द्वारा हासिल की गई हालिया उपलब्धि उल्लेखनीय है – इसने 2024 की पहली तिमाही में 10 गीगा वाट से अधिक सौर क्षमता को जोड़ा, जो किसी भी तिमाही में अब तक

के सबसे अधिक संस्थापन को चिह्नित करता है। यह वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) लगभग 400 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2024 के लिये बड़े पैमाने की पर्याप्त प्रक्रियाधीन परियोजनाएं हैं, जो भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन सौर बाजारों में शामिल करती हैं, जिसमें सुव्यवस्थित नीलामी और आकर्षक टैरिफ इस अभियान को पुनर्जीवित करते हैं। इन घटनाक्रमों के साथ, तेजी से भूमि अधिग्रहण के लिए संचारण इंफ्रास्ट्रक्चर और तंत्र को स्थापित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो जाता है। भारत के पास 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा मूल्य शृंखला में कुल 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के पर्याप्त अवसर हैं, जिसमें नवीकरणीय, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव शामिल हैं।

जैसा कि खंड III में चर्चा की गई है, आर्थिक गतिविधि का एक तात्कालिक पूर्वानुमान (नाउकास्ट) यानी, अधिक वर्तमान उच्च आवृत्ति संकेतकों के आधार पर, सुझाव देता है कि 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि, मोटे तौर पर पिछली तिमाही में हासिल की गई गति को बनाए रख रही है। हालांकि, महामारी के बाद से जीडीपी के गठन में एक संरचनात्मक विराम है। पहली तिमाही की जीडीपी में महामारी की शुरुआत के बाद से अन्य तिमाहियों के सापेक्ष गति का कुछ नुकसान हुआ है। इसलिए, 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष, जब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) अगस्त के अंत में अपना अनुमान जारी करेगा, तो वास्तविक उत्पादन मात्रा की गति में कुछ कमी की प्रत्याशा की जा सकती है। मई 2024 रीडिंग में हेडलाइन मुद्रास्फीति की गिरावट में कमी वर्ष 2024-25 में जीडीपी के पथ के लिए एक आशा की किरण है। गिरावट का लगातार पांचवां महीना, भले ही अनैच्छिक हो, मूल्य/लागत में कटौती का लाभ उठाने के लिए कुल मांग को अवसर देता है। यह तथ्य कि जारी अवस्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के मुख्य घटक की कमी से प्रेरित की जा रही है, मौद्रिक नीति के रुख को प्रमाणित करता है। जब तक खाद्य मूल्य दबाव बना रहता है, तब तक मुद्रास्फीति के लिए अपने लक्ष्य के साथ संरेखित करने का लक्ष्य प्रगति पर है।

इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। घरेलू समष्टि आर्थिक










स्थितियों का आकलन खंड III में निर्धारित किया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को समाहित करता है, जबकि अंतिम खंड में समापन टिप्पणियां दी गई हैं।

II. वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने समुत्थानशीलता प्रदर्शित की, जो कि कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति रुख की ओर अग्रसर केंद्रीय बैंकों की बढ़ती संख्या में परिलक्षित होता है। अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावनाओं (जीईपी) में, विश्व बैंक ने 2024 में वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान को 20 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 3.1 प्रतिशत पर संशोधित कर दिया, जो व्यापार और निवेश के विस्तार को दर्शाता है (सारणी II.1)। वर्ष 2024 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में वृद्धि 1.5 प्रतिशत पूर्वानुमानित है, जबकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के 4.0 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। 2025 में वैश्विक वृद्धि के 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जैसे ही मुद्रास्फीति ने निरंतर कमी के संकेत प्रदर्शित करने शुरू किए, 2024 की पहली तिमाही में यूके और यूरो क्षेत्र सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि धनात्मक हो गई। नवीनतम उच्च आवृत्ति डेटा के साथ संवर्धित हमारा मॉडल-आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान (नाउकास्ट), 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान एक धनात्मक लेकिन सामान्य होती वैश्विक वृद्धि की गति की ओर इंगित करता है (चार्ट II.1)।

सारणी II.1: जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान - चुनिंदा आई और ईएमई

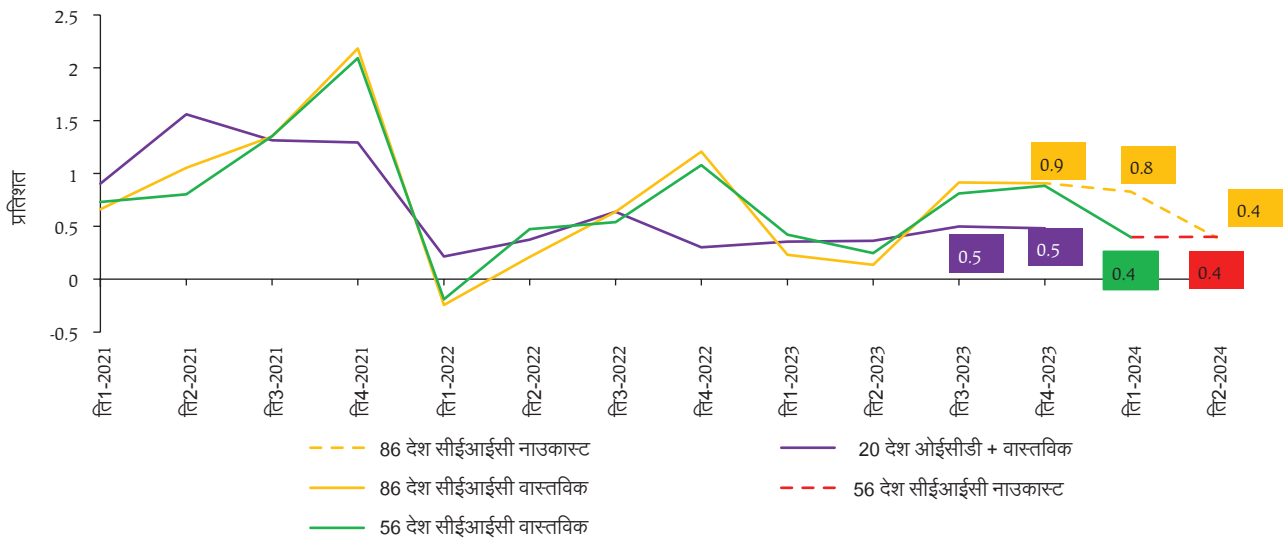
(प्रतिशत)

पूर्वानुमान लगाने का माह →	2024		2025	
	जनवरी 2024	जून 2024	जनवरी 2024	जून 2024
भूभाग/ देश ↓				
 विश्व*	2.9	3.1	3.1	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (ईई)				
 यूएस	1.6	2.5	1.7	1.8
 यूरो क्षेत्र	0.7	0.7	1.6	1.4
 जापान	0.9	0.7	0.8	1.0
उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)				
 ब्राजील	1.5	2.0	2.2	2.2
 रूस	1.3	2.9	0.9	1.4
 भारत#	6.4	6.6	6.5	6.7
 चीन	4.5	4.8	4.3	4.1
 दक्षिण अफ्रीका	1.3	1.2	1.5	1.3

टिप्पणी : *: पीपीपी भारिता #: डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।

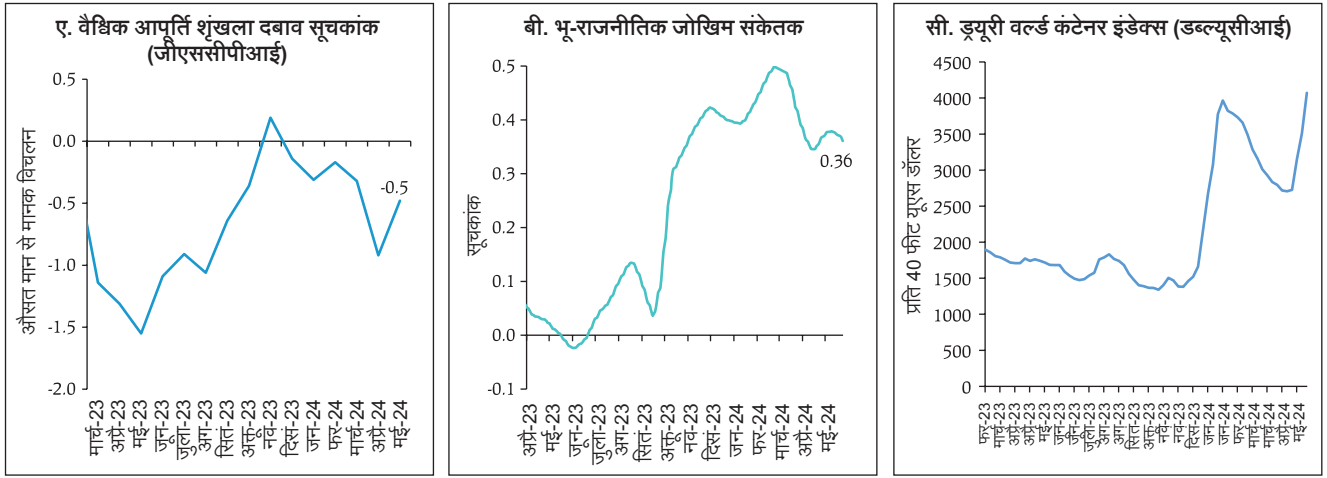
स्रोत : विश्व बैंक

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी वृद्धि तात्कालिक अनुमान (नाउकास्ट) (ति-द-ति)



स्रोत : सीईआईसी; ओईसीडी; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट II.2: वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबावों और भू-राजनीतिक जोखिमों में रुझान



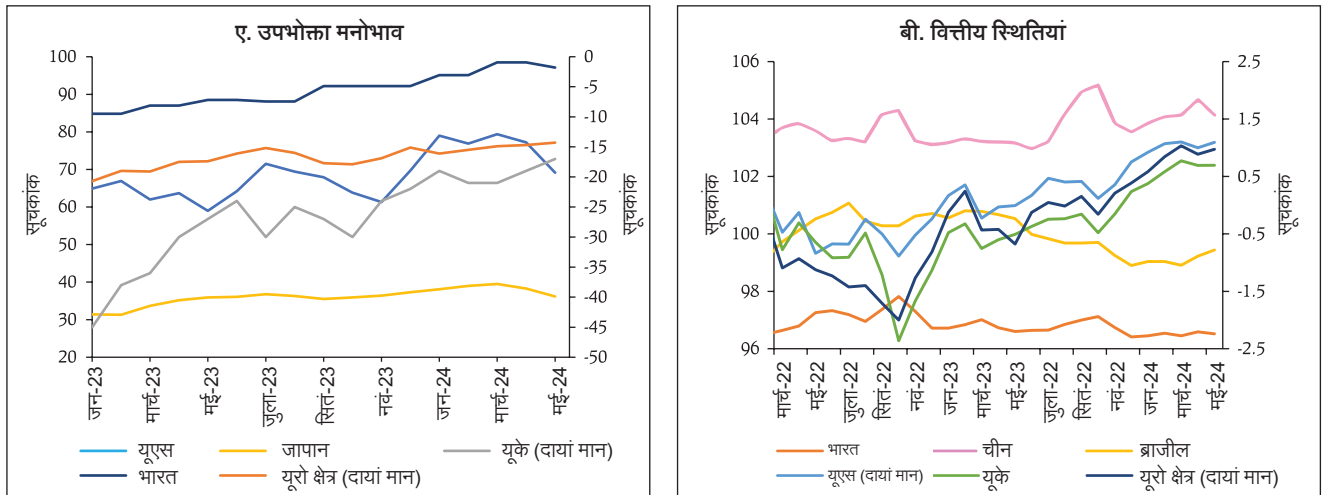
टिप्पणियाँ : 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।
 2. डब्ल्यूसीआई ने प्रमुख पूर्व पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए ड्यूरी द्वारा साप्ताहिक का मूल्यांकन किया, जो वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल डुलाई दरों को रिपोर्ट करता है। मात्रा के हिसाब से 'समग्र' 8 पोत-परिवहन (शिपिंग) मार्गों के भारत आंसते को दर्शाता है और प्रति 40-फीट कंटेनर में यूएसडी में रिपोर्ट किया जाता है।
स्रोत : फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, मई 2024; और ब्लूमबर्ग।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) ने लगातार दो महीनों तक गिरावट के बाद मई 2024 में वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.2ए)। भू-राजनीतिक तनाव में थोड़ी कमी आयी, हालांकि भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक एक साल पहले दर्ज किए गए अपने स्तर से काफी अधिक रहा (चार्ट II.2बी)। मई 2024 के उत्तरार्ध में, लॉजिस्टिक्स व्यवधानों के कारण पोत-परिवहन (शिपिंग) लागत में वृद्धि हुई, जिससे आयात लागत के लिए सकारात्मक

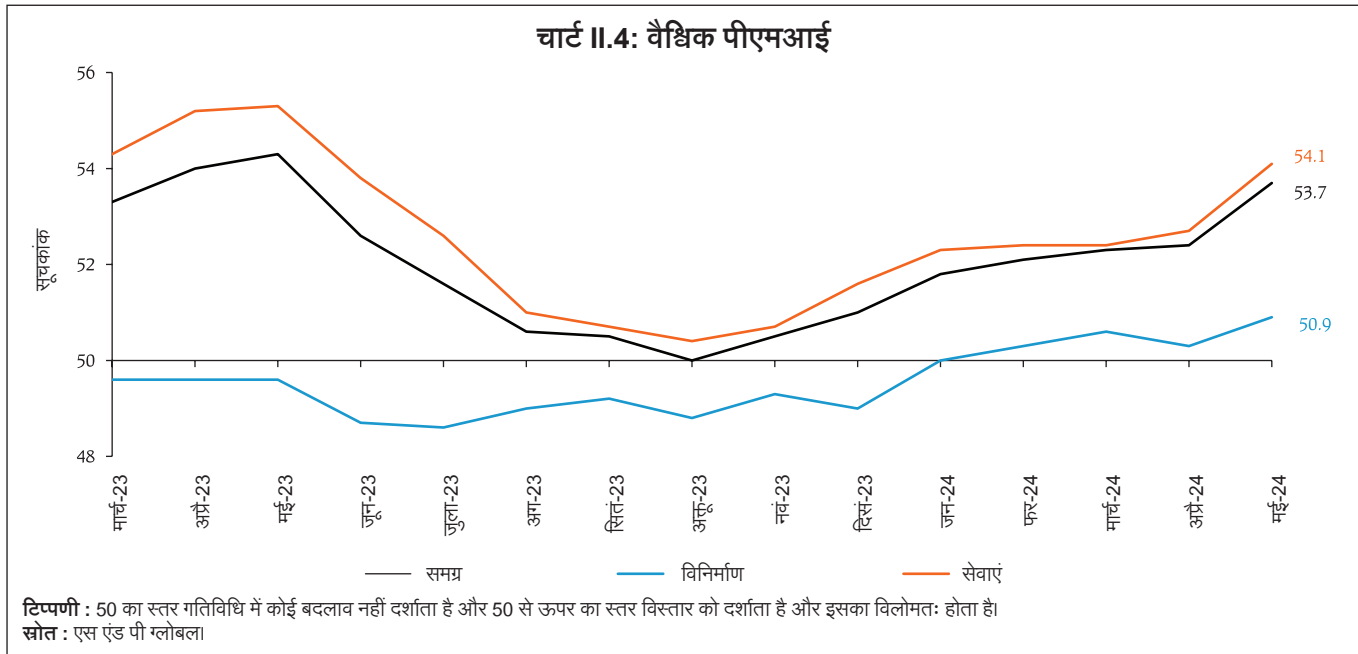
परिणामों की संभावना देखने को मिली (चार्ट II.2सी)।

उपभोक्ता भावनाएं निराशावादी बनीं रहीं तथा बेरोजगारी दर में वृद्धि, धीमी आय वृद्धि, उच्च ब्याज दरों और अभी भी अनिश्चित मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के कारण अमेरिका में पांच महीनों में अपने निम्नतम स्तर पर गिर गईं (चार्ट II.3ए)। ब्राजील और भारत को छोड़कर, मई 2024 के दौरान उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिति कठोर बनी रही (चार्ट II.3बी)।

चार्ट II.3: उपभोक्ता मनोभाव और वित्तीय स्थितियां



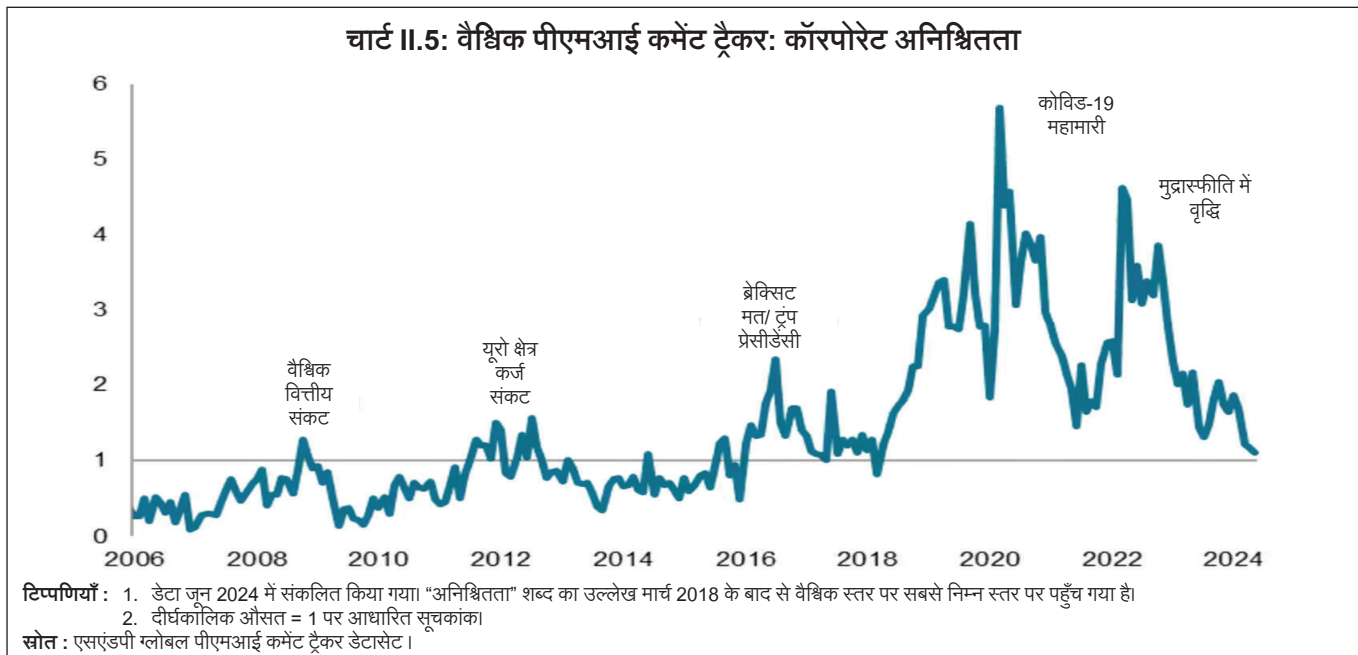
टिप्पणियाँ : 1. जापान: 50 से अधिक का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
 2. यूरो क्षेत्र और यूके: (-)100 अत्यधिक विश्वास की कमी, 0 तटस्थता और 100 अत्यधिक विश्वास को दर्शाता है।
 3. भारत और अमेरिका: मान जितना अधिक होगा, उपभोक्ता का विश्वास उतना अधिक होगा।
स्रोत : ब्लूमबर्ग।

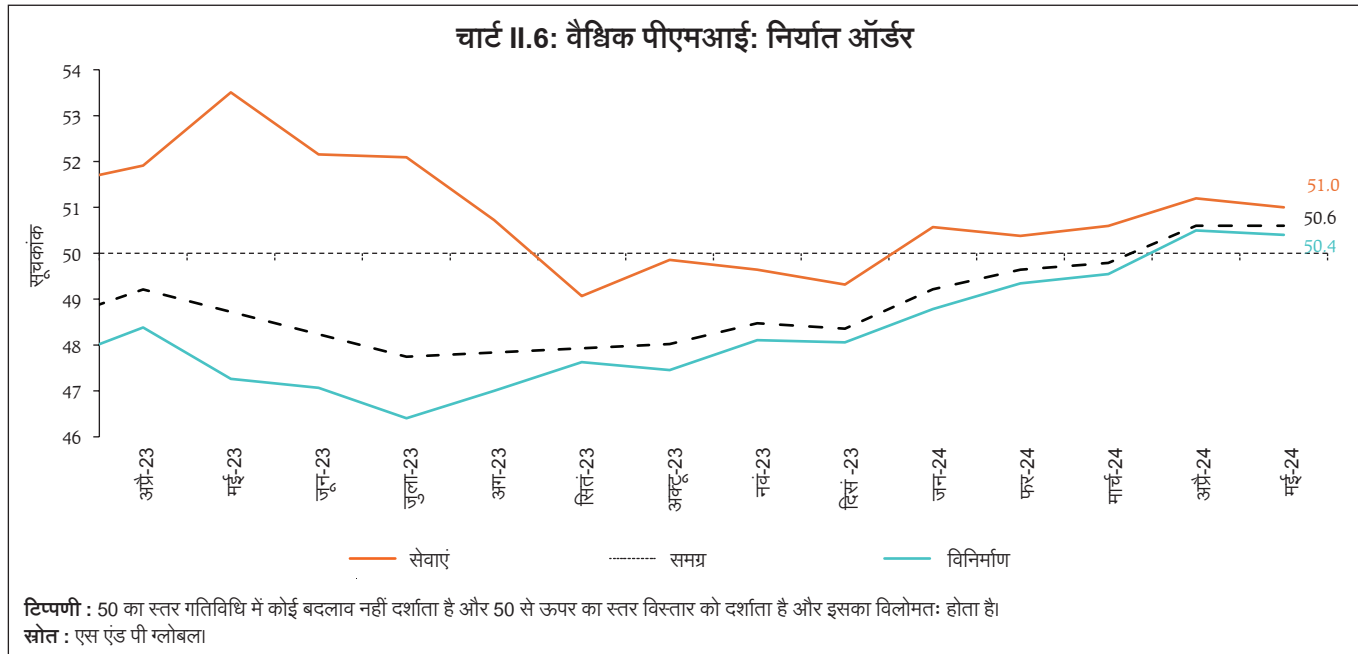


वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स-पीएमआई) में लगातार सातवें महीने अनुक्रमिक वृद्धि देखी गई, जो मई 2024 में 12 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई मई में 22 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो लगातार चौथे महीने तटस्थ चिह्न से ऊपर रही, जिसका कारण था - उत्पादन और नए आदेशों का तीव्र गति से बढ़ना (चार्ट II.4)। सेवा पीएमआई अपने विनिर्माण

समकक्ष से ऊपर रहा और मई में 12 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। कारोबारी स्थितियों में समग्र सुधार मार्च 2018 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर कॉरपोरेट द्वारा सामना की जा रही अनिश्चितता ट्रैकर में गिरावट को भी दर्शाता है (चार्ट II.5)।

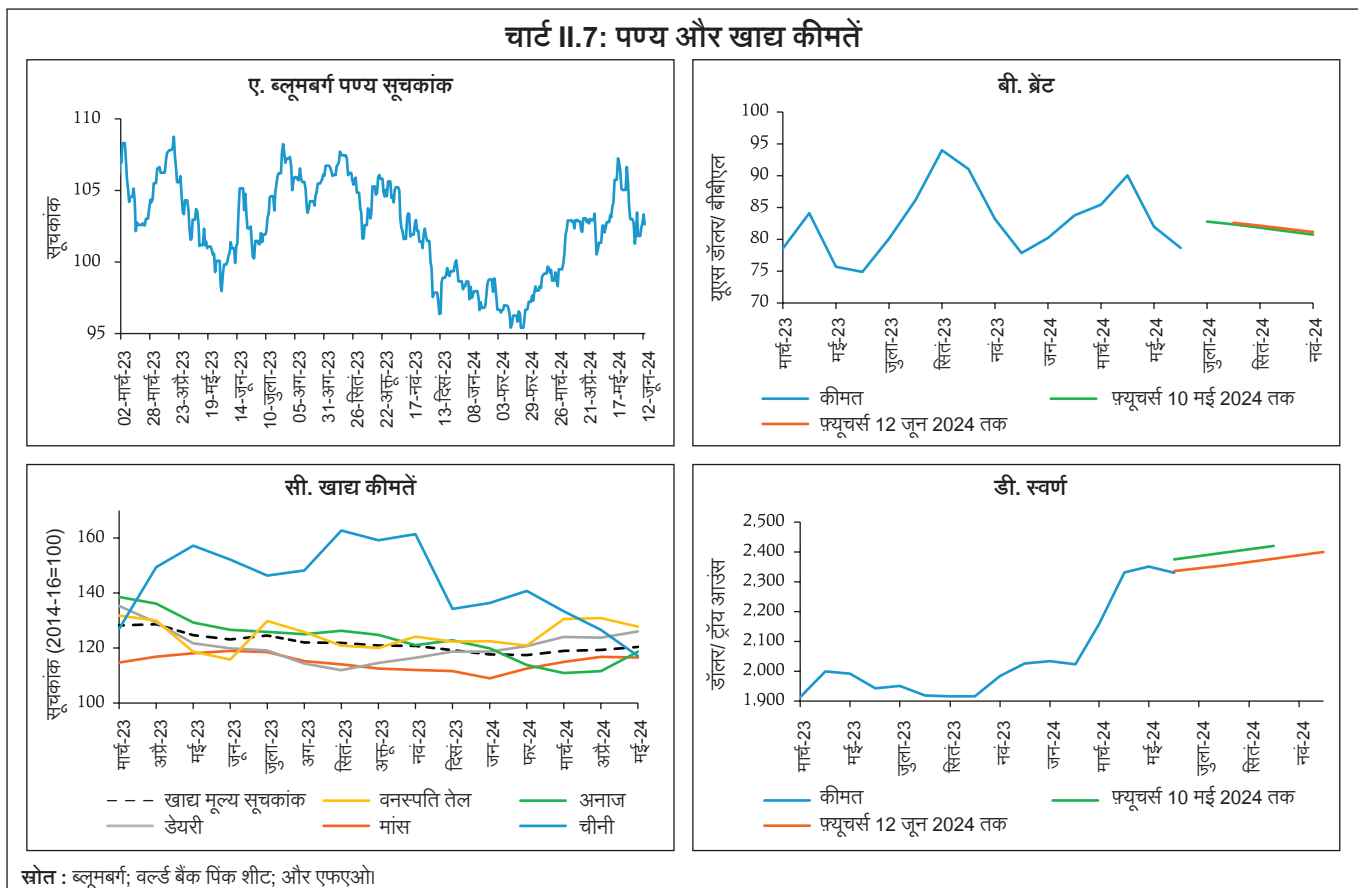
निर्यात आदेशों के लिए समग्र पीएमआई मई 2024 में विस्तारवादी क्षेत्र में रहा, हालांकि विनिर्माण और सेवा निर्यात, दोनों आदेशों में अनुक्रमिक आधार पर थोड़ी कमी आई (चार्ट II.6)।





मई और जून की शुरुआत में वैश्विक पण्य कीमतें अस्थिर रहीं। ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स ने 1-20 मई के दौरान 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, लेकिन मई के अंत और जून की

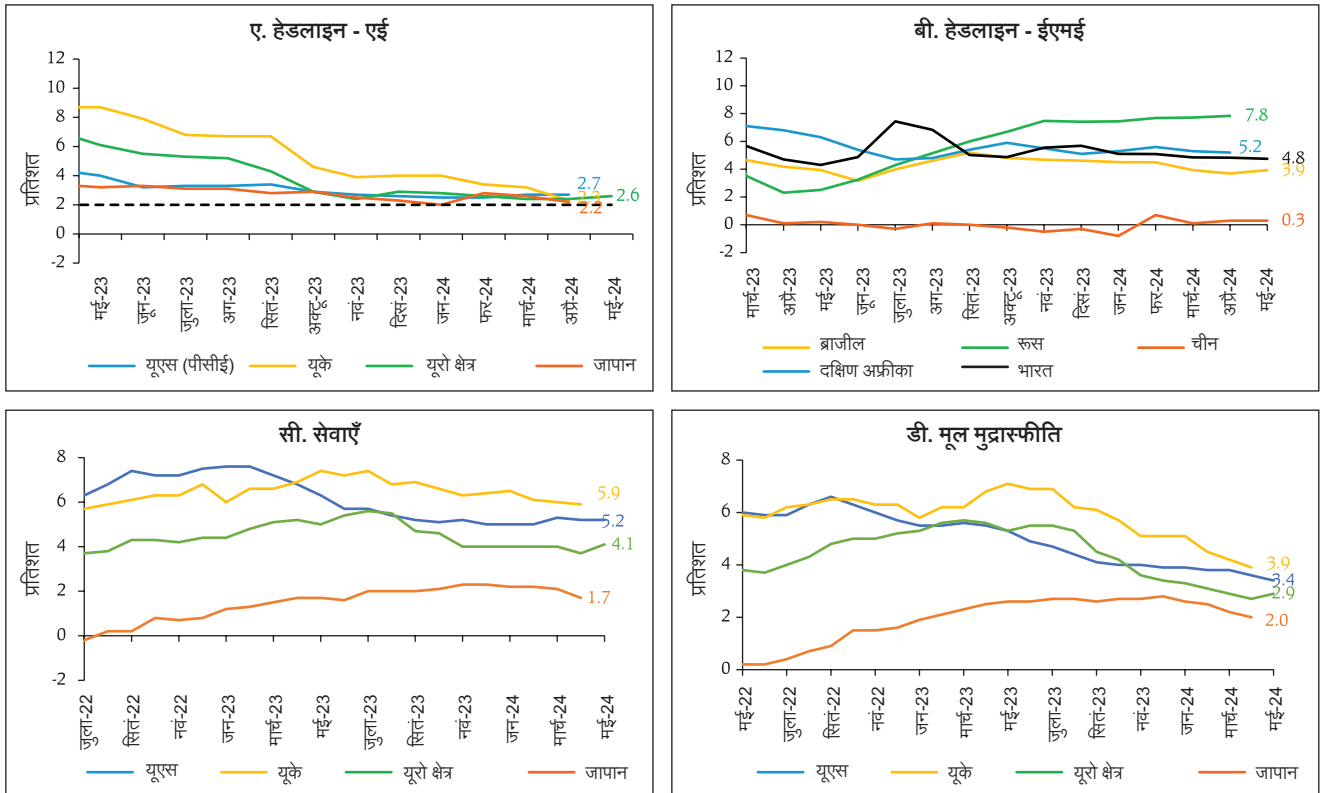
शुरुआत में इसके अधिकांश लाभ में कमी आई (चार्ट II.7ए)। सबसे बड़ी गिरावट तेल की कीमतों में देखने को मिली, मई में ब्रेंट ऑयल की कीमतों में 8.9 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट



आई थी। ओपेक+ की बैठक के बाद जून की शुरुआत में तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही⁶। ब्रेंट ऑयल की कीमतें 10 जून 2024 को यूएस \$79.6 थीं, जिन्होंने यह दर्शाया कि बाजार ने अक्टूबर से शुरू होने वाली "स्वैच्छक" कटौती को समाप्त करने की कीमत तय कर ली है (चार्ट 11.7बी)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का खाद्य मूल्य सूचकांक मई 2024 में 0.9 प्रतिशत (माह-दर-माह) बढ़ा, जो मुख्य रूप से अनाज की कीमतों में वृद्धि (6.3 प्रतिशत) से प्रेरित था, लेकिन चीनी की कीमतों में गिरावट (-7.5 प्रतिशत) से आंशिक रूप से कमी आ गई। हालांकि, सूचकांक एक वर्ष पहले के अपने तत्संबंधी मूल्य से 3.4 प्रतिशत नीचे था, जिसका कारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर चीनी और अनाज की कीमतों में गिरावट थी (चार्ट 11.7सी)। अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट से मदद मिली, स्वर्ण की कीमतें मई में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं, लेकिन बाद में सामान्य हो गईं (चार्ट 11.7डी)।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अवस्फीति जारी है, यद्यपि उसकी गति शिथिल है। विश्व बैंक जीईपी ने वैश्विक मुद्रास्फीति के 2024 में 3.5 प्रतिशत और 2025 में 2.9 प्रतिशत तक कम होने का पूर्वानुमान लगाया। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल में 3.4 प्रतिशत से मई में घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई, जबकि हेडलाइन निजी खपत व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति अप्रैल में 2.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 2.4 प्रतिशत थी। जापान में मुद्रास्फीति (ताजे भोजन को छोड़कर सीपीआई) अप्रैल में 2.2 प्रतिशत तक कम हो गई, जबकि ब्रिटेन में इसमें अप्रैल माह में 2.3 प्रतिशत तक की गिरावट हुई (चार्ट 11.8ए)। ईएमई के मध्य, ब्राजील ने मई में मुद्रास्फीति में वृद्धि का अनुभव किया, जबकि यह चीन में स्थिर रही। अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका में मुद्रास्फीति कम हुई, जबकि रूस में मुद्रास्फीति

चार्ट 11.8: मुद्रास्फीति: विकसित अर्थव्यवस्थाएं (ईई) और उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)



स्रोत : ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

⁶ ओपेक+ ने जून 2024 में अपनी नवीनतम बैठक में तेल उत्पादन में भारी कटौती को 2025 के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की, ताकि कमजोर मांग और दुनिया के अन्य हिस्सों से आपूर्ति में वृद्धि के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही कीमतों को सहारा दिया जा सके। हालांकि, आठ सदस्य अक्टूबर 2024 से कुछ "स्वैच्छक" कटौतियां करने पर सहमत हुए।

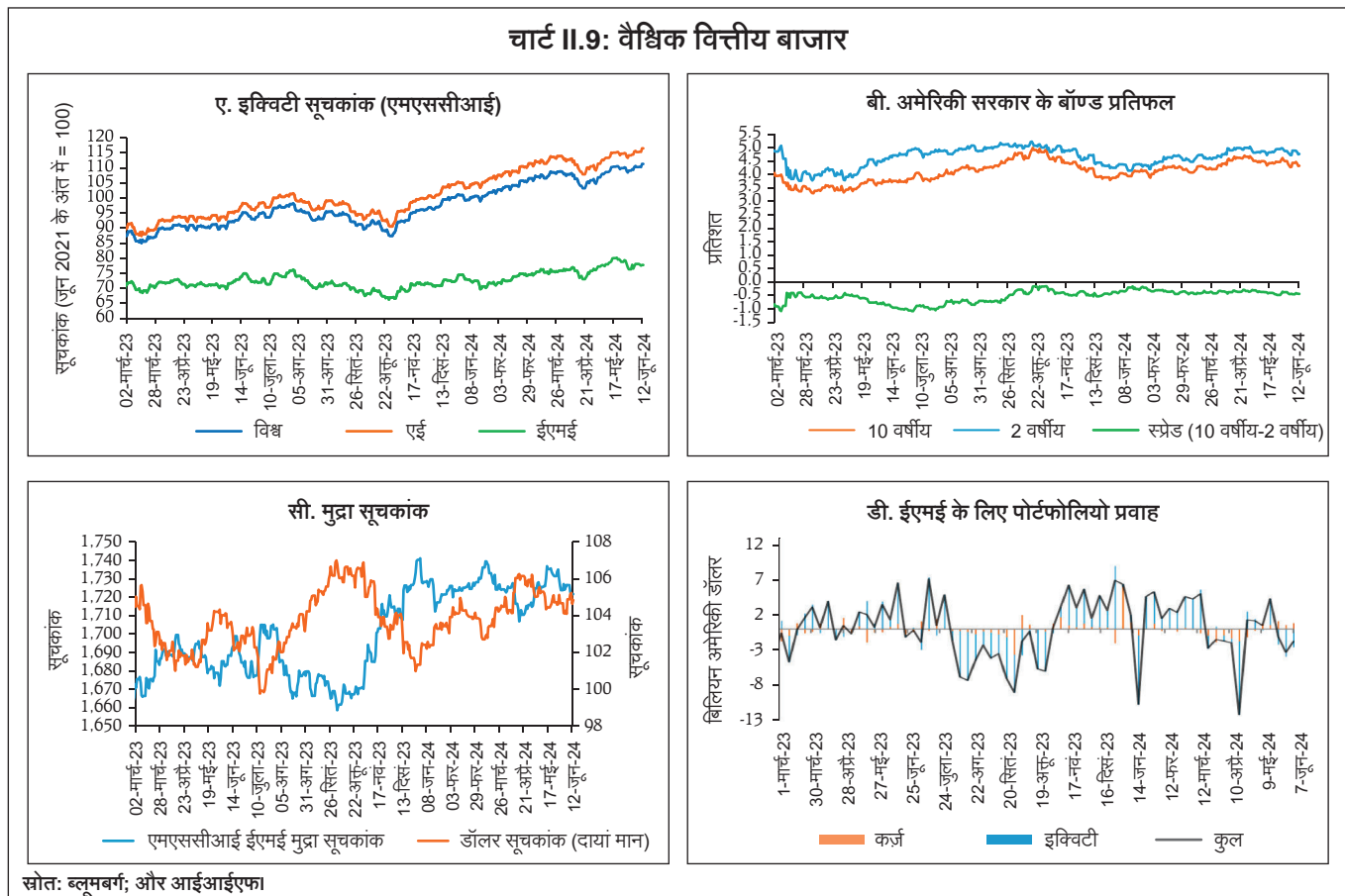
में बढ़ोतरी हुई (चार्ट 11.8बी)। मूल और सेवाओं की मुद्रास्फीति, जापान को छोड़कर प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में हेडलाइन मुद्रास्फीति से अधिक रही (चार्ट 11.8सी और 11.8डी)।

वैश्विक इक्विटी बाजारों में मई में तेजी आई, तथा मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व सूचकांक में 3.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो भू-राजनीतिक तनाव में कुछ कमी तथा अन्य ईई के बाद अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की आशा के बीच हुआ। ऐसा भू-राजनीतिक तनाव में कुछ हद तक कमी और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बाद अमेरिका में आसन्न दर में कटौती पर आशावाद के बीच हुआ (चार्ट 11.9ए)। जून के आरंभ में अमेरिका में अपेक्षा से कम मुद्रास्फीति के आंकड़ों तथा अमेरिकी फेडरल नीति घोषणा के कारण बाजार में बढ़त जारी रही। हालांकि, ईएमई में इक्विटी बाजारों में भौगोलिक क्षेत्रों में राजनीतिक घटनाक्रमों पर मई के अंतिम सप्ताह में सुधार देखा गया, लेकिन जून की शुरुआत में उनमें आंशिक रूप से सुधार हुआ। अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) प्रतिफल

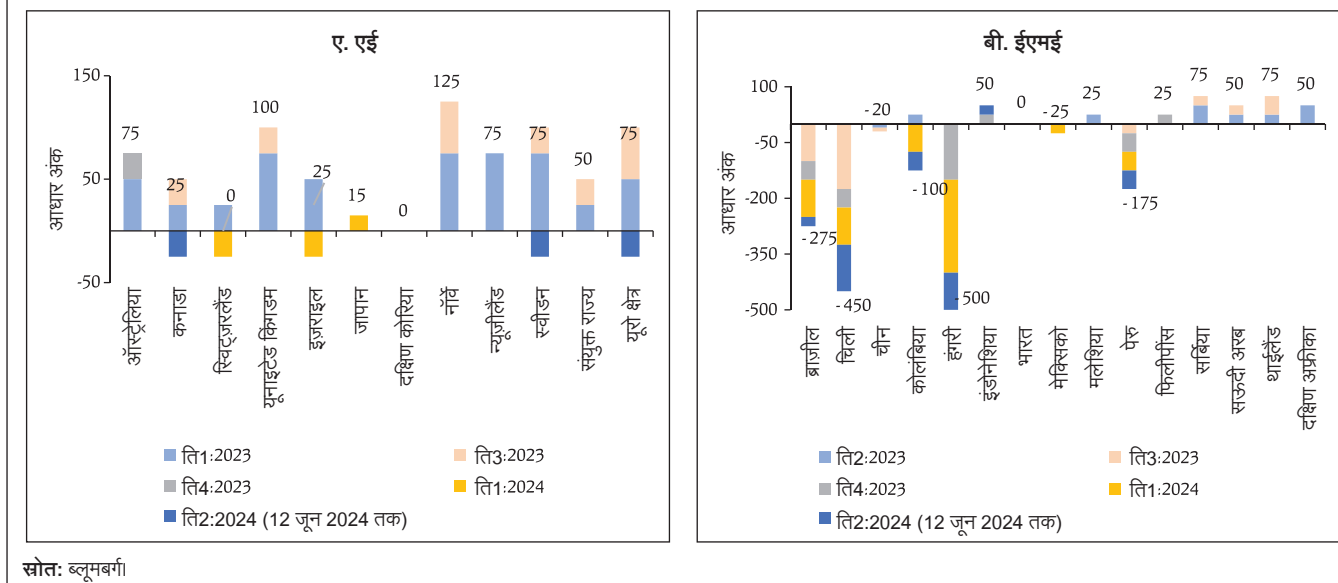
- 10-वर्षीय और 2-वर्षीय - दोनों मई में क्रमशः 18 आधार अंक और 16 आधार अंक कम हो गए, जो वित्तीय बाजारों द्वारा अपेक्षित आधार पर पीसीई मुद्रास्फीति के आंकड़ों के जारी होने के कारण हुआ (चार्ट 11.9बी)। हालांकि, जून में प्राप्त होने वाले आंकड़ों के अनुसार प्रतिफल में अस्थिरता देखी गई। मुद्रा बाजारों में, फेडरल रिजर्व द्वारा दर में कटौती पर बढ़े हुए दांव के कारण, मई में गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनुमान से अधिक मजबूत होने के बाद अमेरिकी डॉलर में थोड़ी गिरावट आई। ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक में मई के उत्तरार्ध में थोड़ी गिरावट देखी गई, जो प्रमुखतः इक्विटी खंड में ईएमई से पूंजी बहिर्वाह में वृद्धि के कारण बढ़ गई (चार्ट 11.9सी और 11.9डी)।

चुनिंदा ईई और ईएमई ने अपनी नवीनतम बैठकों में अपनी बेंचमार्क दरों को कम कर दिया क्योंकि एक धारणीय अवस्फीति के संकेत उभरने लगे। इसीबी की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) ने अपनी जून बैठक में तीन प्रमुख ब्याज दरों में से प्रत्येक में 25 आधार अंक कम करने का निर्णय लिया क्योंकि सितंबर 2023

चार्ट 11.9: वैश्विक वित्तीय बाजार



चार्ट II.10: नीतिगत दरों में परिवर्तन



से मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। कनाडा ने मुद्रास्फीति में गिरावट होने से वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जून में अपनी नीति दर में 25 बीपीएस की कटौती की, यह दोहराते हुए कि मौद्रिक नीति को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। चेक गणराज्य और स्वीडन ने भी मई की अपनी बैठकों में अपनी नीति दरों में क्रमशः 50 और 25 आधार अंकों की कमी की (चार्ट II.10ए)। वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जून में अपनी बैठक में संघीय निधि (फेडरल फंड) की ब्याज दर को 5.25-5.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा। ईएमई केंद्रीय बैंकों के बीच, चिली और हंगरी ने अपनी मई की बैठकों में बेंचमार्क दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की, जबकि ब्राजील और पेरू ने अपनी मई की बैठकों में नीति दरों में 25 आधार अंकों की कमी लायी (चार्ट II.10बी)। अधिकांश अन्य केंद्रीय बैंकों ने अवस्फीति के अंतिम पड़ाव में अपने प्रतिबंधात्मक नीतिगत रुख को बनाए रखा।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने विपरीत भू-राजनीतिक परिस्थितियों और आपूर्ति शृंखला दबावों के निर्माण के कारण एक मजबूत समष्टि-आर्थिक निष्पादन किया (चार्ट III.1ए)। शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण का मई 2024 का दौर स्थायी आशावाद की ओर इंगित करता है, भले ही वर्तमान स्थिति पर धारणाओं में अनुक्रमिक कमी दर्ज की गई (चार्ट III.1बी)। आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) के अनुसार, 2024-25 की पहली तिमाही में

जीडीपी वृद्धि के लगभग 7.4 प्रतिशत पर रहने की संभावना है (चार्ट III.1सी और चार्ट III.1डी)।

आंतरिक डॉयनैमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम (डीएसजीई) मॉडल के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि 2024-25 के दौरान जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक पहुंच सकती है और हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक कम हो सकती है (सारणी III.1 और चार्ट III.2)⁷

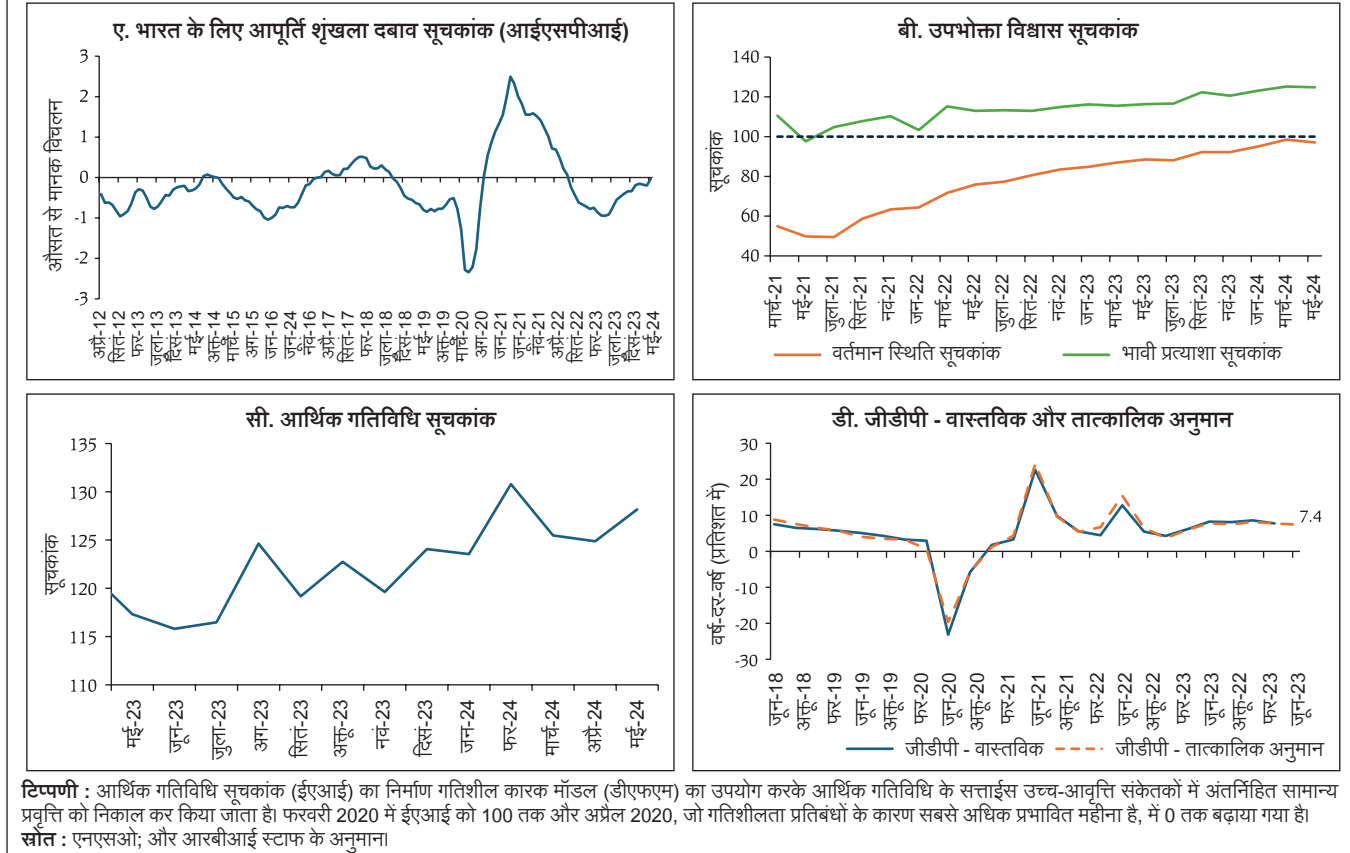
सारणी III.1: आधारभूत (बेसलाइन) पूर्वानुमान

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में)

अवधि	जीडीपी वृद्धि	सीपीआई मुद्रास्फीति
ति2: 2024-25	7.4	4.5
ति3: 2024-25	8.4	4.3
ति4: 2024-25	6.8	4.0
वित्तीय वर्ष 2024-25	7.6	4.4
ति1: 2025-26	6.5	3.9
ति2: 2025-26	6.5	4.0
ति3: 2025-26	6.4	4.0
ति4: 2025-26	6.3	4.1
वित्तीय वर्ष 2025-26	6.4	4.0

⁷ आधारभूत पूर्वानुमानों का अनुमान इस धारणा के तहत लगाया गया है कि 2024-25 और 2025-26 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति - आईएमएफ डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2024 अपडेट के अनुसार होगी; और नीति रेपो दर एवं यूएस फेड निधि दर चालू और अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत पर बनी रहेगी।

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी वृद्धि के तात्कालिक अनुमान (नाउकारस्ट)

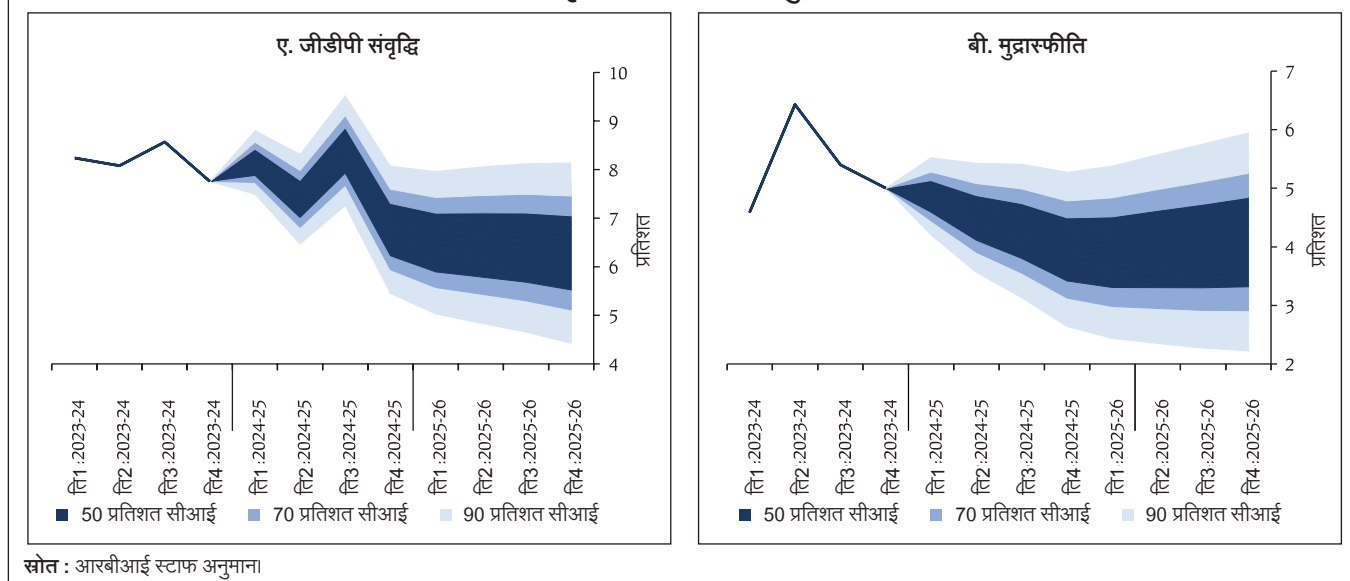


वर्ष 2025-26 के दौरान, जीडीपी के 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का पूर्वानुमान है जबकि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

समग्र मांग

31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों (पीई) के अनुसार, भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद

चार्ट III.2: जीडीपी संवृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति का फैन चार्ट



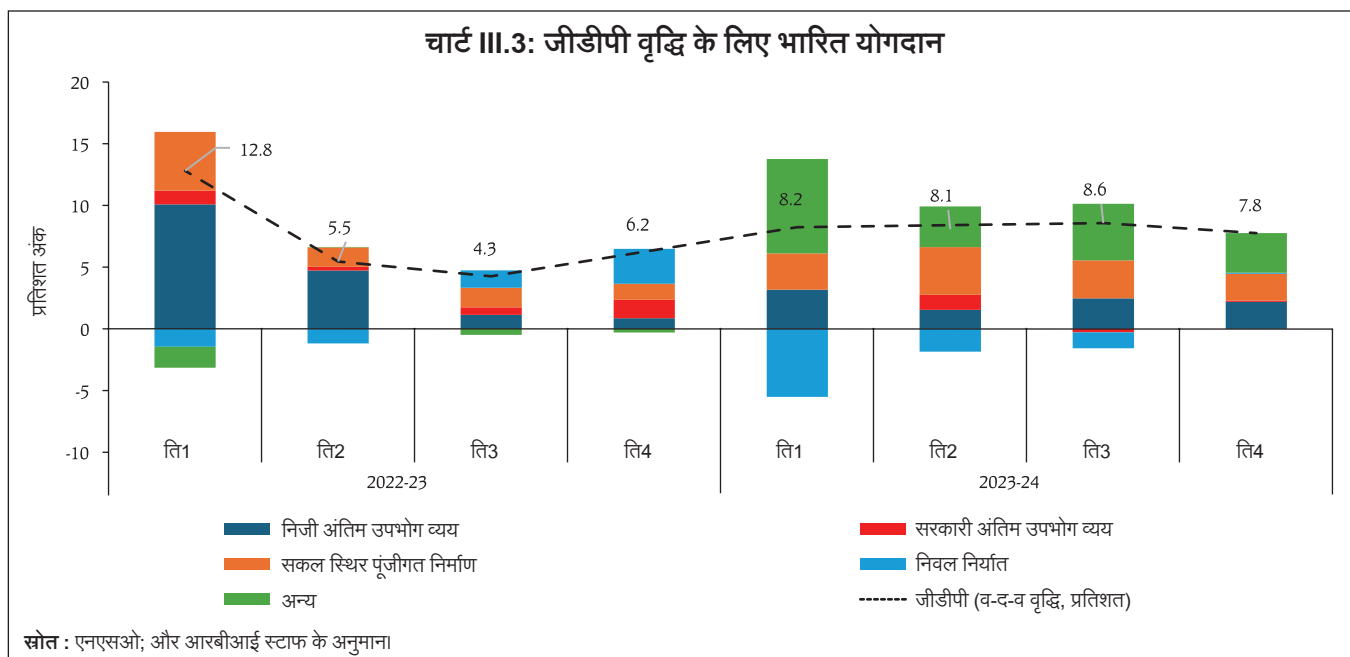
(जीडीपी) ने एक वर्ष पहले 7 प्रतिशत की तुलना में, 2023-24 के लिये 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जीडीपी वृद्धि को दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) से 0.6 प्रतिशत अंक और अधिक पर संशोधित किया गया है। उच्च संशोधित वृद्धि, मुख्य रूप से निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) और निर्यात की वृद्धि में ऊर्ध्वगामी संशोधन के कारण है। तथापि, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) को एसएई की तुलना में पीई में कमी कर संशोधित किया गया है।

त्रैमासिक वृद्धि मार्ग की ओर बढ़ते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.6 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में 7.8 प्रतिशत पर विस्तारित हुई। 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में एसएई में 5.9 प्रतिशत की अंतर्निहित वृद्धि दर की तुलना में, जीडीपी वृद्धि के 190 बीपीएस अधिक होने का अनुमान है (चार्ट III.3)। पीएफसीई की वृद्धि, तीसरी तिमाही में तेजी के बाद 2023-24 की चतुर्थ तिमाही के दौरान 4.0 प्रतिशत पर बनी रही। पिछली तिमाही में संकुचन के बाद जीएफसीई में 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में निर्माण गतिविधि में गिरावट के साथ, स्थिर निवेश वृद्धि पिछली तिमाही के 9.7 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत हो गई। निर्यात और आयात में क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत की जोरदार

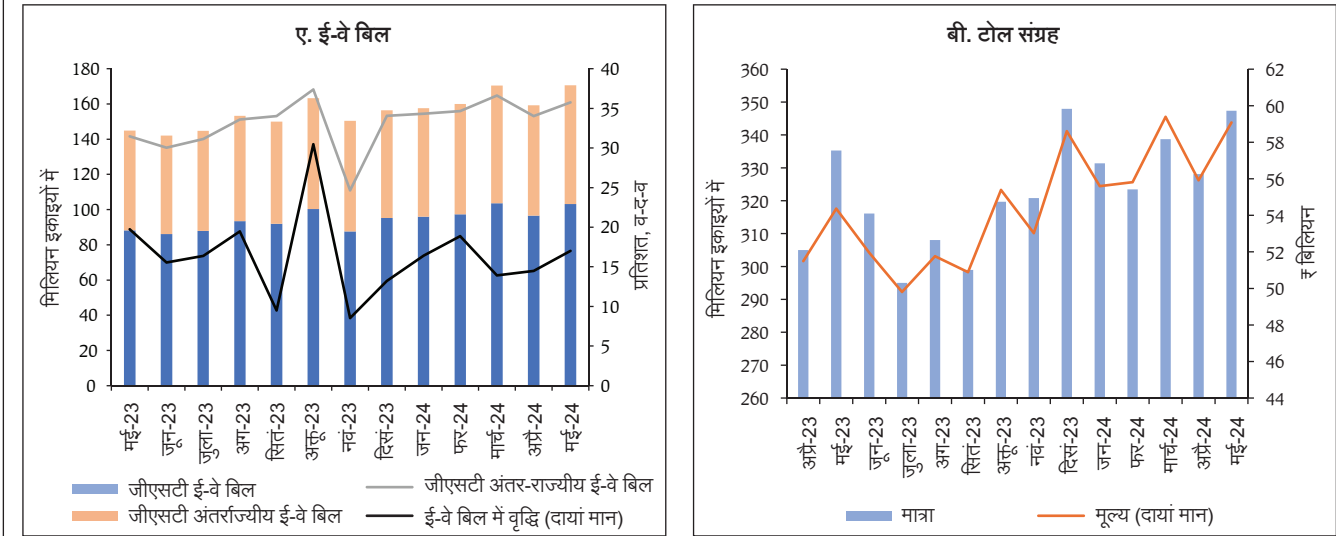
वृद्धि हुई। इससे पिछली तीन तिमाहियों में संकुचन में रहने के बाद, निवल निर्यात ने 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में जीडीपी वृद्धि में धनात्मक योगदान दिया।

उच्च आवृत्ति संकेतक 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान घरेलू मांग की स्थिति में अविरत गति की ओर इंगित करते हैं। मई 2024 में ई-वे बिल में 17 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें अंतर-राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ई-वे, दोनों में क्रमिक वृद्धि हुई (चार्ट III.4ए)। मई 2024 में पथ-कर (टोल) संग्रह में 8.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.4बी)।

मई 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 9.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके लिए यात्री वाहन खंड के साथ-साथ दोपहिया और तिपहिया वाहन उत्तरदायी थे, जबकि प्रवेश स्तर के वाहनों (आधारभूत रूप से कम लागत वाले वाहन) की वृद्धि कमजोर बनी रही (चार्ट III.5ए)। मई 2024 में ट्रैक्टर की घरेलू बिक्री सात महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) के समय पर आगमन एवं खरीफ मौसम की बुवाई की शुरुआत ने किसानों के मनोभाव में उत्साह लाया (चार्ट III.5बी)। मई 2024 में वाहन पंजीकरण में कमी आई, मुख्य रूप से गैर-परिवहन वाहन खंड में क्योंकि अत्यधिक गर्मी ने वॉक-इन और पंजीकरण को कम कर दिया (चार्ट III.5सी)। पेट्रोलियम खपत के अंतर्गत, मुख्य रूप से ट्रकों



चार्ट III.4: ई-वे बिल और टोल संग्रह

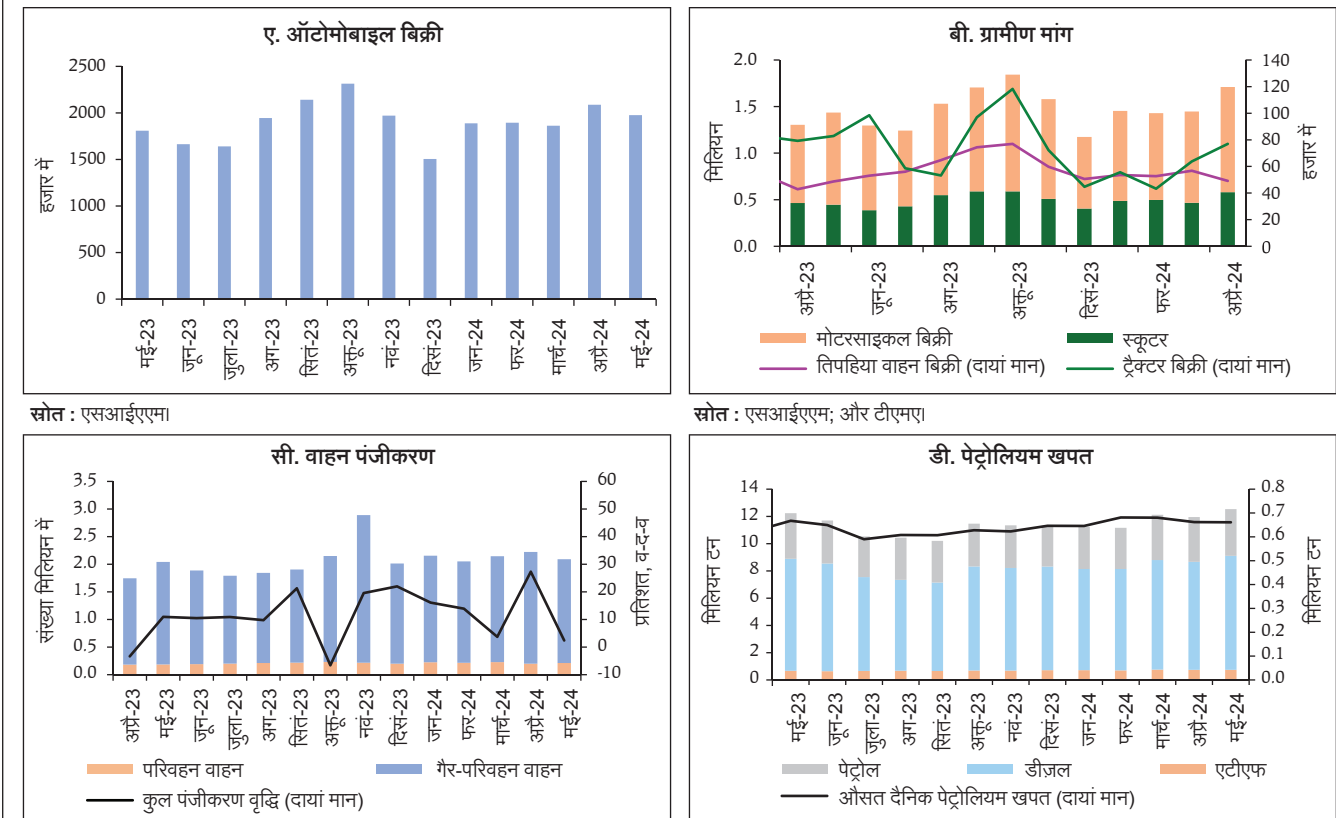


स्रोत: जीएसटीएन; और आरबीआई

सहित वाणिज्यिक वाहनों में उपयोग किए जाने वाले डीजल की बिक्री और मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) ने शृंखला (अप्रैल 1998

की शुरुआत से) में उच्च स्तर दर्ज किया, जो मजबूत परिवहन गतिविधि का संकेत देता है (चार्ट III.5डी)।

चार्ट III.5: ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक



स्रोत: एसआईएएम

स्रोत: एसआईएएम; और टीएमए

स्रोत: एसआईएएम

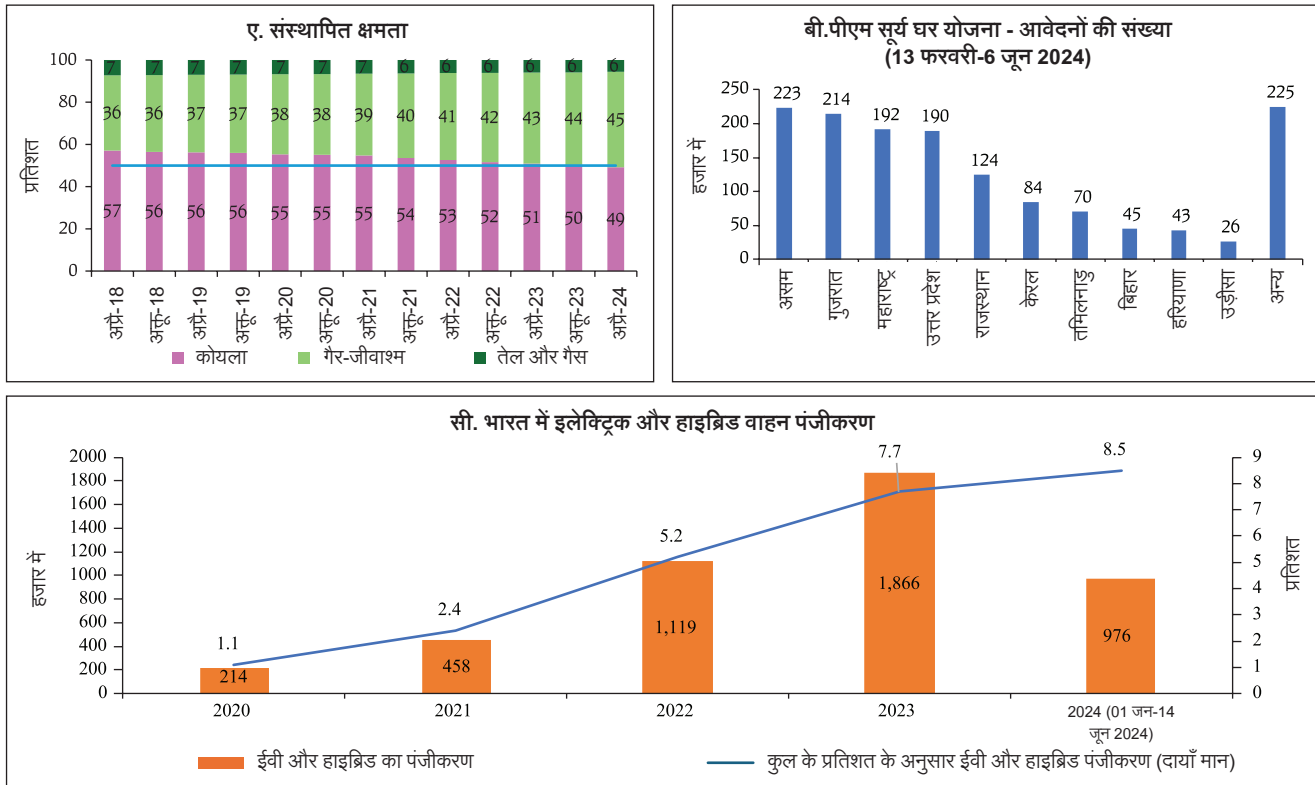
स्रोत: एसआईएएम; और टीएमए

वर्ष 2023-24 में प्रयुक्त कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 71 प्रतिशत है। नवीकरणीय ऊर्जा में इस वृद्धि ने अप्रैल 2024 में कोयले और लिग्नाइट की हिस्सेदारी को भारत की कुल संस्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से नीचे ला लिया (चार्ट III.6ए)। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में हाल की कुछ पहलें आगे चलकर भारत के जलवायु कार्रवाई प्रदर्शन के लिए शुभ संकेत हैं। वर्ष 2023-24 में 47.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बोलियां जारी की गईं, जो पिछले तीन वर्षों में आमतौर पर सालाना जोड़ी जाने वाली राशि का तीन गुना है⁸ छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए 06 जून 2024⁹ तक पीएम सूर्य घर योजना योजना (पीएमएसजीवाई) के तहत लगभग 14.3 लाख आवेदन प्राप्त हुए (चार्ट III.6बी)। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, सरकार ने सालाना 4.12 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निविदाएं आबंटित की हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत की हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 1,500 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की गईं हैं। स्वच्छ परिवहन के लिए सार्वजनिक रुख ने सुदृढ़ गति दिखाई, जैसा कि 2024 (1 जनवरी - 14 जून) में ईवी और हाइब्रिड पंजीकरण में वृद्धि से स्पष्ट है, जो दुपहिया और तिपहिया वाहन खंड द्वारा संचालित है। जून 2024 के अंत तक कुल ईवी पंजीकरण के 1 मिलियन से अधिक होने की संभावना है, जो लगभग 2022 के लिए पूरे वर्ष की संख्या के बराबर है (चार्ट III.6सी)।

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर (यूआर) घटकर 20 महीने के निचले स्तर 7 प्रतिशत पर आ गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम बेरोजगारी दर द्वारा संचालित है (चार्ट III.7ए)। श्रम भागीदारी दर (एलपीआर) में मामूली गिरावट दर्ज की गई,

चार्ट III.6: हरित संक्रमण

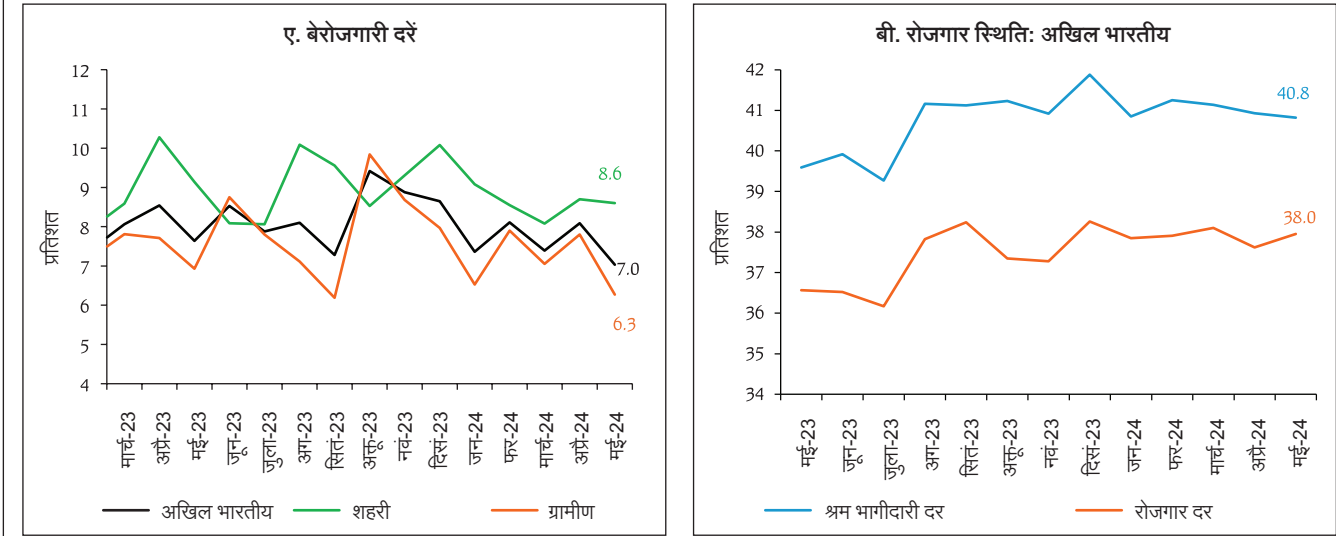


टिप्पणी: गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता में जैव, जल विद्युत, परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा शामिल हैं।
स्रोत: भारत सरकार; नीति आयोग डैशबोर्ड; और 'वाहन' डैशबोर्ड।

⁸ काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वायरनेमेंट एंड वाटर, 2024।

⁹ केंद्र सरकार द्वारा पीएमएसजीवाई को 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट में प्रस्तुत किया गया था और इसके लिए आवेदन 13 फरवरी 2024 से शुरू हुए थे।

चार्ट III.7: श्रम बाजार स्थितियां



स्रोत : सीएमआईई।

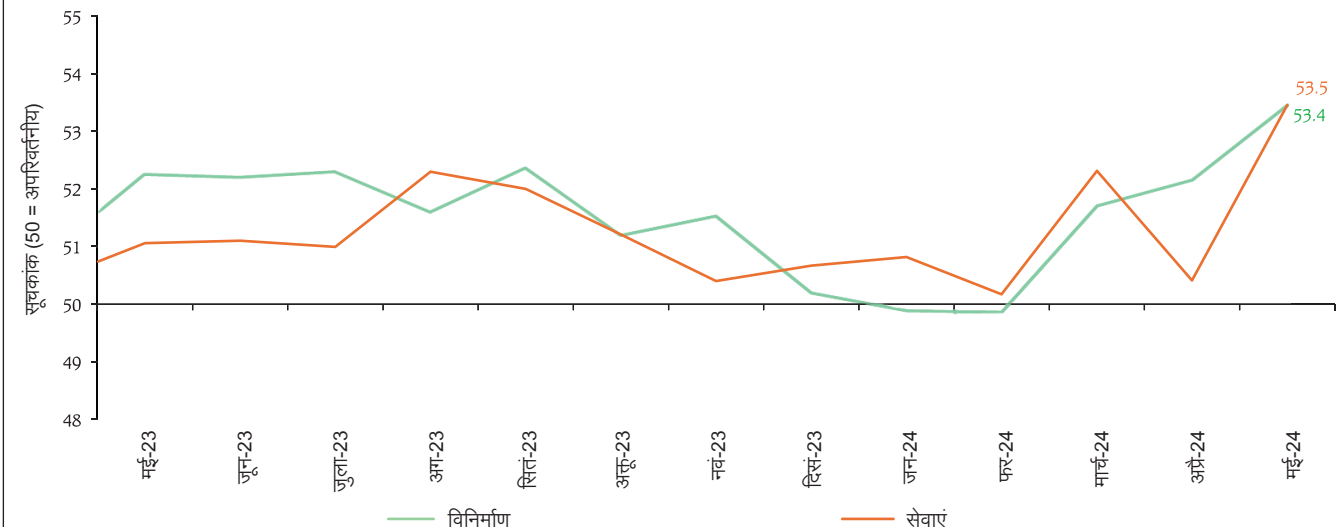
जबकि रोजगार दर (ईआर) में पिछले महीने की तुलना में वृद्धि हुई, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आई (चार्ट III.7बी)।

मई 2024 में, संगठित विनिर्माण रोजगार ने 18 महीनों में सबसे तीव्र विस्तार दर्ज किया, जो नए आदेशों और पीएमआई रोजगार दृष्टिकोण द्वारा पता लगाई गई अनुकूल मांग प्रत्याशाओं से प्रेरित है। अगस्त 2022 के बाद से सेवा रोजगार सृजन अपने सबसे मजबूत स्तर तक विस्तारित हुआ, जो नए व्यापार खंड में

मजबूत वृद्धि से प्रेरित था (चार्ट III.8)।

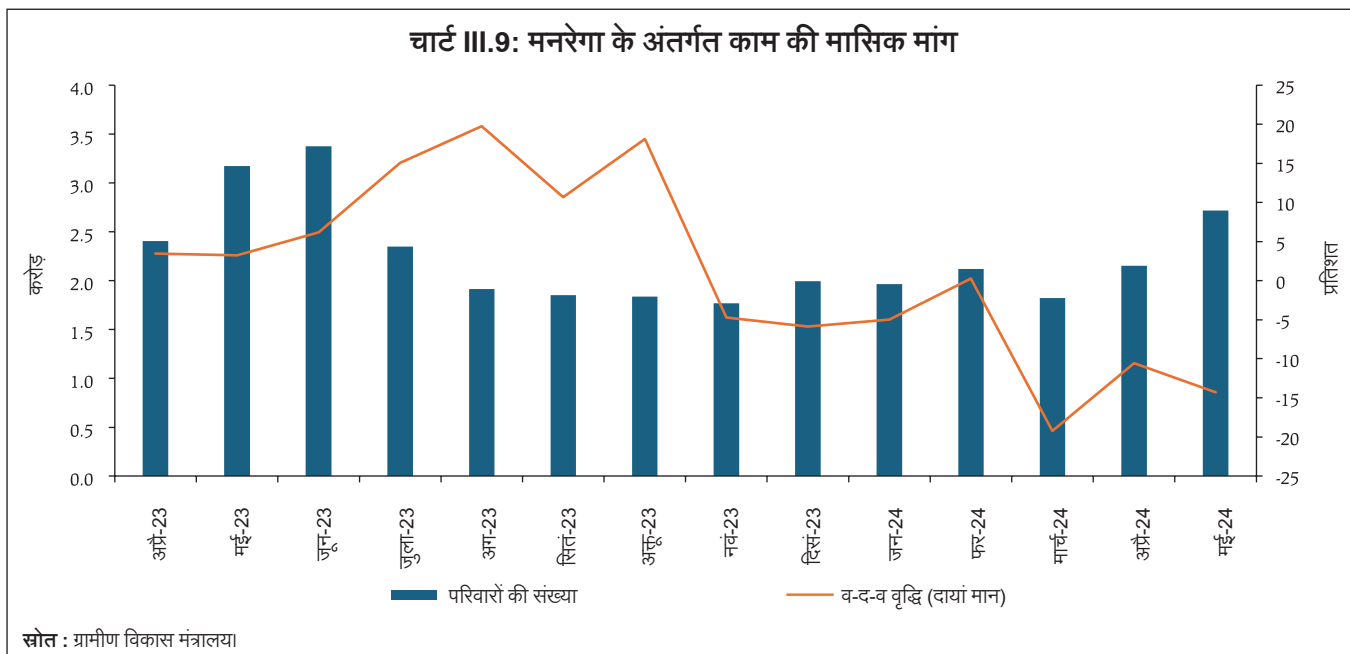
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पारिवारिक स्तर पर काम की मांग में मई में 26.4 प्रतिशत (माह-दर-माह) की वृद्धि देखी गई, जो कृषि उत्पादन में मौसमी स्वरूप को दर्शाती है (चार्ट III.9)। हालांकि, मई 2024 में मनरेगा रोजगार में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 14.3 प्रतिशत की गिरावट आई।

चार्ट III.8: पीएमआई रोजगार सूचकांक



टिप्पणी : पीएमआई का 50 से अधिक का मान विस्तार दर्शाता है।

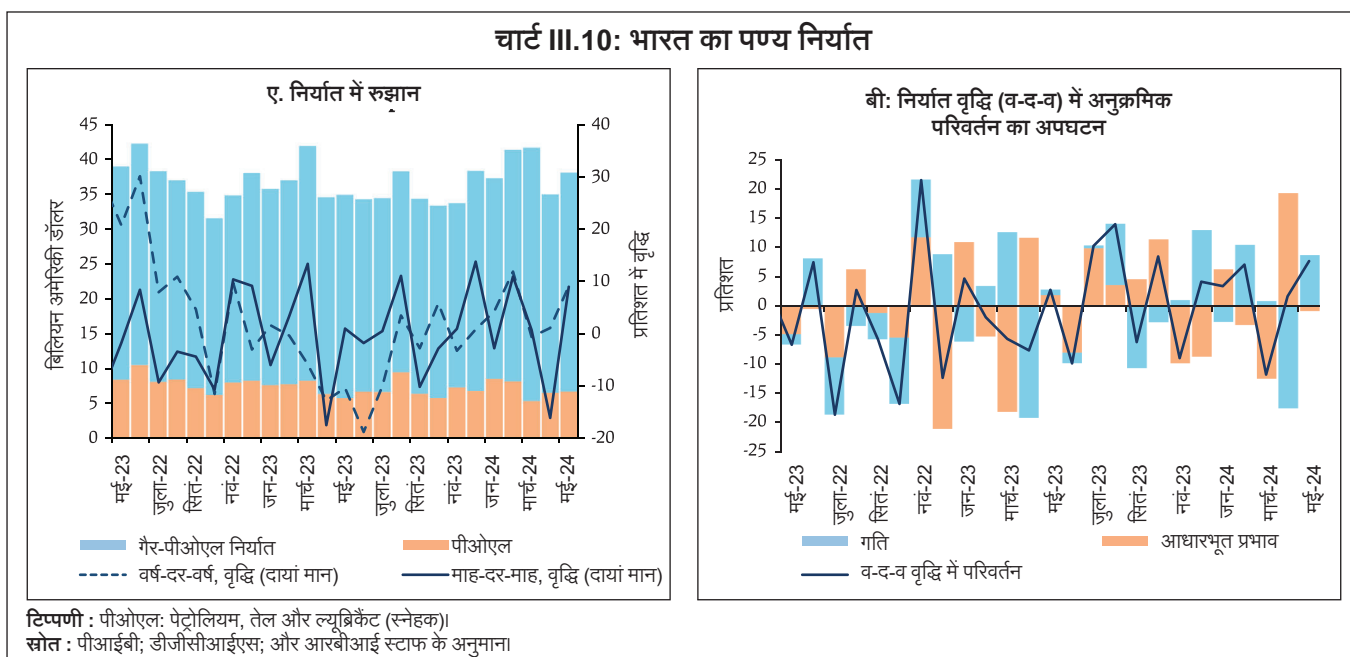
स्रोत : एस एंड पी ग्लोबल।

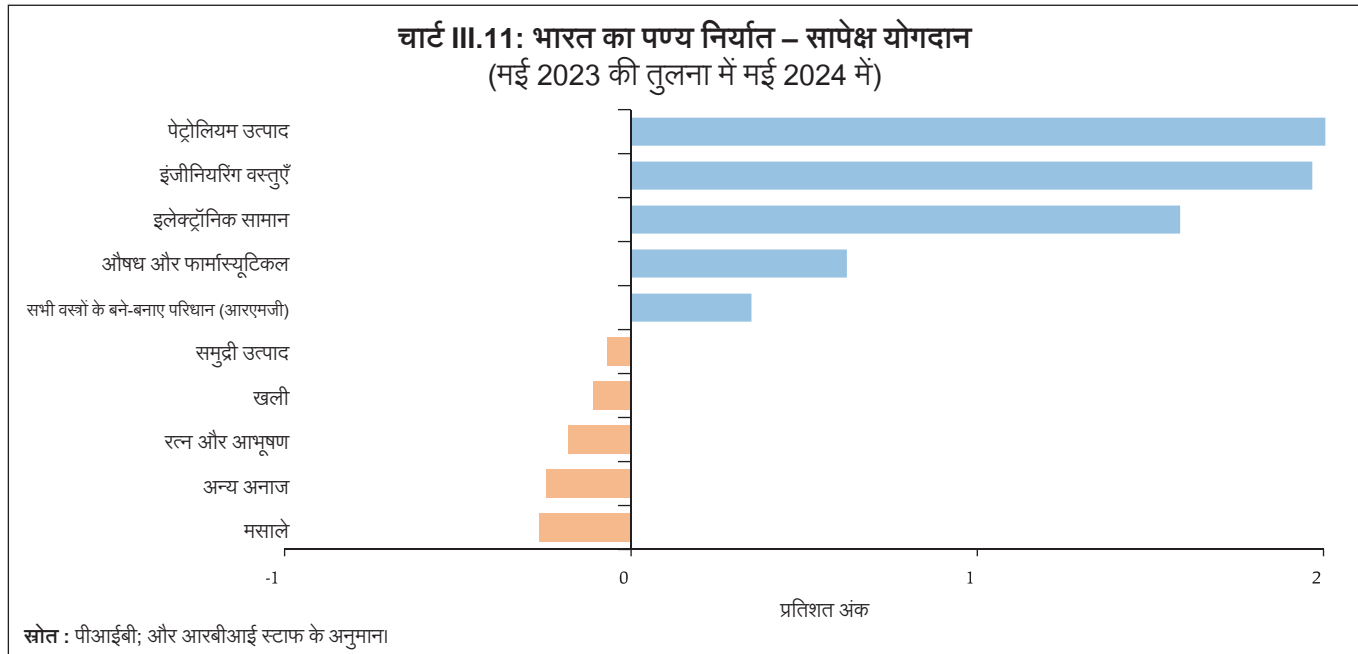


भारत का व्यापारिक निर्यात मई 2024 में 9.1 प्रतिशत की गति से 38.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा, जो अप्रैल में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक था (चार्ट III.10)। वस्तुओं के निर्यात में व्यापक आधार पर विस्तार दर्ज किया गया क्योंकि 30 प्रमुख वस्तुओं में से 20 (निर्यात समूह का 80.8 प्रतिशत हिस्सा) ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विस्तार दर्ज किया। पेट्रोलियम

उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाओं और फार्मास्यूटिकल, और बने-बनाए वस्त्रों ने निर्यात वृद्धि का समर्थन किया, जबकि मसालों, अन्य अनाज, रत्न और आभूषण, खली और समुद्री उत्पादों के कारण मई में इसमें कमी आई (चार्ट III.11)।

मई में 61.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पण्य आयात में 7.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो एक धनात्मक गति से



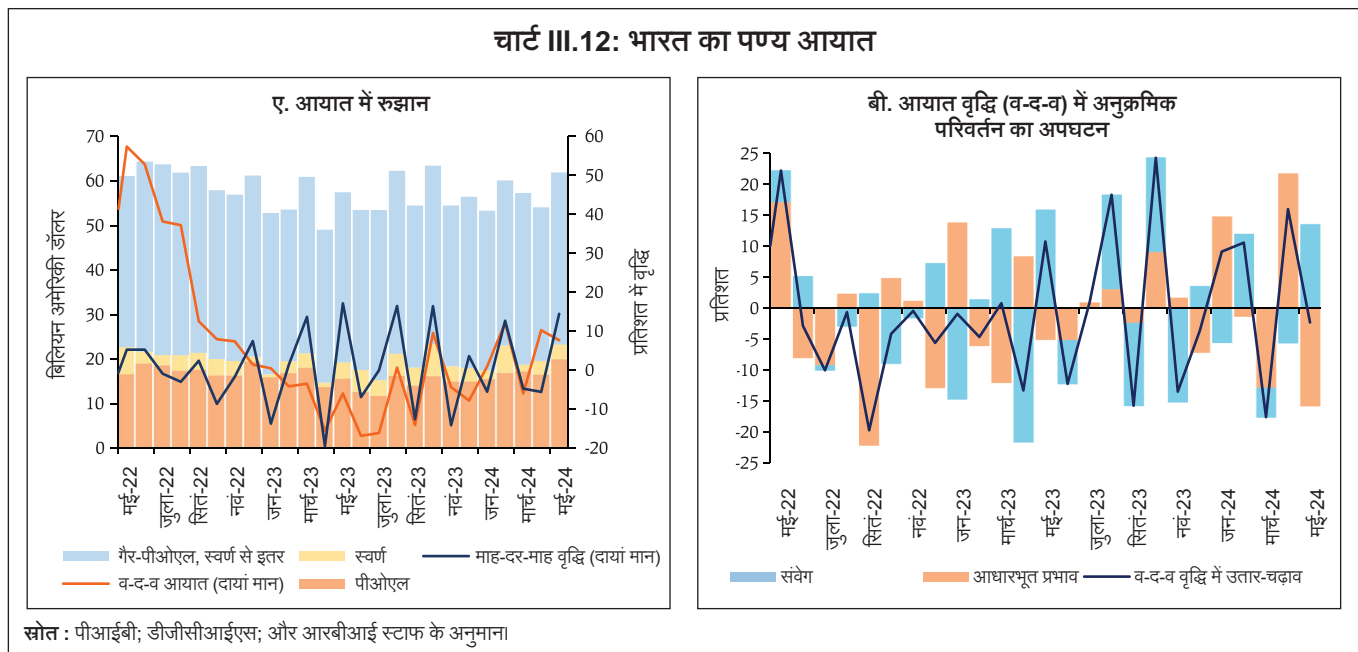


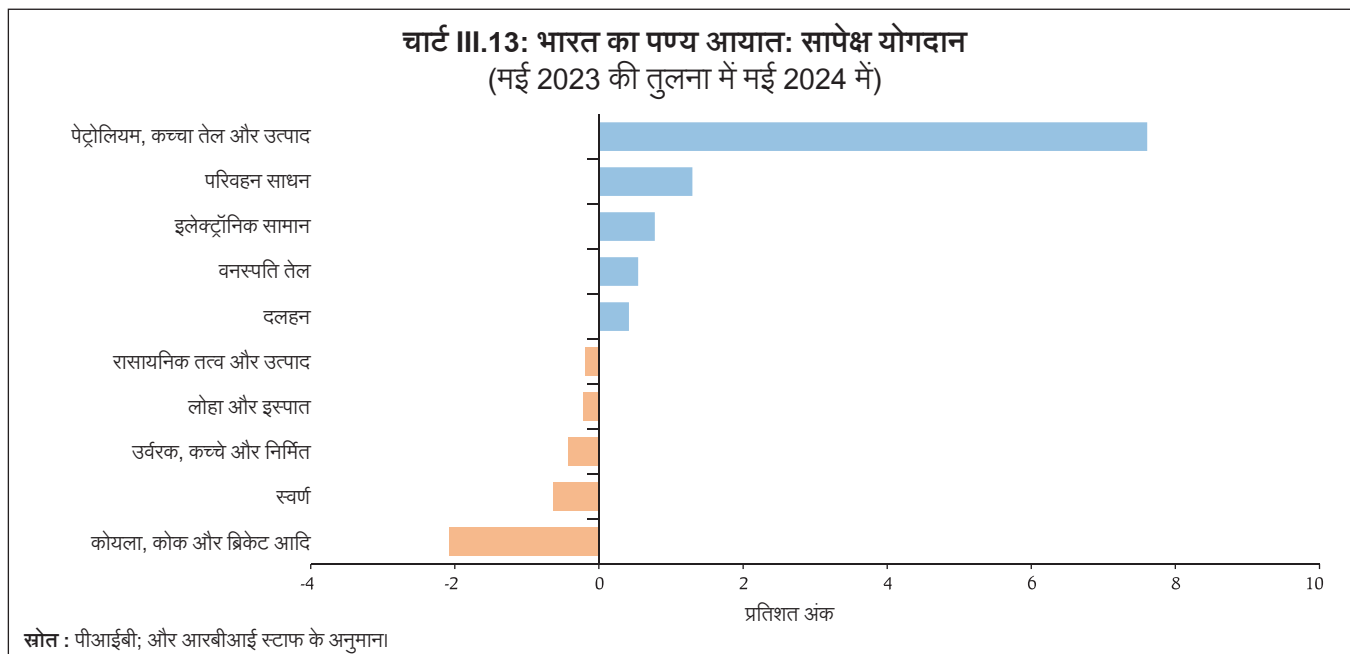
प्रेरित थी (चार्ट III.12)। 30 प्रमुख जिंसों में से 16 जिंसों (आयात समूह का 69.6 प्रतिशत हिस्सा) ने वार्षिक आधार पर वृद्धि दर्ज की।

मई में पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उससे बने उत्पादों, परिवहन साधनों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल और दलहन ने आयात वृद्धि में योगदान दिया, जबकि कोयला, स्वर्ण,

उर्वरक, लोहा और इस्पात, तथा रासायनिक तत्व और उत्पाद प्रमुख अवरोध थे (चार्ट III.13)।

मई 2024 में पण्य व्यापार घाटा 7 महीने के उच्च स्तर 23.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो एक महीने पहले 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मई में तेल घाटा 13.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया,

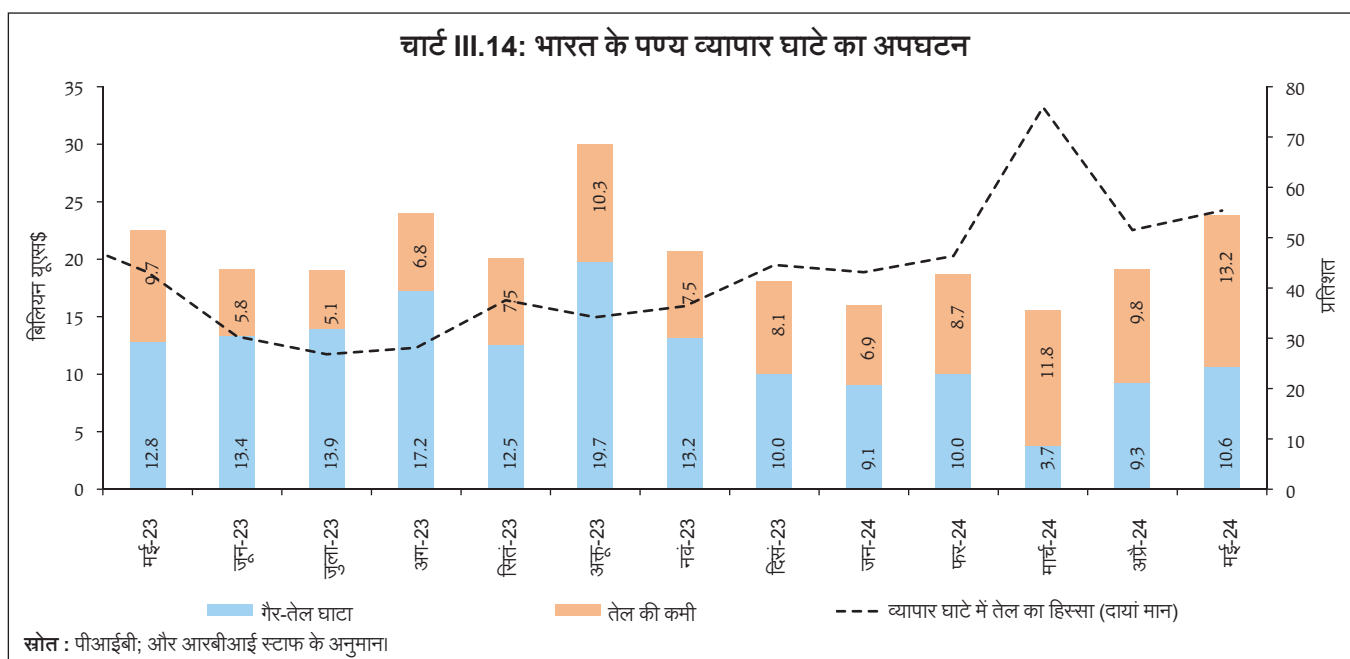


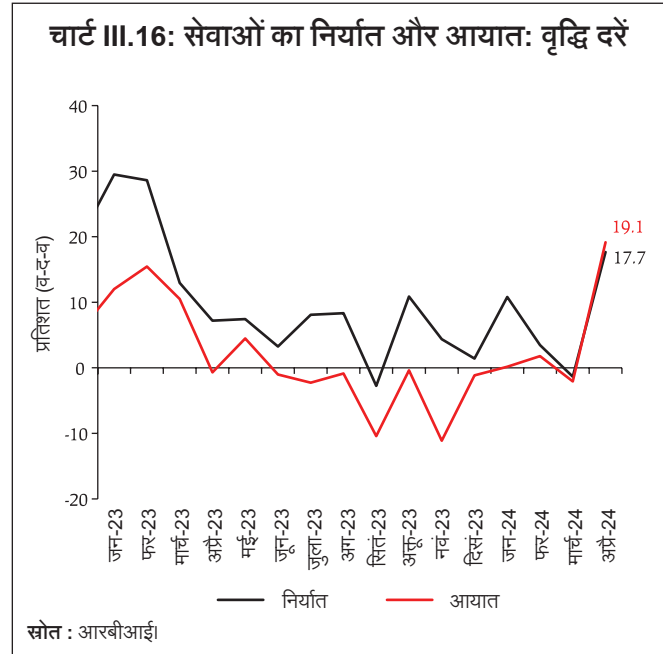
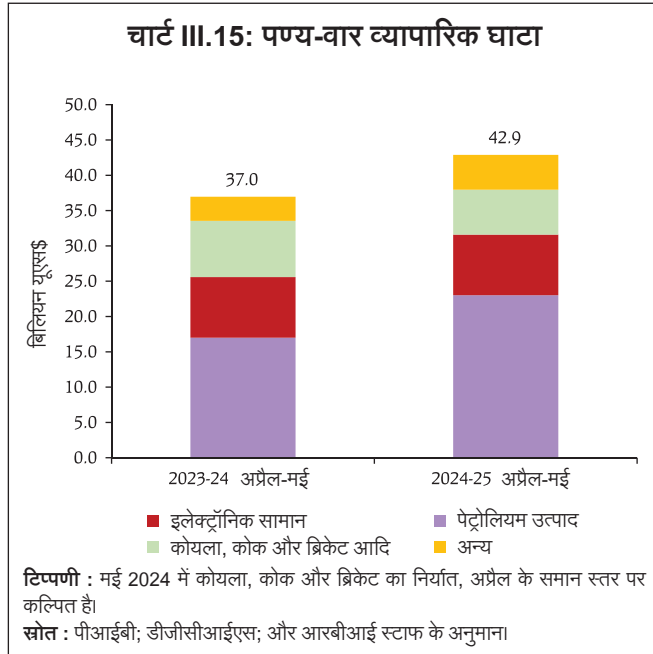


कुल घाटे में इसका हिस्सा बढ़कर 55.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट III.14)। पेट्रोलियम उत्पाद 2024-25 में अब तक (अप्रैल-मई) व्यापार घाटे का सबसे बड़ा कारण थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान थे (चार्ट III.15)।

अप्रैल 2024 में, निर्यात सेवाएं 17.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)

बढ़कर 30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं; जबकि आयात सेवाएं 19.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं (चार्ट III.16)। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल 2024 में निवल निर्यात सेवा अर्जन 15.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।





केंद्र सरकार के प्रमुख घाटे संकेतकों यथा सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा (आरडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) ने संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में अनंतिम खातों (पीए) के अनुसार 2023-24 में सुधार दिखाया। यह सुधार राजस्व प्राप्तियों में व्यापक-आधारित वृद्धि और 2023-24 के संशोधित

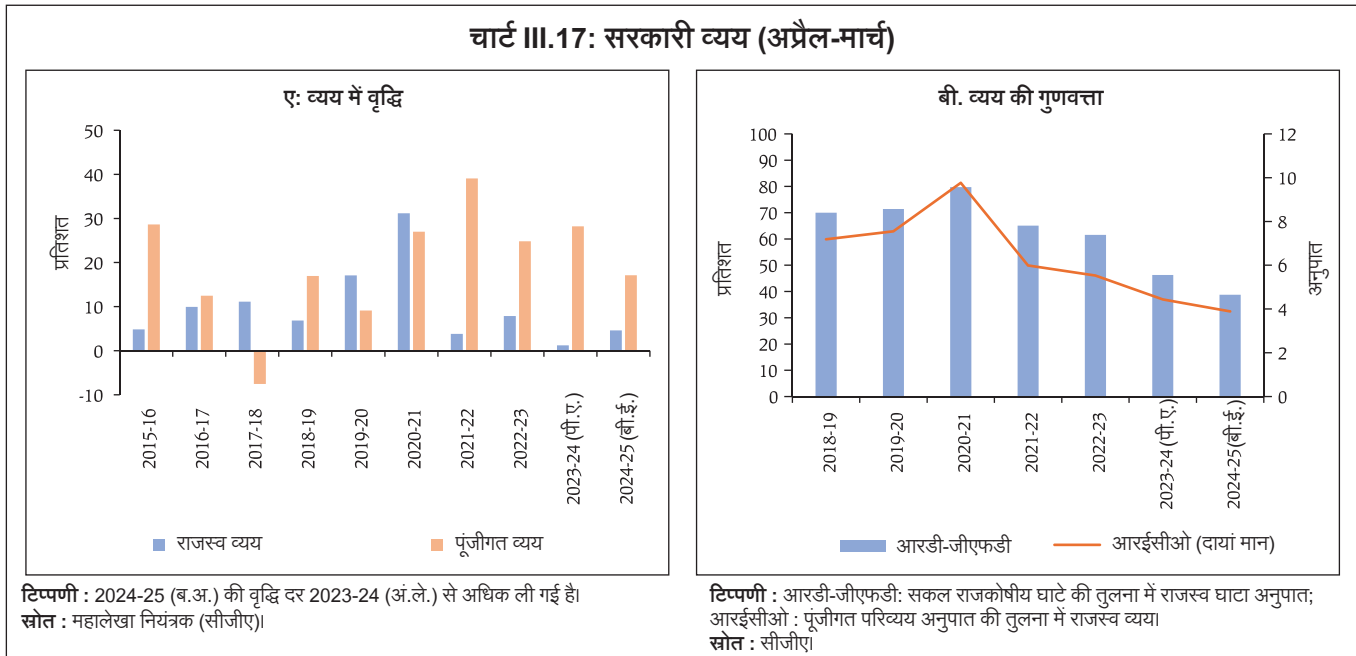
अनुमान (आरई) की तुलना में अनंतिम लेखे (पीए) में राजस्व व्यय की वृद्धि में मंदी के कारण आया था (सारणी III.2)। इसके अतिरिक्त, 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) की तुलना में अनंतिम अनुमानों (पीई) के अनुसार, जीडीपी में ऊर्ध्वगामी संशोधन ने भी 2023-24 (पीए) में जीएफडी-

सारणी III.2: केंद्र सरकार के प्रमुख संकेतक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

1	2022-23	2023-24			2024-25
	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	अं.ले.	ब.अ.
	2	3	4	5	6
1. राजकोषीय घाटा	6.45	5.92	5.90	5.60	5.14
2. राजस्व घाटा	3.97	2.88	2.86	2.59	1.99
3. प्राथमिक घाटा	3.00	2.34	2.31	2.00	1.51
4. सकल कर राजस्व	11.33	11.14	11.70	11.73	11.69
5. कर-रहित राजस्व	1.06	1.00	1.28	1.36	1.22
6. राजस्व व्यय	12.81	11.61	12.05	11.83	11.15
7. पूंजीगत व्यय	2.75	3.32	3.23	3.21	3.39
(i) पूंजीगत परिव्यय	2.32	2.77	2.75	2.67	2.87

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2023-24 (ब.अ.) और 2024-25 (ब.अ.) के लिए प्रयुक्त जीडीपी क्रमशः केंद्रीय बजट 2023-24 और 2024-25 के अनुसार है।
2. वर्ष 2023-24 (सं.अ.) के लिए जीडीपी, एनएसओ द्वारा 29 फरवरी 2024 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) के अनुसार है। वर्ष 2023-24 (अं.ले.) के लिए प्रयुक्त जीडीपी, एनएसओ द्वारा 31 मई 2024 को जारी अनंतिम अनुमान (अं.अ.) है।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज; और महालेखा नियंत्रक (सीजीए)।



जीडीपी अनुपात में सुधार में योगदान दिया। तदनुसार, जीएफडी को 2023-24 (पीए) में जीडीपी के 5.6 प्रतिशत पर रखा गया था, जबकि 2023-24 (आरई) के अनुसार यह जीडीपी के 5.9 प्रतिशत पर था।

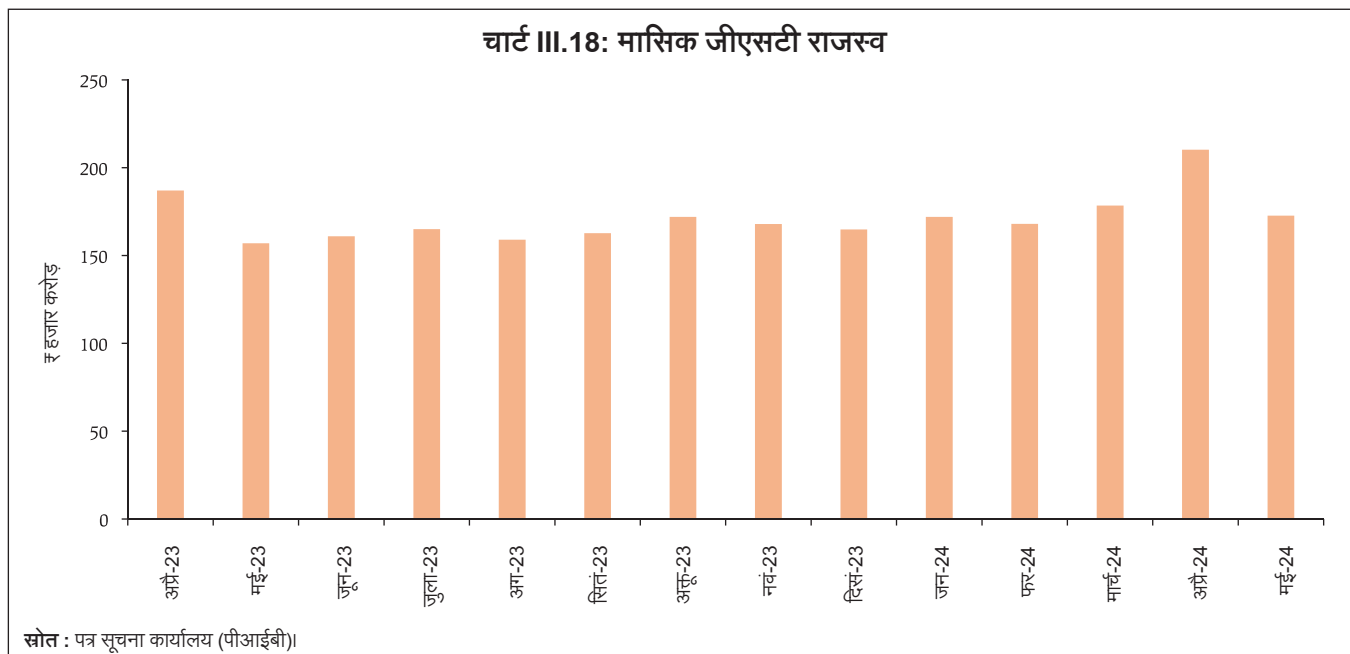
व्यय पक्ष पर, कुल व्यय की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में 2023-24 (पीए) में 5.9 प्रतिशत तक कमी आई। जबकि राजस्व व्यय वृद्धि 1.2 प्रतिशत तक सीमित थी, पूंजीगत व्यय पर जोर जारी रहा (चार्ट III.17ए)। पूंजीगत परिव्यय (अर्थात पूंजीगत व्यय से ऋण और अग्रिम को घटाने पर) में लगातार सुधार जारी रहा, जो मध्यम से दीर्घावधि वृद्धि को मजबूत करने पर सरकार के जोर को रेखांकित करता है। नतीजतन, पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय अनुपात (आरईसीओ) और आरडी-जीएफडी कम बने हुए हैं, जो सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार के संकेतक के रूप में कार्य करता है (चार्ट III.17बी)। इसी तरह प्राप्तियों के स्तर पर, राजस्व प्राप्तियों में 2023-24 (पीए) में 14.5 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गई, जिसमें निवल कर राजस्व और कर-रहित राजस्व में क्रमशः 10.9 प्रतिशत और 40.8 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई।

अप्रैल 2024 के दौरान, घाटे के प्रमुख संकेतकों जैसे जीएफडी, आरडी और पीडी ने अपने संबंधित बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में

वृद्धि दर्ज की। प्राप्तियों के मामले में, सकल कर राजस्व एक साल पहले की तुलना में अधिक रहा, जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः 14.1 प्रतिशत और 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कर-रहित राजस्व में सालाना आधार पर क्रमशः 62.1 प्रतिशत और 149.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत, अप्रैल 2024 के दौरान कुल व्यय वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, जिसका श्रेय राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्रमशः 43.7 प्रतिशत और 26.5 प्रतिशत की वृद्धि को जाता है।

मई 2024 में सकल जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) 9.96 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹1.73 लाख करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण घरेलू लेनदेन में मजबूत वृद्धि है। लगातार मजबूत प्रदर्शन के कारण, अप्रैल-मई 2024-25 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह ₹3.83 लाख करोड़ रहा जिसने 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.18)।

अनंतिम लेखे (पीए) के अनुसार, वर्ष 2023-24 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का समेकित जीएफडी, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.0 प्रतिशत था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान सीमा के अनुरूप था। हालांकि, इसमें एक साल पहले की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से उच्च पूंजीगत व्यय



से प्रेरित है। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत, जीएसटी मुआवजे की समाप्ति के कारण केंद्र सरकार से कम अनुदान तथा वित्त आयोग के अनुदानों की धीरे-धीरे कमी (टेपरिंग) ने, कर और कर-रहित राजस्व में वृद्धि को बराबर कर दिया। दूसरी ओर, वर्ष 2023-24 (पीए) में राज्यों के राजस्व व्यय में गिरावट आई, जबकि 'पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना' द्वारा सहायता प्राप्त पूंजीगत व्यय, जीडीपी का 2.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया। वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों का संयुक्त जीएफडी-

जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है, जो 2023-24 (पीए) के स्तर से अपरिवर्तित है [सारणी III.3]।

बढ़ते पूंजीगत व्यय और कम राजस्व व्यय ने पिछले कुछ वर्षों में राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार किया है, जैसा कि पूंजी परिव्यय की तुलना में कम राजस्व व्यय अनुपात (आरईसीओ) और कुल व्यय में पूंजी परिव्यय के अधिक हिस्से (सीओटीई) में परिलक्षित होता है [चार्ट III.19]।

सारणी III.3: राज्यों के प्रमुख राजकोषीय संकेतक

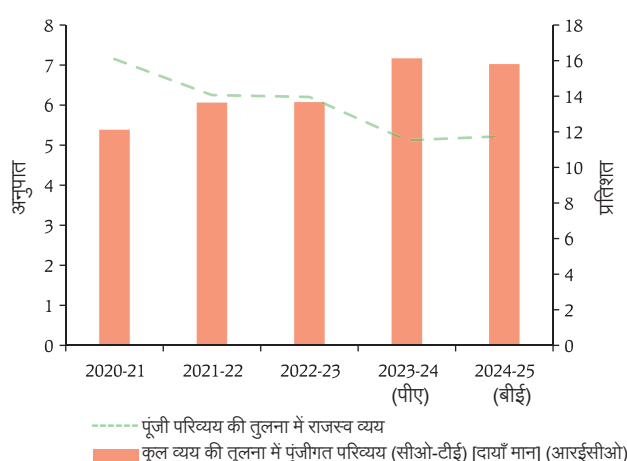
(जीडीपी/ जीएसडीपी का प्रतिशत)

संकेतक	2022-23	2023-24			2024-25
	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	अं.ले.	ब.अ.
राजस्व प्राप्तियां	13.6	14.3	13.8	13.4	13.5
कर राजस्व	10.1	10.4	10.4	10.4	10.5
कर-रहित राजस्व	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1
अनुदान	2.5	2.7	2.3	1.9	1.9
राजस्व व्यय	13.8	14.4	14.3	13.6	13.7
पूंजीगत व्यय	2.5	3.2	3.0	2.9	2.9
जिनमें से:					
पूंजी परिव्यय	2.2	2.9	2.7	2.6	2.6
राजस्व घाटा	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2
सकल राजकोषीय घाटा	2.7	3.1	3.3	3.0	3.0
प्राथमिक घाटा	1.0	1.4	1.6	1.4	1.3

टिप्पणी : वर्ष 2022-23, 2023-24 (ब.अ.) और 2023-24 (अं.ले.) के आंकड़े 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और 2023-24 (सं.अ.) और 2024-25 (ब.अ.) के लिए डेटा 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। वर्ष 2023-24 (सं.अ.) और 2024-25 (ब.अ.) के आंकड़ों को जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

स्रोत : राज्यों के बजट दस्तावेज़; और भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक।

चार्ट III.19: राज्यों के व्यय की गुणवत्ता के संकेतक



टिप्पणी : 2023-24 (अं.ले.) का डेटा 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और 2024-25 (ब.अ.) का डेटा 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

स्रोत : राज्यों के बजट दस्तावेज़; और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

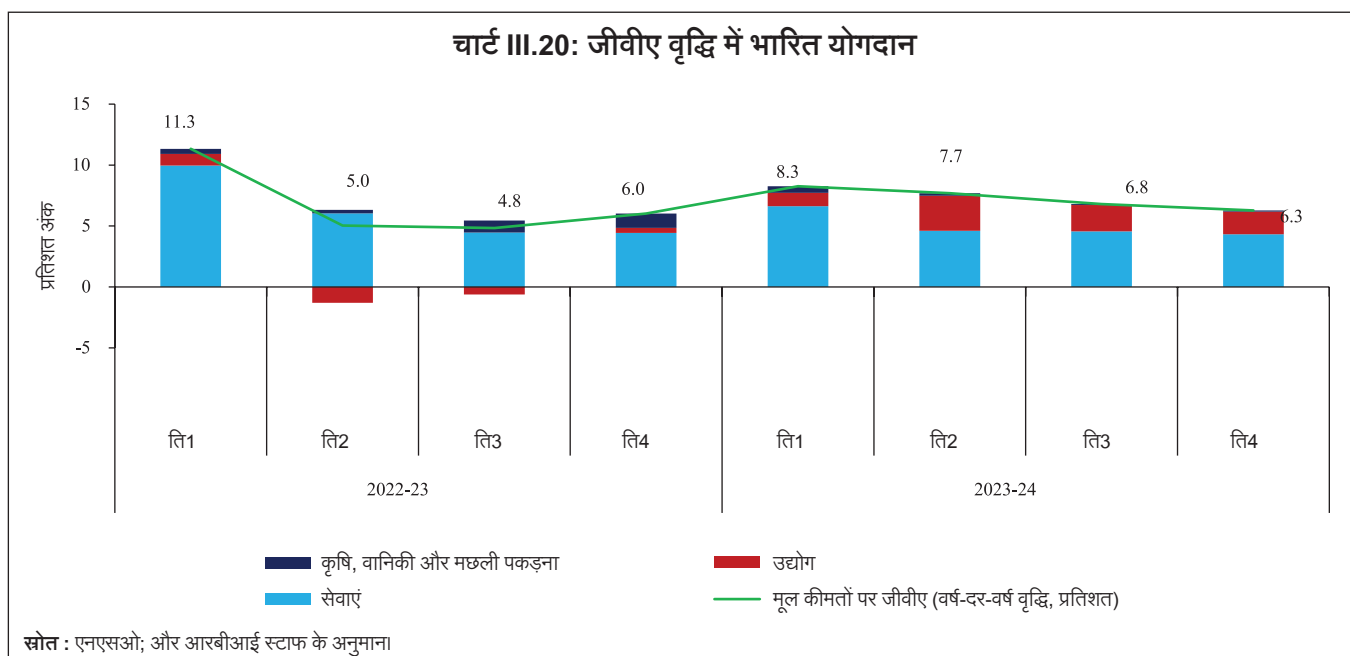
समग्र आपूर्ति

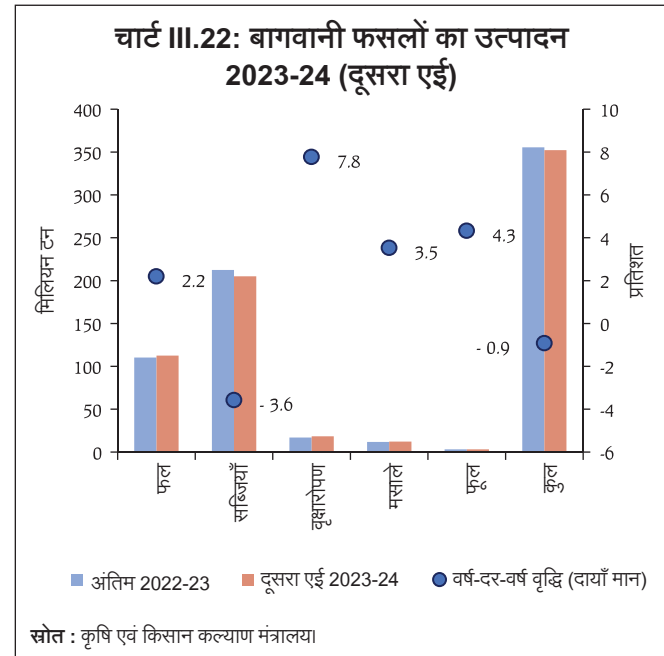
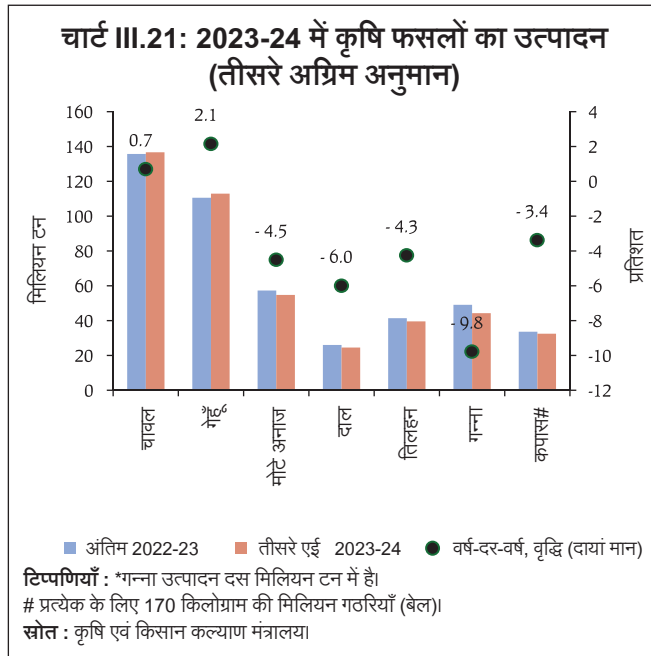
मूल कीमतों पर जीवीए द्वारा मापी गई समग्र आपूर्ति, पीई के अनुसार 2023-24 में 7.2 प्रतिशत बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) में जीवीए वृद्धि को 6.9 प्रतिशत से 30 आधार अंक बढ़ाकर संशोधित किया गया।

वर्ष 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में, वास्तविक जीवीए वृद्धि 6.3 प्रतिशत थी, जो एसएई में 5.4 प्रतिशत की अंतर्निहित वृद्धि दर से काफी अधिक थी। हालांकि, इसने औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में मंदी के कारण अपनी गति खो दी (चार्ट III.20)। कृषि ने 2023-24 की तीसरी तिमाही में 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 0.6 प्रतिशत पर मामूली वृद्धि प्रदर्शित की। विनिर्माण जीवीए वृद्धि में कमी आई, क्योंकि इनपुट लागत में वृद्धि हुई जिससे सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की लाभप्रदता प्रभावित हुई। हालांकि पिछली तीन तिमाहियों के दौरान संकुचन में रहने के बाद, असंगठित विनिर्माण क्षेत्र की वास्तविक जीवीए वृद्धि ने धनात्मक क्षेत्र में प्रवेश किया। जबकि खनन और उत्खनन क्षेत्रों की वृद्धि क्रमिक रूप से धीमी हो गई, यह कोयला और प्राकृतिक गैस के मजबूत उत्पादन द्वारा समर्थित 2022-23 की चतुर्थ तिमाही की तुलना में मजबूत

रही। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत पर समुत्थानशील रही। सेवा क्षेत्र में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथा वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाओं में पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई, जिसे आशावादी क्रेडिट और जमा वृद्धि एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार से समर्थन मिला। सरकारी व्यय में वृद्धि और अन्य सेवाओं में सुधार के कारण लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में विस्तार दर्ज किया गया। निर्माण गतिविधि का विस्तार यद्यपि कुछ संयम के साथ जारी रहा। हालांकि, प्रसारण से संबंधित व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और सेवाओं में वृद्धि, क्रमिक और वर्ष-दर-वर्ष, दोनों आधार पर कम हुई।

कृषि फसल उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों (एई) ने 2023-24 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन को 328.9 मिलियन टन पर रखा, जो कि 2022-23 के अंतिम अनुमानों की तुलना में थोड़ा कम (-0.3 प्रतिशत) है (चार्ट III.21)। यह अल-नीनो वर्ष में सामान्य से कम और अनियमित मानसून के बावजूद मौसम की स्थितियों के प्रति खाद्यान्न उत्पादन की समुत्थानशीलता में वृद्धि को सकारात्मक रूप से दर्शाता है। जबकि गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, दलहन और मोटे अनाज के उत्पादन





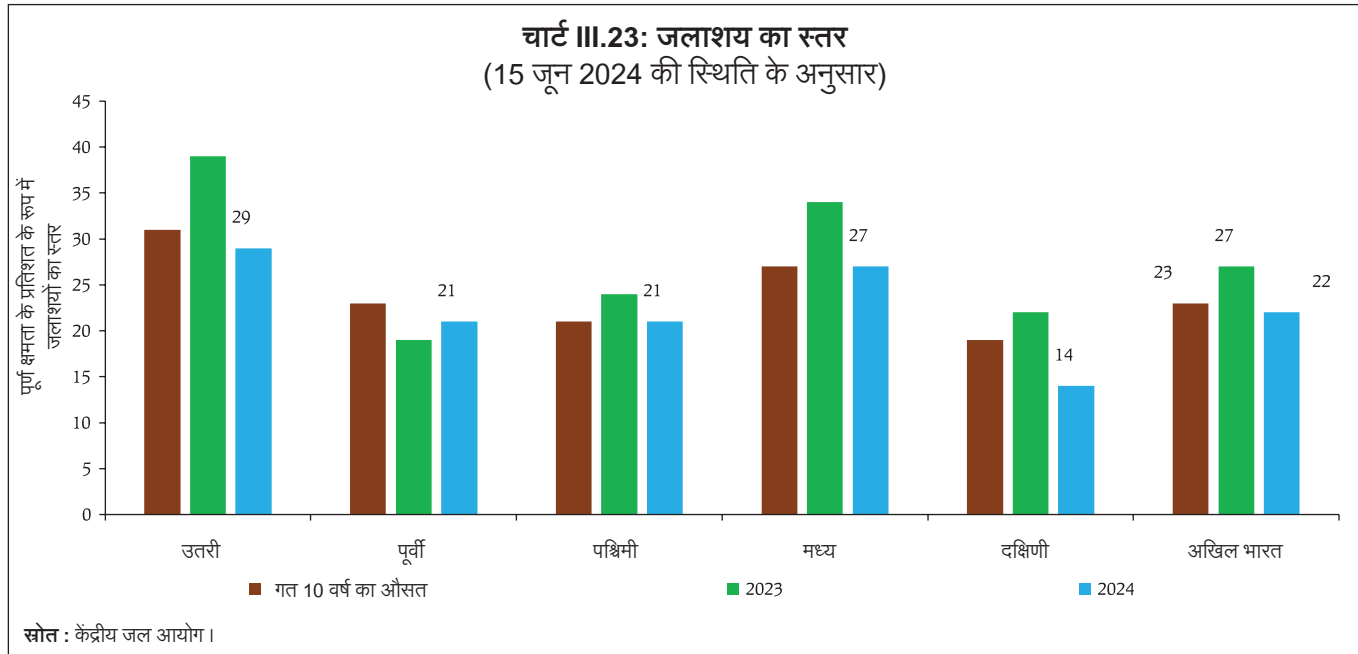
में गिरावट से यह संतुलित हुआ। दलहन-उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत कम रहा, जिसका मुख्य कारण फसल के तहत क्षेत्र में गिरावट थी। वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत सभी फसलों, विशेष रूप से गन्ने के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड उत्पादन से 2023-24 में 9.8 प्रतिशत कम हो गई। तिलहन उत्पादन में भी 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट (-12.9 प्रतिशत) है।

2002-03 के बाद पहली बार 2023-24 में बागवानी फसलों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। दूसरे वार्षिक अनुमान के अनुसार, 2023-24 के दौरान बागवानी फसलों के उत्पादन में 2022-23 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है, जिसकी वजह प्याज (-19.8 प्रतिशत) और आलू (-5.6 प्रतिशत) का कम उत्पादन है [चार्ट III.22]। दूसरी ओर, फलों के उत्पादन में 2022-23 की तुलना में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2023-24 में बागवानी फसलों की कुल उपज में 2022-23 की तुलना में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कुल क्षेत्रफल में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

आईएमडी ने सामान्य से अधिक एसडब्ल्यूएम का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें 61 प्रतिशत संभावना है कि बारिश पिछले आठ वर्षों में पहली बार¹⁰ सामान्य से अधिक होगी। आईएमडी को यह भी उम्मीद है कि बारिश के अनुकूल ला नीना की स्थिति और सकारात्मक हिंद महासागर डिपोल (आईओडी) की उत्पन्न स्थिति के कारण मानसून अच्छी होगी। वर्षा के स्थानिक वितरण से पता चलता है कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक, उत्तर-पश्चिम में सामान्य और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। देश के अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों से मिलकर बने मानसून कोर जोन (एमसीजेड) में बारिश सामान्य से अधिक होने की उम्मीद है।

सामान्य से अधिक एसडब्ल्यूएम का पूर्वानुमान आगामी खरीफ बुआई के लिए शुभ संकेत है। 15 जून, 2024 तक एसडब्ल्यूएम पहले ही मध्य भारत में प्रवेश कर चुका है और संचयी वर्षा (01 जून, 2024 से) दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) से 16 प्रतिशत कम रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान एलपीए से 51 प्रतिशत कम थी।

¹⁰ आईएमडी के दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) के लिए 27 मई 2024 को जारी अद्यतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान (एलआरएफ) के अनुसार, वर्षा अधिक सटीकता (मॉडल त्रुटि +/- 4 प्रतिशत) के साथ पिछले एलआरएफ से एलपीए के 106 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

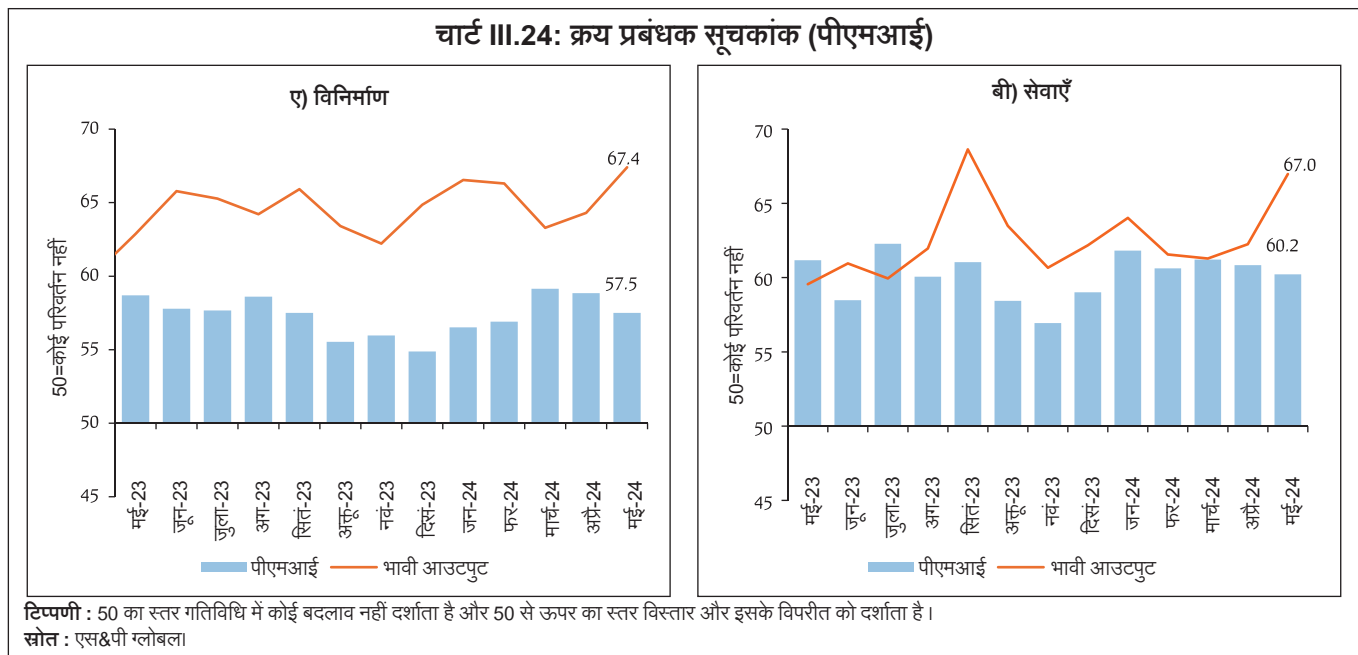


जलाशयों का स्तर दशकीय औसत से नीचे बना हुआ है। देश के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण स्तर कुल जलाशय क्षमता का 22 प्रतिशत है (चार्ट III.23)।

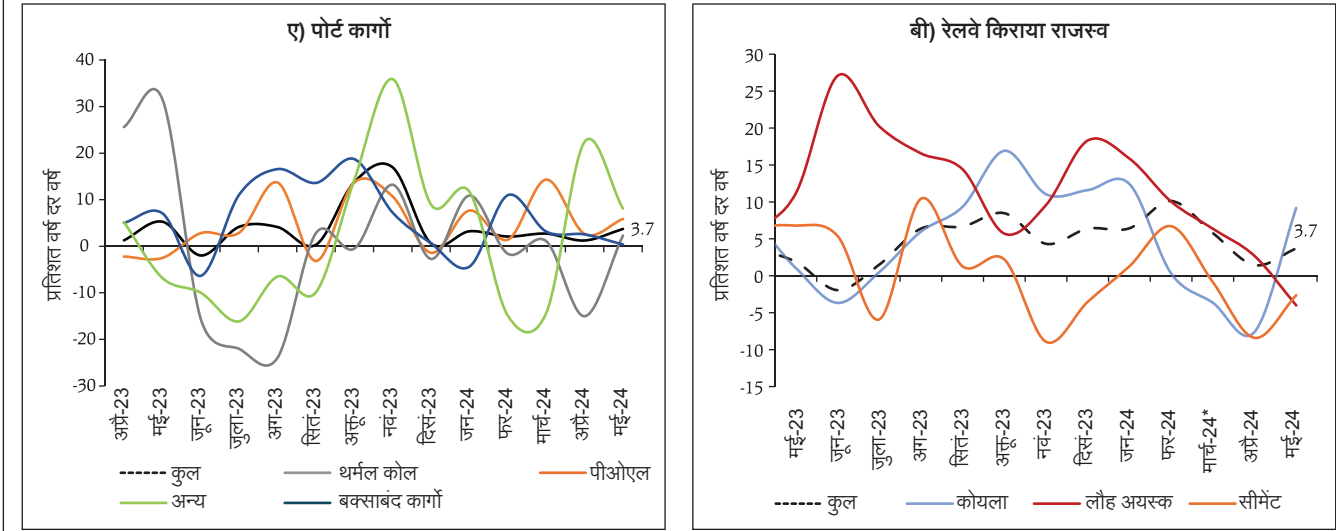
क्रमिक नरमी के बावजूद, विनिर्माण के लिए हेडलाइन पीएमआई मई 2024 में विस्तार की स्थिति में रहा (चार्ट III.24ए)। अनुकूल मांग स्थितियों और नवाचार के कारण मई में भविष्य

का उत्पादन लगभग साढ़े नौ वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो 67.4 तक पहुंच गया। सेवाओं के लिए पीएमआई में भी धीमी गति से विस्तार करना जारी रहा है, जो नए व्यवसाय में वृद्धि से प्रेरित है। (चार्ट III.24बी)।

मई 2024 में माल परिवहन के संकेतकों में तेजी आई। प्रमुख बंदरगाहों पर माल यातायात में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई,



चार्ट III.25: पोर्ट कार्गो और रेलवे किराया ट्रैफिक



टिप्पणी : * मार्च 2024 में रेलवे माल दुलाई के आंकड़े फरवरी और अप्रैल 2024 की औसत संख्या के रूप में प्रक्षेपित किया गया है।
स्रोत : भारतीय बंदरगाह संघ; रेल मंत्रालय।

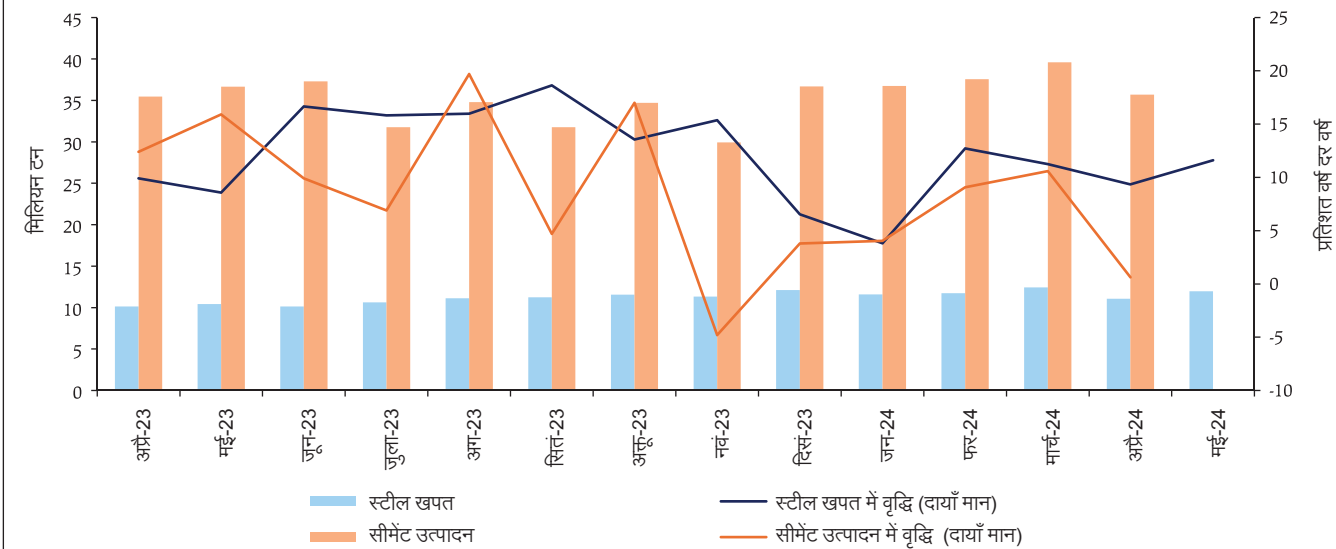
जिसमें कोयला और पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल) के कार्गो का योगदान सबसे अधिक रहा [चार्ट III.25ए]। कोयला यातायात में वृद्धि के कारण रेलवे माल यातायात में भी वृद्धि हुई (चार्ट III.25बी)।

निर्माण क्षेत्र ने मिश्रित संकेत दिए, मई 2024 में इस्पात की खपत में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अप्रैल

2024 में सीमेंट उत्पादन की वृद्धि 0.6 प्रतिशत पर धीमी रही (चार्ट III.26)।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतकों ने मई 2024 में विस्तार दर्ज किया, जो आर्थिक गतिविधि में निरंतर विकास का संकेत देता है (सारणी III.4)।

चार्ट III.26: स्टील खपत और सीमेंट निर्माण

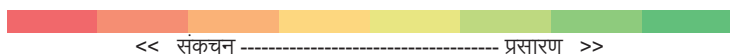


स्रोत : संयुक्त प्लांट समिति और आर्थिक परामर्शदाता, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कार्यालय।

सारणी III.4 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएँ

(वर्ष दर वर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	सित-23	अक्तू-23	नव-23	दिस-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रैल-24	मई-24	
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	3.1	17.3	4.3	3.2	13.9	5.7	8.9	1.2	4.0	
	दोपहिया वाहन बिक्री	0.8	20.1	31.3	16.0	26.2	30.0	15.3	30.8	10.1	
ग्रामीण मांग	तीन पहिया वाहन बिक्री	47.0	42.1	30.8	30.6	9.5	4.6	4.3	14.5	14.7	
	ट्रैक्टर बिक्री	-14.7	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-33.0	-23.1	-3.0	0.0	
	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	6.9			3.2			-3.8			
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	रेलवे माल ढुलाई यातायात	6.7	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1		1.5	3.7	
	पोर्ट कार्गो यातायात	0.3	13.8	16.9	0.6	3.2	-1.4	2.7	1.3	3.7	
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	-4.5	10.6	9.0	8.7	10.0	7.6	8.7	0.3	8.1	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	2.7	15.0	4.9	12.2	19.3	25.7	22.5	16.2	19.0	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	19.3	10.7	8.7	8.1	5.0	2.2	4.7	3.8	5.3	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	19.6	17.5	19.8	18.1	17.0	15.2	15.0	16.8	14.9	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	9.5	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (आंतर राज्य)	12.4	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	4.9	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	
	होटल अधिभोग दर @	61.0	62.5	63.0	70.0	66.6	72.5	64.4	62.3		
	प्रति कमरा औसत राजस्व	18.3	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8		
	यात्री आगमन	17.5	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7		
	विनिर्माण	इस्पात उपभोग	18.6	13.6	15.4	6.5	3.8	12.7	11.2	9.3	11.6
		सीमेंट उत्पादन	4.7	17.0	-4.8	3.8	4.0	9.1	10.6	0.6	
पीएमआई संकेतक*	सेवाएँ	61.0	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	



टिप्पणी : #: स्तरों में डेटा. *: मई 2024 के आंकड़े दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। @: डेटा दर में है, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर में नहीं। हीट-मैप जुलाई-2021 से आज तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए तैयार किया गया है।
स्रोत : सियाम; रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ; भारतीय बंदरगाह संघ; आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; जीएसटीएन; हवाई अड्डों भारतीय प्राधिकरण; एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्किट।

मुद्रास्फीति

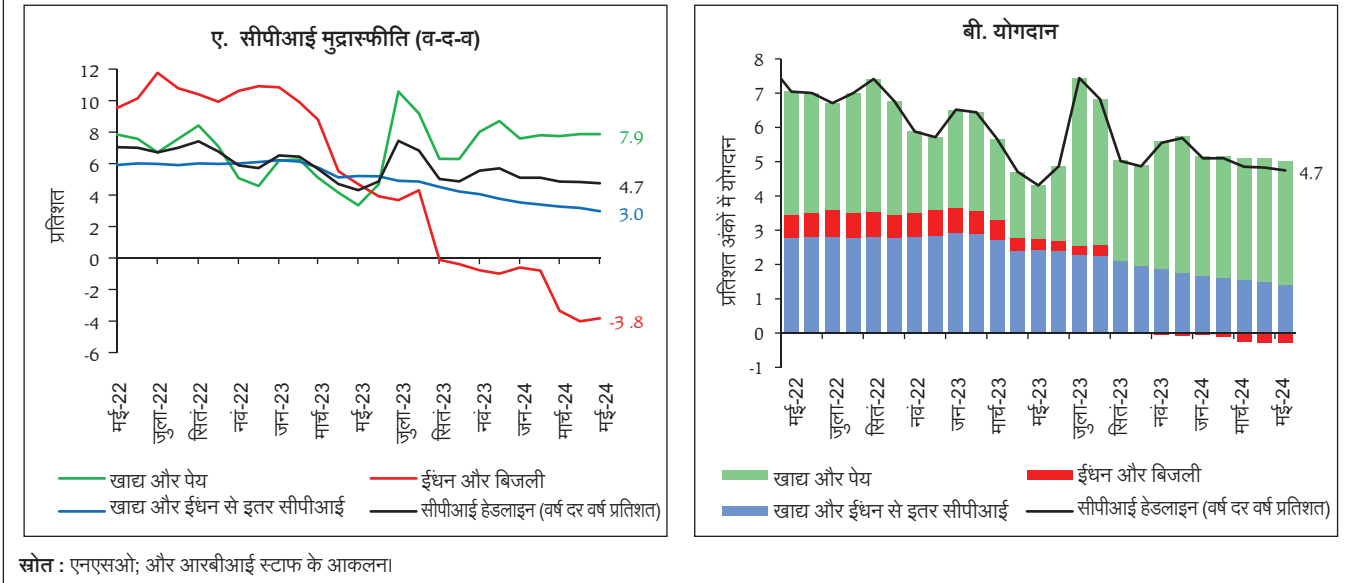
अखिल भारतीय सीपीआई¹¹ में साल-दर-साल बदलावों के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल में 4.8 प्रतिशत से मई 2024 में घटकर 4.7 प्रतिशत हो गई - जो पिछले 12 महीनों में सबसे कम है (चार्ट III.27)। मुद्रास्फीति में 8 बीपीएस की यह नरमी 56 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव से आई, जो खाद्य में 68 बीपीएस, ईंधन में 80 बीपीएस और कोर गुप (अर्थात खाद्य और ईंधन को छोड़कर) में 24 बीपीएस की वृद्धि के

कारण 48 बीपीएस के सकारात्मक परिवर्तन को ऑफसेट करने के पश्चात आया है।

मई में खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) 7.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। उप-समूहों के संदर्भ में, अनाज, अंडे, फल और दालों के संबंध में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जबकि मांस और मछली, दूध, चीनी, मसाले, गैर-अल्कोहल पेय और तैयार भोजन की मुद्रास्फीति में कमी देखी गई। सब्जियों की कीमतों में लगातार सातवें महीने दो अंकों की वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई। खाद्य तेलों में अपस्फीति बनी रही, हालांकि एक महीने पहले की तुलना में यह दर धीमी रही (चार्ट III.28)।

¹¹ एनएसओ द्वारा 12 जून 2024 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

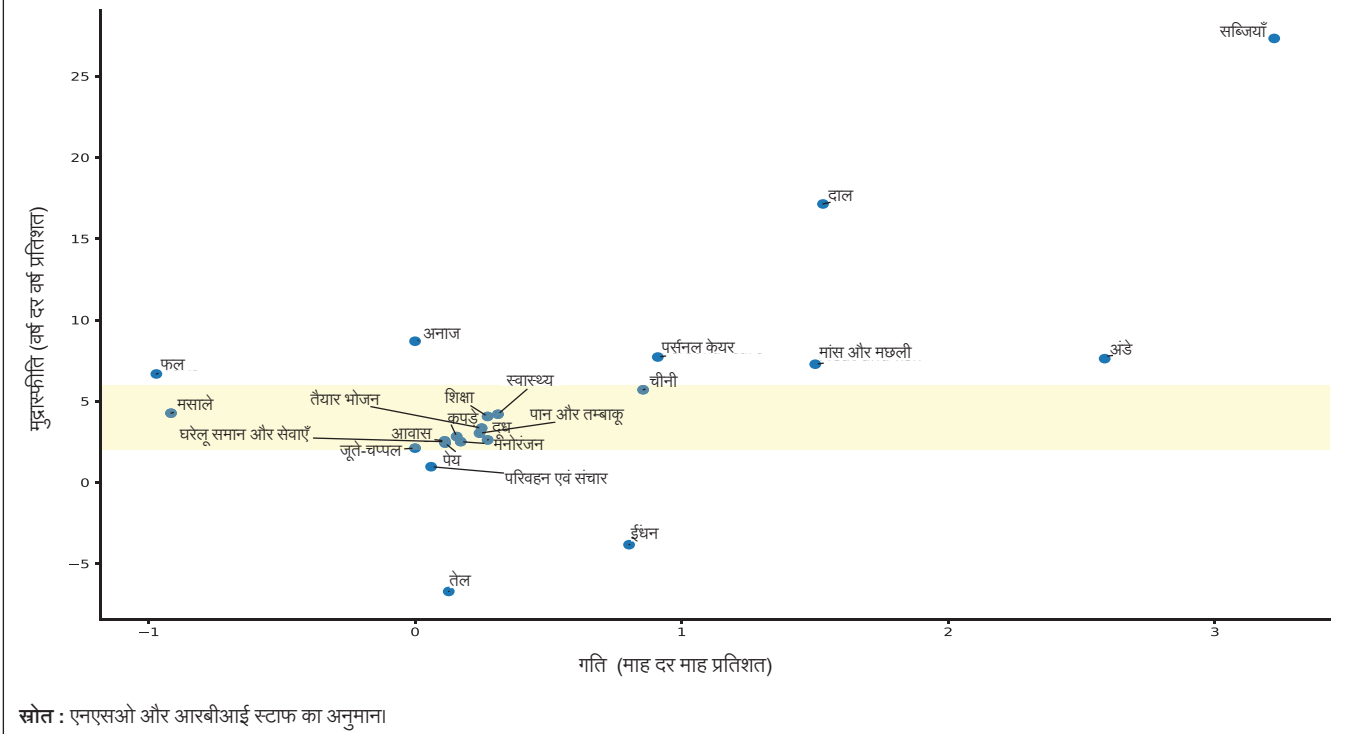
चार्ट III.27: सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और वाहक

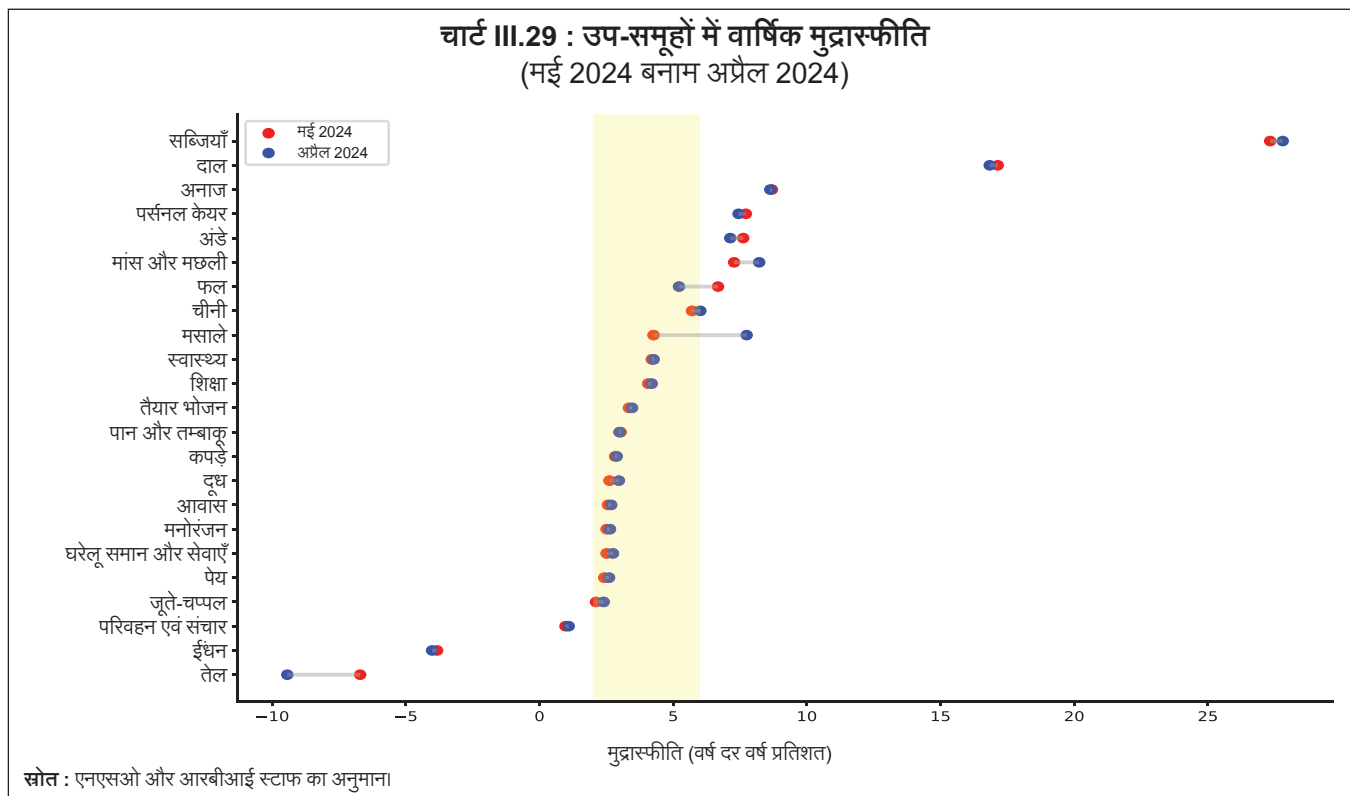


ईंधन की अवस्फीति अप्रैल में (-)4.0 प्रतिशत से घटकर मई में (-)3.8 प्रतिशत तक कम हो गई, जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत केरोसिन की

कीमतों की मुद्रास्फीति में वृद्धि है। बिजली की कीमतों के मामले में मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में बनी रही, जबकि एलपीजी की कीमतों में दोहरे अंकों में गिरावट दर्ज की गई।

चार्ट III.28 : उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) एवं गति (माह दर माह)



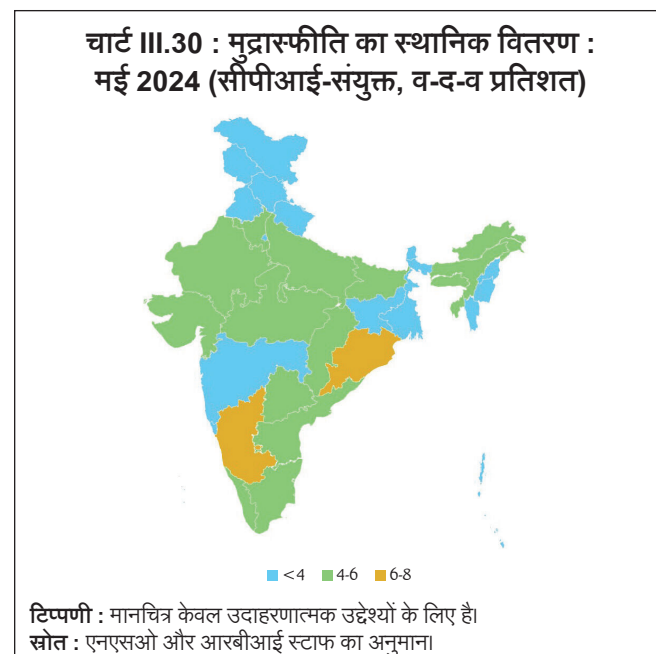


कोर मुद्रास्फीति अप्रैल में 3.2 प्रतिशत से मई में और कम होकर 3.0 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई (2012=100) शृंखला में सबसे कम है, जिसमें 9 में से 7 उप-समूहों में नरमी दर्ज की गई। पान, तम्बाकू और मादक पदार्थों की मुद्रास्फीति अपरिवर्तित रही, जबकि व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.29)।

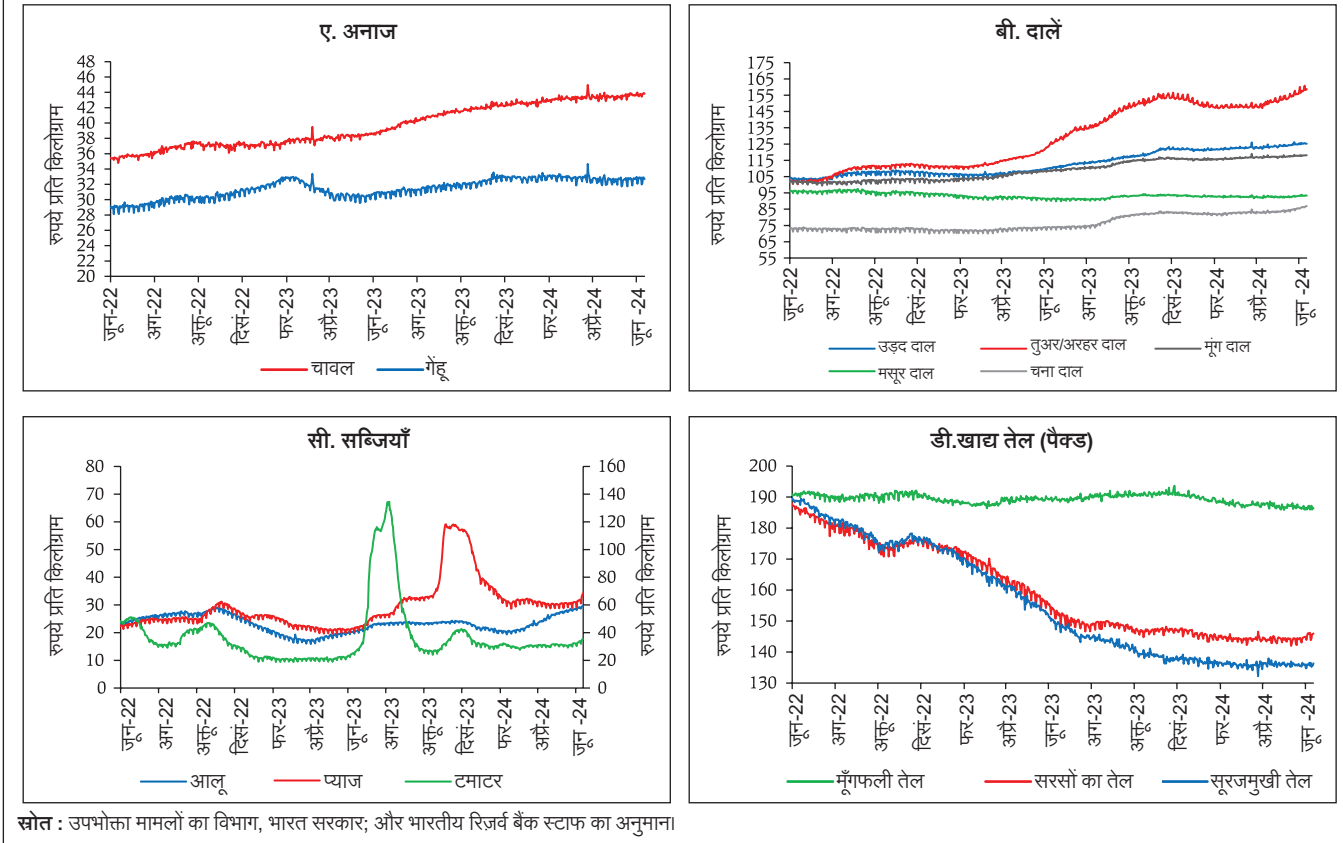
क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, मई 2024 में 5.3 प्रतिशत पर ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति (4.2 प्रतिशत) से अधिक थी। अधिकांश राज्यों को 6 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा (चार्ट III.30)।

जून के लिए अब तक (12 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा से पता चलता है कि अनाज की कीमतों में, मुख्य रूप से चावल और गेहूँ के मामले में, वृद्धि दर्ज की गई है। दालों की कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि दर्ज की गई और सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य तेल की कीमतों में भी तेजी आई। प्रमुख सब्जियों में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में जून में और वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.31)।

जून में अब तक (12 तारीख तक) चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें स्थिर रहीं। केरोसिन की कीमतों में यद्यपि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी के अनुरूप गिरावट दर्ज की गई, तथापि एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया (सारणी III.5)।



चार्ट III.31 : डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य



मई 2024 के लिए पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की फर्मों में इनपुट लागत में वृद्धि का संकेत दिया। विनिर्माण और सेवाओं दोनों में आउटपुट कीमतों में भी तेजी आई (चार्ट III.32)।

दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो पिछली तिमाही में 3.8 प्रतिशत से अधिक थी, लेकिन एक वर्ष पहले के 4.6 प्रतिशत से कम थी (चार्ट III.33)।

2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान, अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)¹² में 4.1 प्रतिशत (वर्ष-

मई 2024 में रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के सर्वेक्षण (आईईएसएच) के दौर में, उनकी मौजूदा मुद्रास्फीति धारणाएं 10

सारणी III.5: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह दर माह (प्रतिशत)	
		जून-23	मई-24	जून-24 [^]	मई-24	जून-24 [^]
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.91	100.91	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	90.72	90.72	0.0	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	44.12	50.03	46.61	0.9	-6.0
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	1113.25	813.25	813.25	0.0	0.0

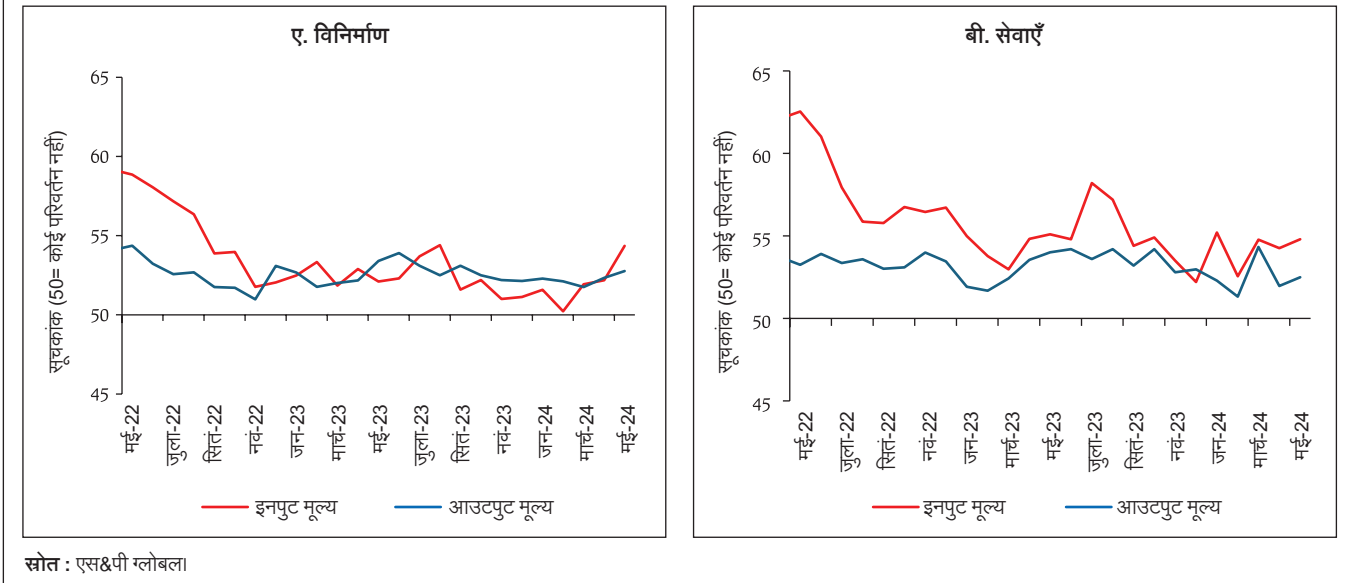
[^]: 1-12 जुलाई, 2024 की अवधि के लिए।

नोट : मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत : आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

¹² आवास मूल्य सूचकांक (आधार: 2010-11=100), दस प्रमुख शहरों (यथा अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में पंजीकरण प्राधिकारियों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

चार्ट III.32: पीएमआई - इनपुट और आउटपुट मूल्य



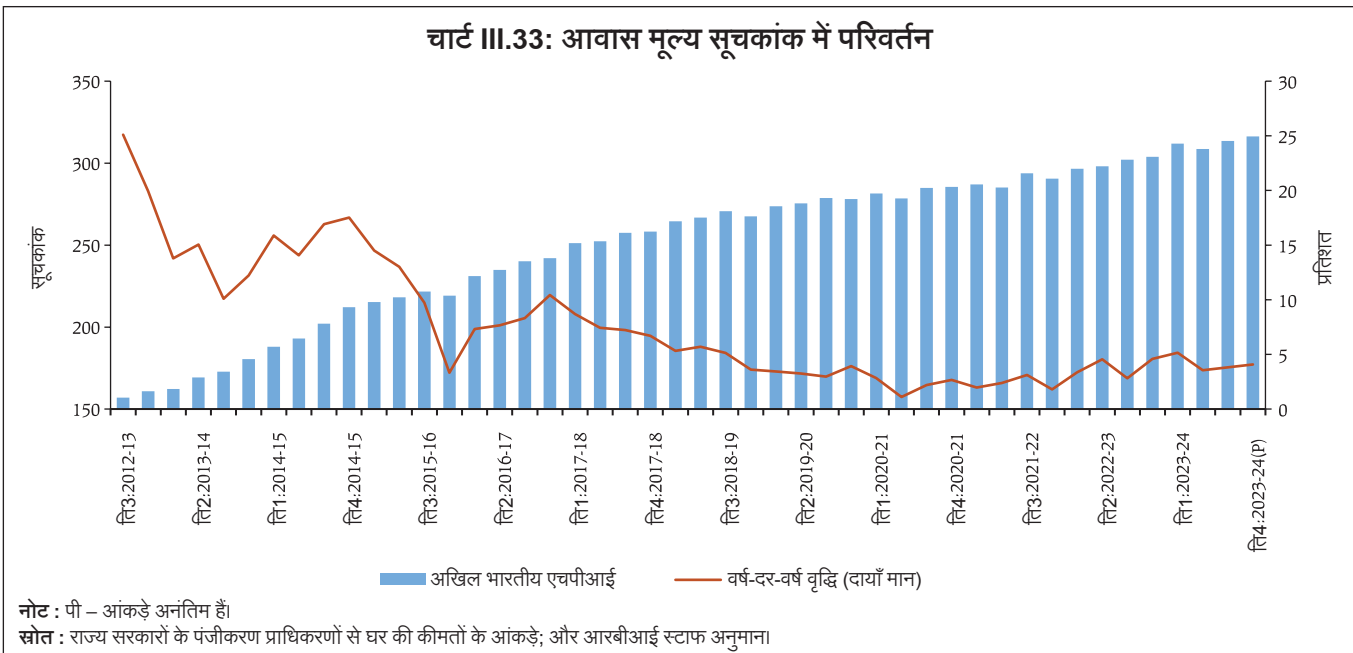
बीपीएस से घटकर 8.0 प्रतिशत हो गईं हालांकि, उनकी तीन महीने और एक साल आगे की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में क्रमशः 20 बीपीएस और 10 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट III.34)।

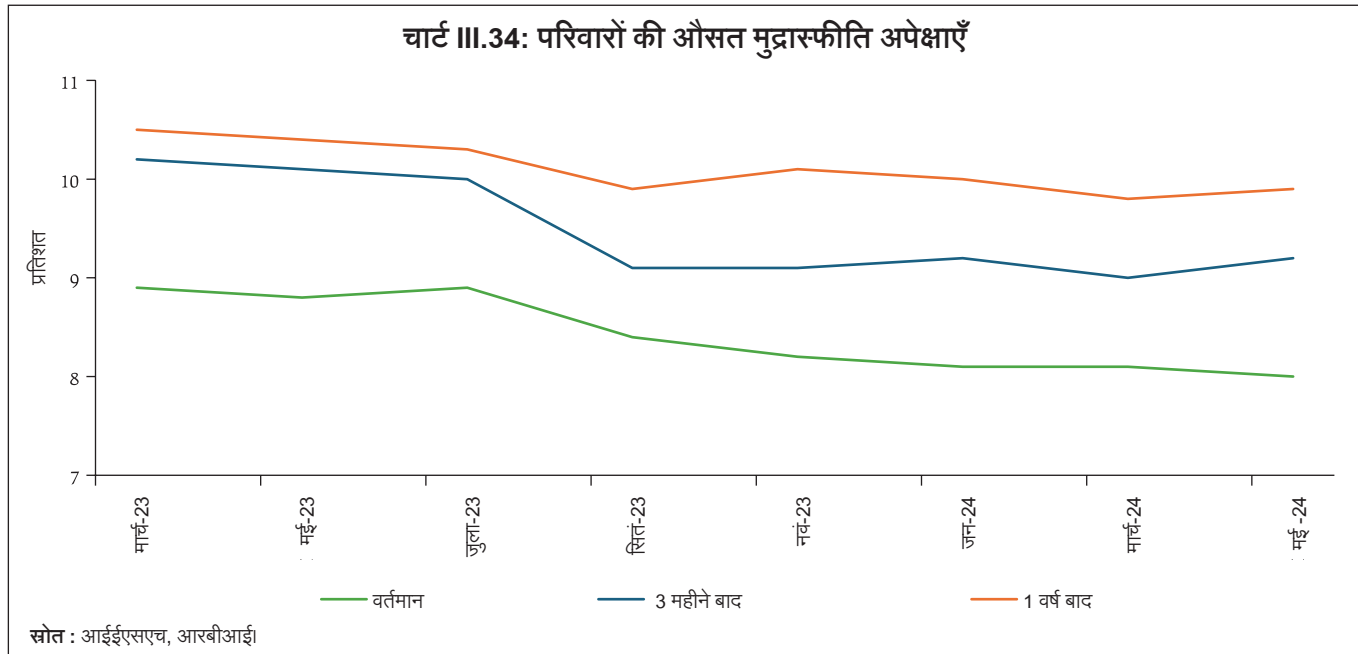
IV. वित्तीय स्थितियाँ

अप्रैल के अंत और मई के दौरान प्रणालीगत चलनिधि घाटे में रही, क्योंकि अग्रिम कर भुगतान और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बहिर्वाह, सुस्त सरकारी खर्च और उच्च

मुद्रा व्यय के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि हुई। यह 2 जून, 2024 से अधिशेष में बदल गया, जबकि महीने के अंत में सरकारी नकदी शेष में सामान्य कमी आई। इन बदलावों को दर्शाते हुए, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन 16 मई से 12 जून, 2024 के दौरान ₹0.76 लाख करोड़ रहा, जबकि 16 अप्रैल - 15 मई, 2024 के दौरान औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन ₹0.80 लाख करोड़ था (चार्ट IV.1)।

चार्ट III.33: आवास मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

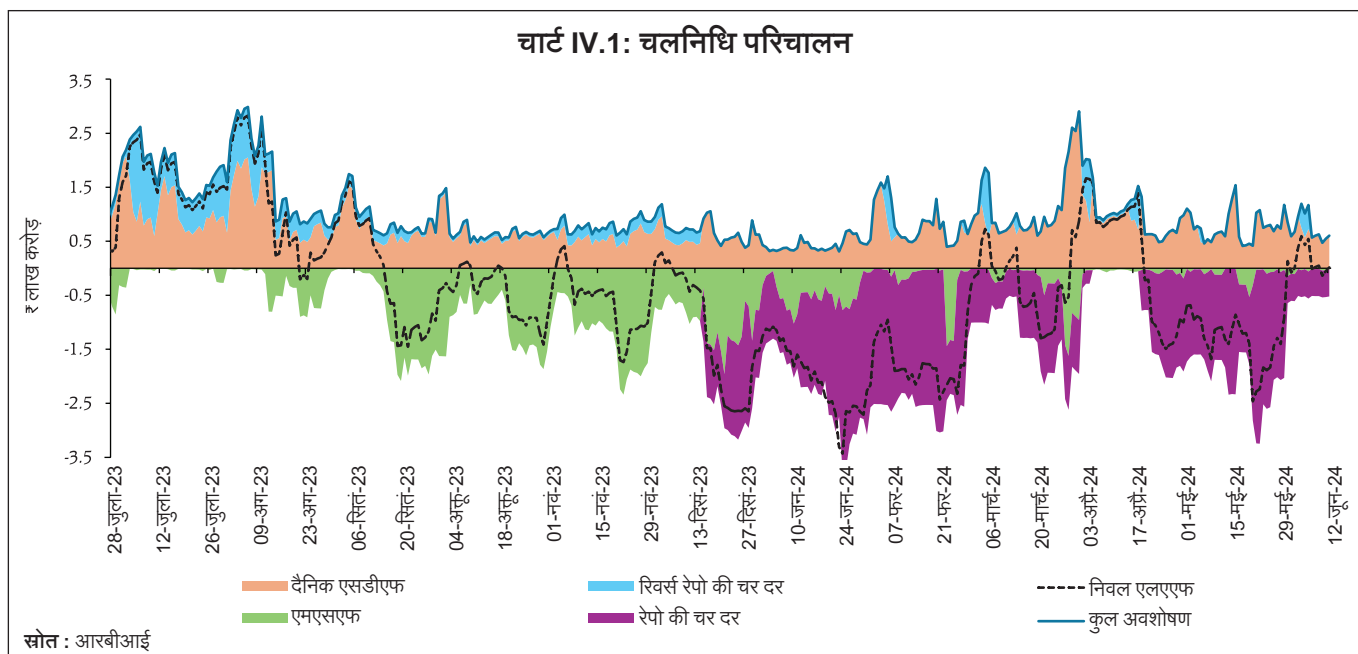




रिज़र्व बैंक ने 16 मई से 12 जून, 2024 के दौरान दो मुख्य परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालनों और 2 से 4 दिन की परिपक्वता वाले चार परिमार्जन वीआरआर परिचालनों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अंतर्विष्ट की, जिसकी कुल राशि ₹5.72 लाख करोड़ थी। मुख्य और परिमार्जन वीआरआर परिचालनों में उच्च बोली-कवर अनुपातों में परिलक्षित निधियों की मांग मज़बूत थी। जून की शुरुआत में जब चलनिधि की स्थिति

अधिशेष में बदल गई, तो रिज़र्व बैंक ने 4 जून, 2024 को 3 दिन की परिपक्वता वाली दो परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित कीं, जिनमें से कुल मिलाकर ₹0.44 लाख करोड़ अवशोषित हुए।

2024 के दौरान कठोर चलनिधि की स्थिति के बीच सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत उधारी बढ़कर ₹10,001 करोड़ के दैनिक औसत पर पहुंच गई, जबकि 16 अप्रैल से 15 मई



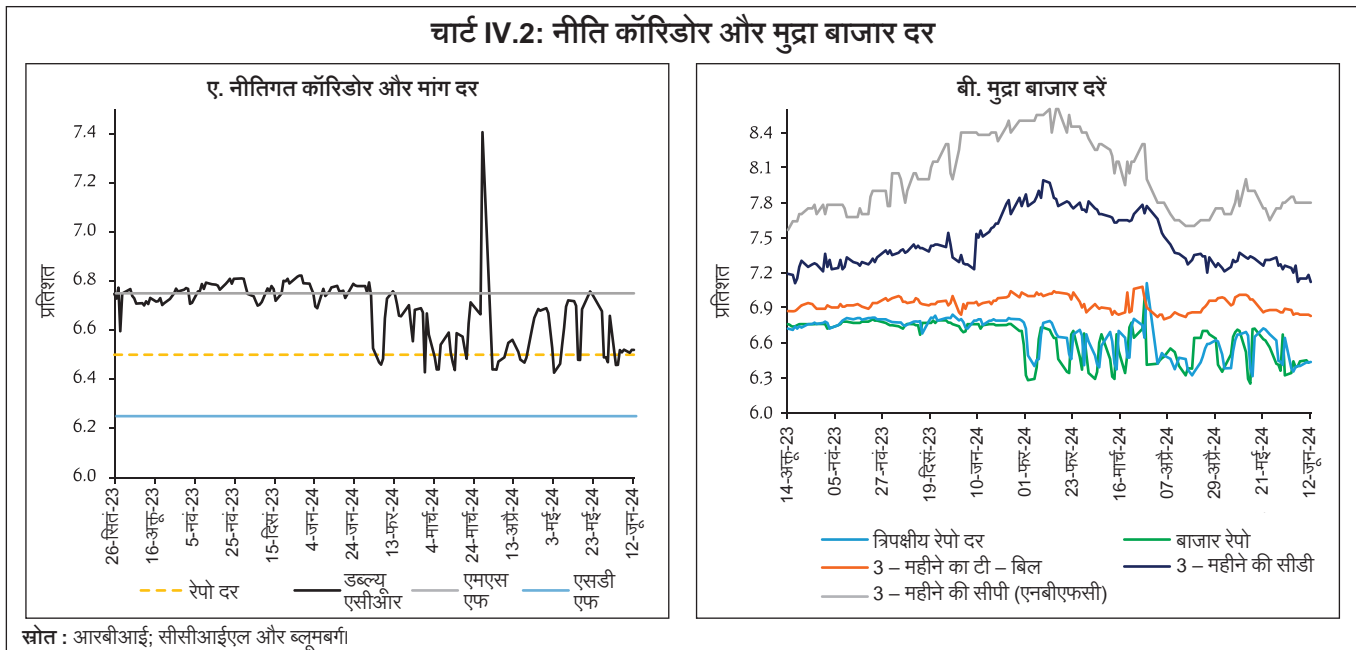
2024 के दौरान यह ₹5,850 करोड़ थी। 16 मई से 12 जून 2024 के दौरान ₹0.77 लाख करोड़ के औसत कुल अवशोषण में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधियों का प्लेसमेंट 16 अप्रैल से 15 मई 2024 के दौरान औसत कुल अवशोषण के 92 प्रतिशत की तुलना में 94 प्रतिशत था। शेष राशि 4 जून 2024 को किए गए परिमार्जन वीआरआरआर परिचालन के माध्यम से जुटाई गई।

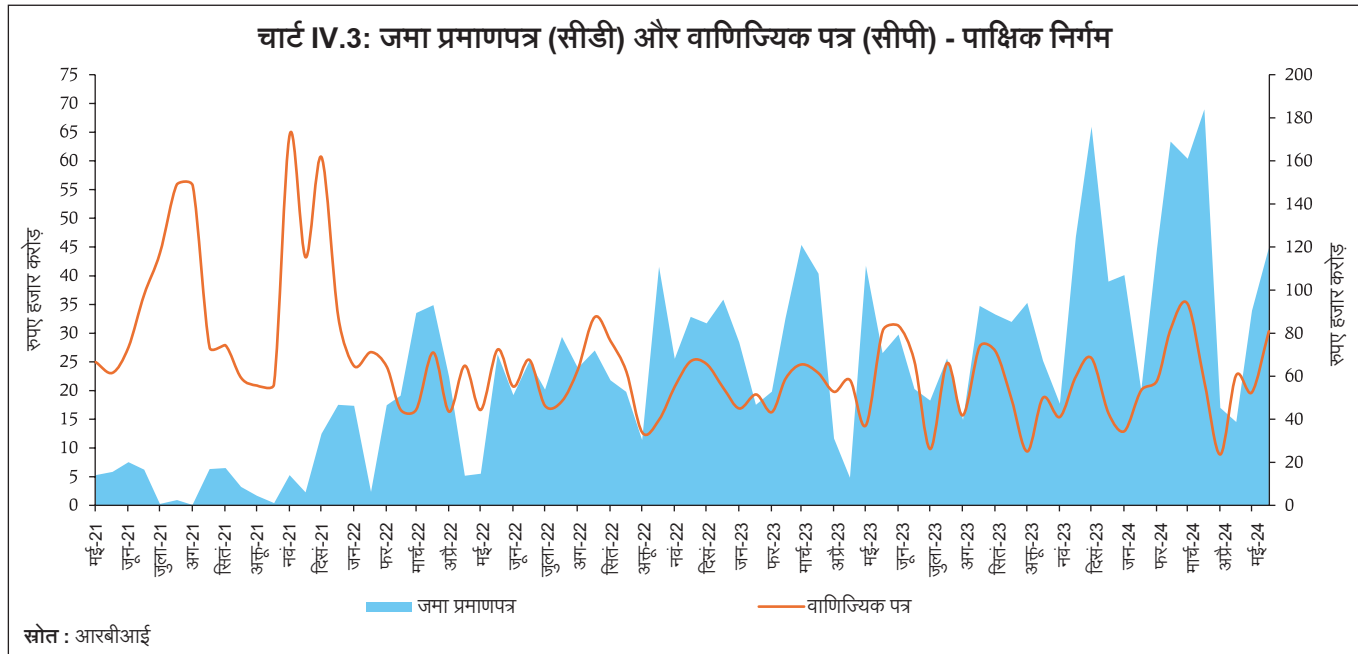
चलनिधि की गतिशीलता को दर्शाते हुए, भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - मोटे तौर पर एलएएफ कॉरिडोर के भीतर रहा और 16 मई से 12 जून 2024 के दौरान औसतन 6.57 प्रतिशत रहा, जो 16 अप्रैल - 15 मई 2024 के दौरान लगभग समान था (चार्ट IV.2ए)। मई के अंतिम सप्ताह और जून की शुरुआत में, चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ, जिससे डब्ल्यूएसीआर काफी नरम हो गया, सिवाय 31 मई को जब बैंकों ने रिज़र्व रखरखाव चक्र की शुरुआत में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव के लिए भारी मात्रा में उधार लिया था। संपार्श्विक खंड में दरें - त्रिपक्षीय और बाजार रेपो - डब्ल्यूएसीआर के अनुरूप आगे बढ़ीं। औसत आधार पर, 16 मई से 12 जून, 2024 के दौरान त्रिपक्षीय रेपो ने पॉलिसी दर से 2 आधार अंक (बीपीएस) नीचे कारोबार किया और बाजार रेपो दर ने नीतिगत रेपो दर पर कारोबार किया (चार्ट IV.2बी)।

सावधि मुद्रा बाजार खंड में, 3 महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) पर प्रतिफल और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर दरें कम हुईं, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर दरें 16 मई से 12 जून, 2024 के दौरान सख्त हुईं। 17 मई, 2024 को 2024-25 की पहली तिमाही के लिए कम अवधि के टी-बिल की आपूर्ति में कमी की घोषणा के फलस्वरूप 3 महीने के टी-बिल पर प्रतिफल में कमी आई। इसे दर्शाते हुए, मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने का सीपी माइनस 91-दिवसीय टी-बिल) 16 अप्रैल - 15 मई, 2024 के दौरान 79 बीपीएस से बढ़कर 16 मई - 12 जून, 2024 के दौरान 92 बीपीएस हो गया। हालाँकि, वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल रहीं, 16 अप्रैल - 15 मई, 2024 के दौरान सावधि स्प्रेड (10 वर्ष जी-सेक माइनस 91 दिन टी-बिल) 18 बीपीएस से कम होकर 14 बीपीएस हो गया।

प्राथमिक बाजार में, अप्रैल में सुस्ती के बाद मई में सीडी निर्गम के माध्यम से निधि जुटाने में तेजी आई। बैंकों ने 2024-25 (31 मई तक) के दौरान ₹1.25 लाख करोड़ मूल्य के सीडी जारी किए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹0.95 लाख करोड़ से अधिक है (चार्ट IV.3)। दूसरी ओर, 2024-25 (31 मई तक) के दौरान ₹2.18 लाख करोड़ मूल्य के सीपी जारी करना पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹2.29 लाख करोड़ से कम रहा।

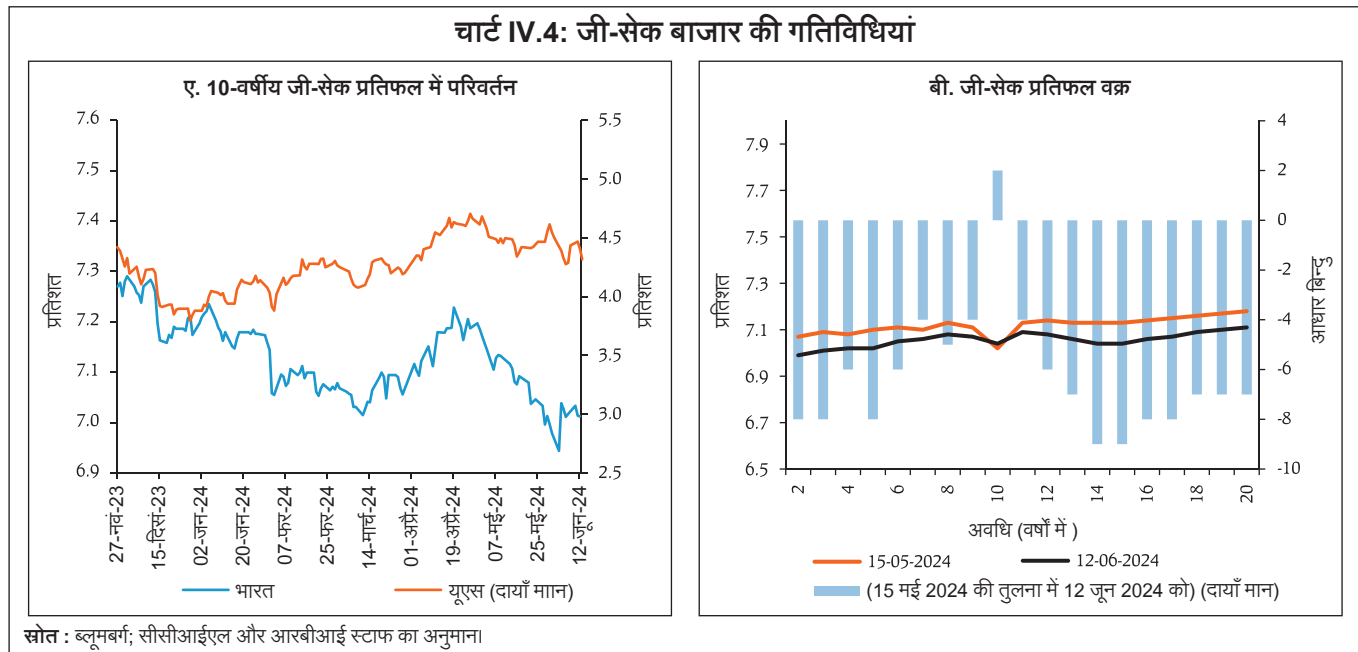
चार्ट IV.2: नीति कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दर





कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उम्मीद से अधिक लाभांश हस्तांतरण से सरकार को अतिरिक्त राजकोषीय स्थान मिलने, जून में वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय जी-सेक को शामिल करने पर सकारात्मक भावना और स्थिर रुपये के कारण 10 वर्षीय भारतीय बेंचमार्क (7.10 जीएस 2034) जी-सेक पर प्रतिफल

15 मई को 7.03 प्रतिशत से 12 जून को 7.01 प्रतिशत तक कम हो गया। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को 'स्थिर' से 'सकारात्मक' करने के कारण बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉण्ड प्रतिफल में और कमी आई (चार्ट IV.4ए)। 10-वर्ष की परिपक्वता (चार्ट IV.4बी) को छोड़कर, सभी आवधिक संरचनाओं के प्रतिफल में नरमी आई।



¹³ रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 22 मई को लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹2.11 लाख करोड़ हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र को और मजबूत बनाने के लिए, 2023-24 के लिए आकस्मिक रिज़र्व बफर (सीआरबी) के तहत जोखिम प्रावधान को 2022-23 के 6.0 प्रतिशत से बढ़ाकर तुलन पत्र के 6.50 प्रतिशत पर तय किया गया।

भारत सरकार ने मई और जून 2024 की शुरुआत में कुल ₹2.3 लाख करोड़ की राशि के लिए पाँच वापसी खरीद नीलामियों की घोषणा की। वापसी खरीद प्रस्ताव की घोषणा सरकार की बेहतर नकदी स्थिति की पृष्ठभूमि में की गई थी और इसका उद्देश्य समय से पहले अपने कुछ ऋणों को चुकाना था ताकि ऋण का सक्रिय रूप से प्रबंधन किया जा सके। हालाँकि, वापसी खरीद प्रस्ताव के प्रति प्रतिक्रिया धीमी रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹2.3 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के मुकाबले कुल ₹0.3 लाख करोड़ के प्रस्ताव स्वीकार किए। वापसी खरीद एक सक्रिय ऋण समेकन रणनीति का हिस्सा है जिसका चलनिधि पर प्रभाव होता है लेकिन इसे चलनिधि प्रबंधन संचालन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

16 मई से 12 जून, 2024 के दौरान विविध परिपक्वता प्रोफाइल और रेटिंग में कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल में कमी आई, जबकि जोखिम प्रीमियम में वृद्धि हुई (सारणी IV.1)। 5-वर्षीय एए रेटेड कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल में कमी आई, जो 5-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है।

सीआरआर में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित निधि (आरएम) में 7 जून 2024 को 7.5 प्रतिशत (वर्ष

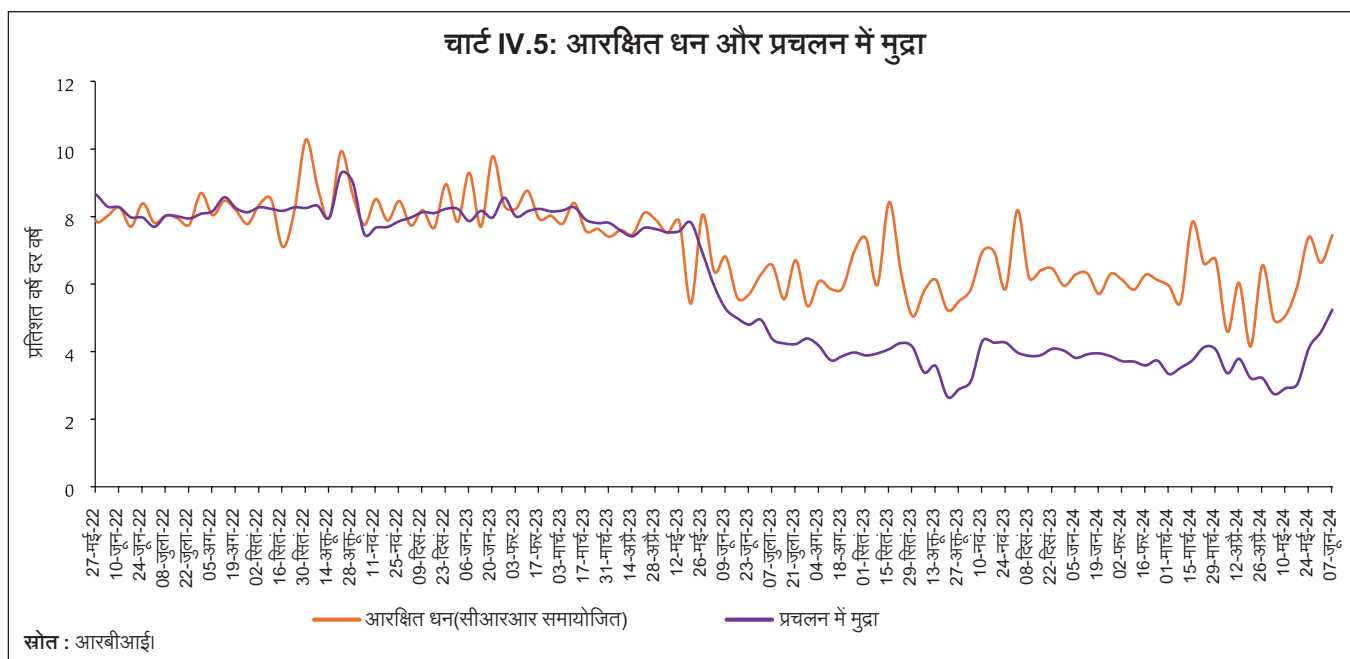
सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार बिन्दु) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 अप्रैल 2024-15 मई 2024	16 मई 2024-12 जून 2024	अंतर	16 अप्रैल 2024-15 मई 2024	16 मई 2024-12 जून 2024	अंतर
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एए (1-वर्ष)	7.82	7.86	4	65	72	7
(ii) एए (3-वर्ष)	7.99	7.91	-8	71	75	4
(iii) एए (5-वर्ष)	7.91	7.82	-9	61	65	4
(iv) एए (3-वर्ष)	8.59	8.56	-3	131	139	8
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.17	12.16	-1	489	499	10

टिप्पणी : प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत : फीमडा; और ब्लूमबर्ग।

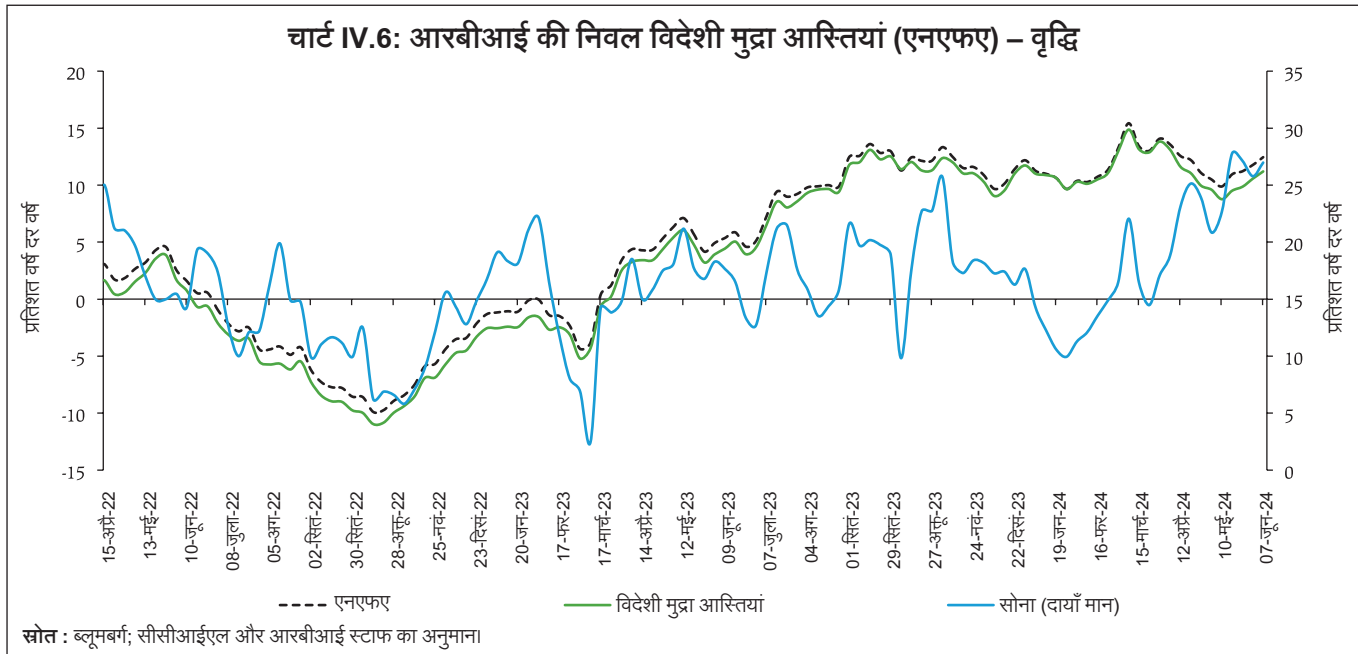
दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक साल पहले 6.8 प्रतिशत) [चार्ट IV.5]। आरएम के सबसे बड़े घटक, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि 17 मई 2024 को 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 7 जून 2024 को 5.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई, जो 2000 रुपये के बैंक नोटों की वापसी जिसमें – 97.82 प्रतिशत बैंकिंग प्रणाली में ज्यादातर जमा के रूप में वापस आ जाने (31 मई 2024 तक) के आधार प्रभाव के कारण है¹⁴।

चार्ट IV.5: आरक्षित धन और प्रचलन में मुद्रा



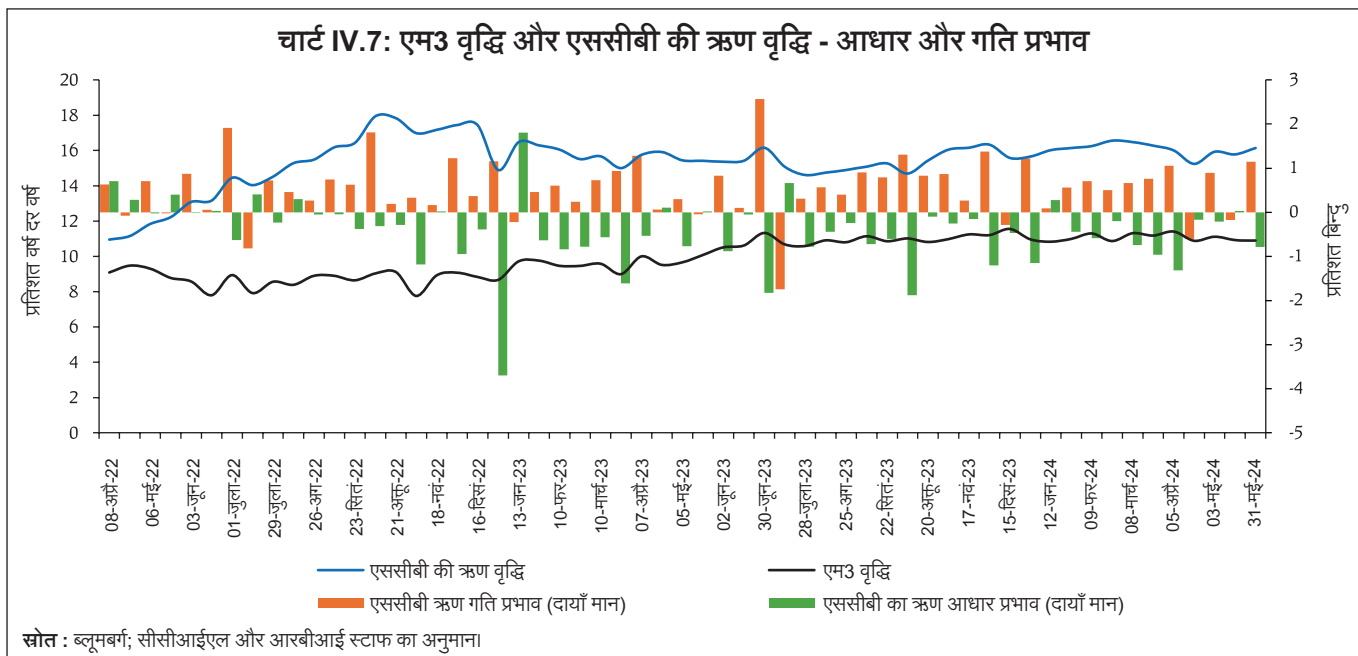
स्रोत : आरबीआई

¹⁴ 19 मई 2023 को घोषित किया गया।

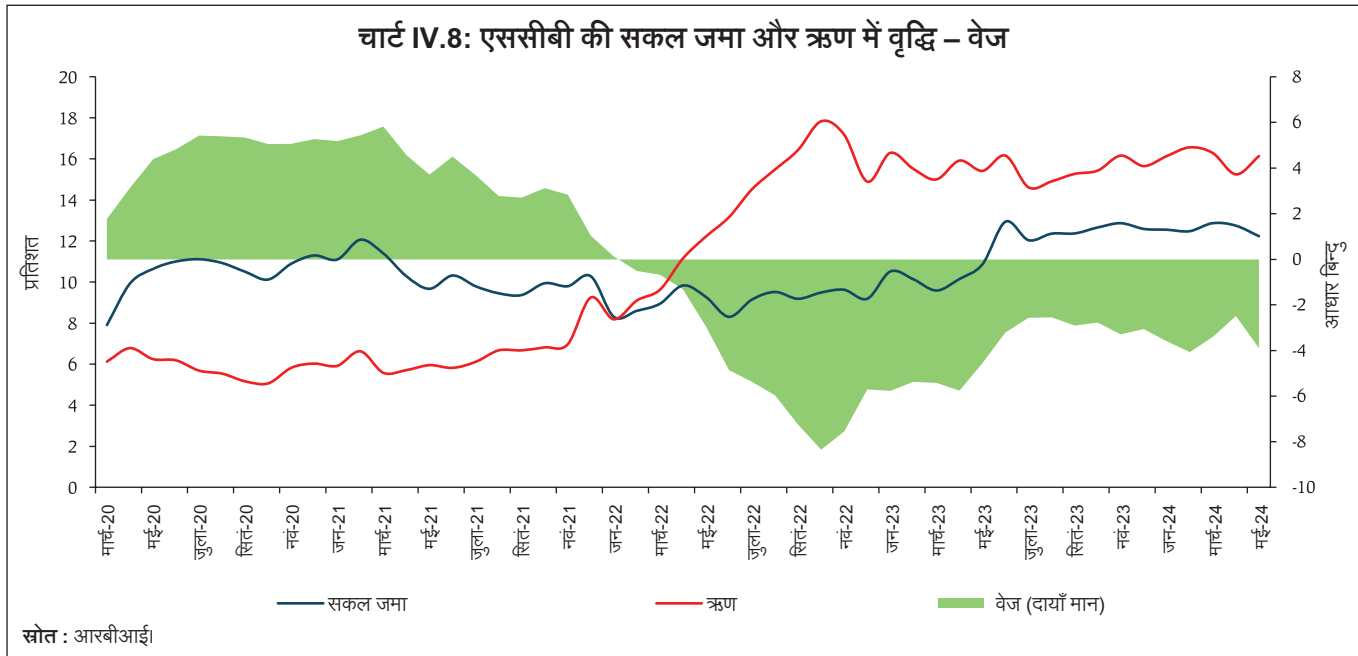


स्रोत पक्ष (आस्तियों) पर, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) शामिल हैं। जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा) में वृद्धि जो मार्च 2024 से घट रही थी, मई 2024 के दौरान थोड़ी बढ़ गई; एनएफए के अन्य प्रमुख घटक सोने ने फरवरी 2024 से दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है (चार्ट IV.6)।

31 मई 2024 को मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 10.9 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 10.5 प्रतिशत)।¹⁵ बैंकों के पास कुल जमाराशि, जो एम₃ का सबसे बड़ा घटक है, में 11.7 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 11.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 31 मई, 2024 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 16.1 प्रतिशत रही (एक वर्ष पहले 15.4 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]।



¹⁵ किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई 2023 से प्रभावी)।



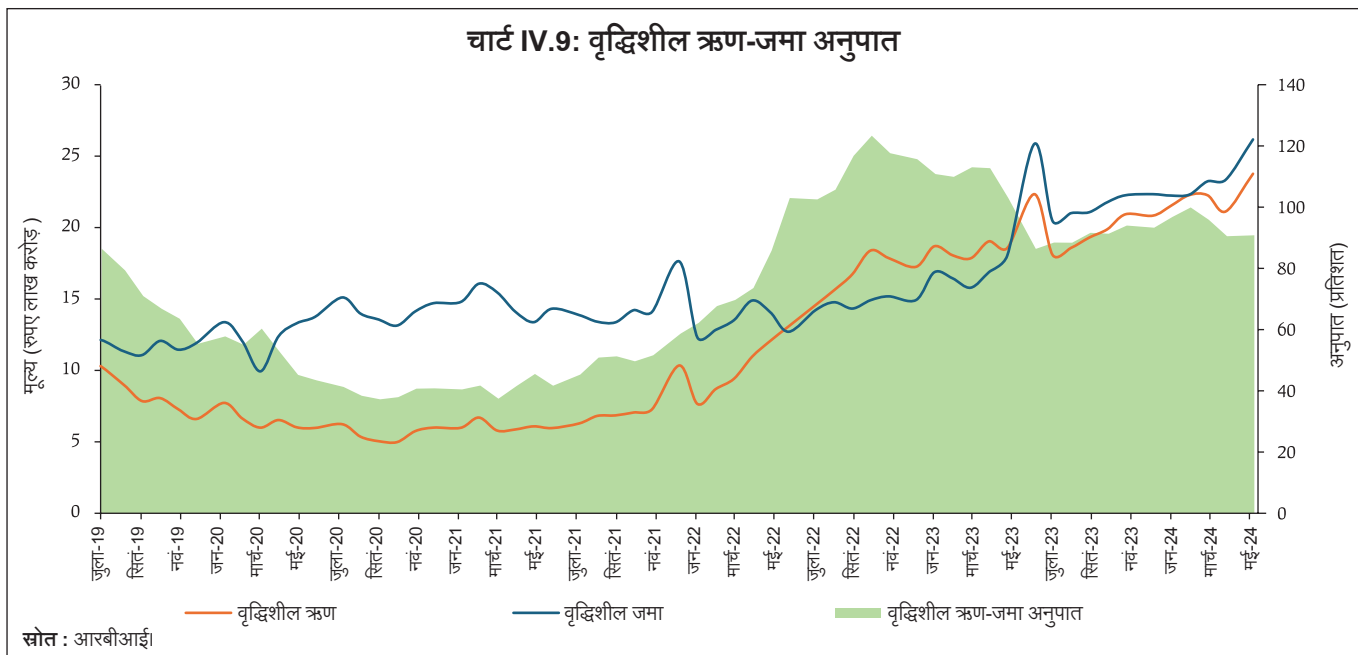
एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर), जिसमें ₹ 2000 के बैंक नोटों की वापसी के कारण वृद्धि दर्ज की गई, मई 2024 में दोहरे अंकों में रही (चार्ट IV.8)।

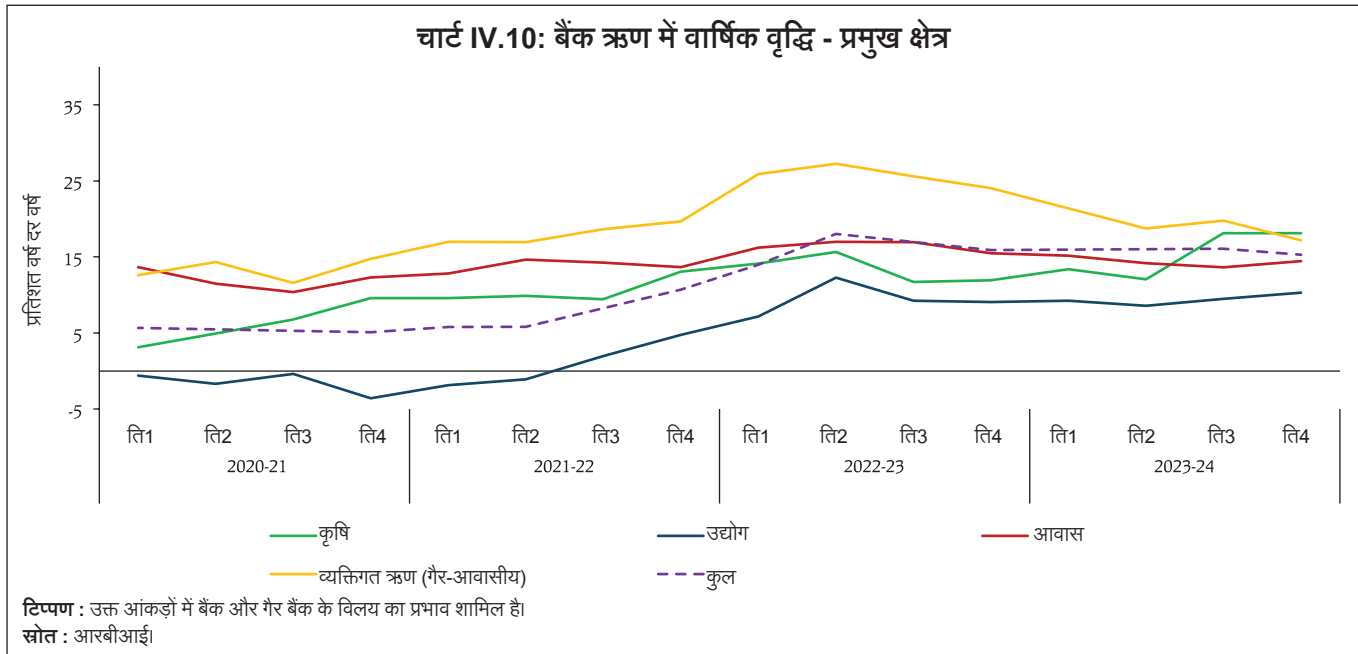
2024 तक प्रणालीगत स्तर पर वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 90.8 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.9)।

सीआरआर और वैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए वैधानिक अपेक्षाएँ क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18.0

प्रतिशत होने के साथ, 31 मई 2024 तक ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली के पास लगभग 77 प्रतिशत जमा उपलब्ध थी। जमा आधार को सीडी निर्गम द्वारा समर्थित किया गया था।

2023-24 की चौथी तिमाही में, कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण ने महामारी के बाद से सबसे मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज की। पिछली सात तिमाहियों के दौरान उद्योग के लिए मजबूत ऋण वृद्धि देखी



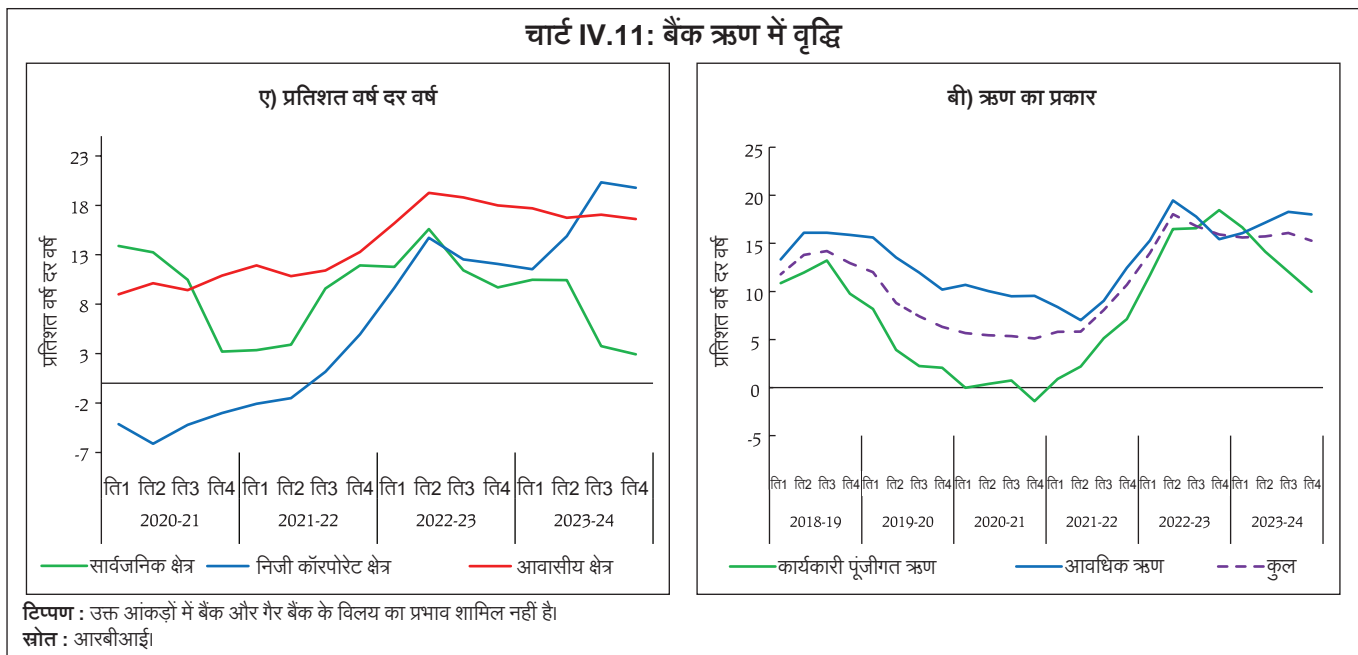


गई, साथ ही आवास और गैर-आवासीय व्यक्तिगत ऋण क्षेत्रों में बैंक ऋण वृद्धि लगातार दोहरे अंकों में रही। (चार्ट IV.10)।

निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की ऋण वृद्धि 2023-24 की दूसरी छमाही में उत्साहजनक रही, जो संभवतः निजी क्षेत्र द्वारा क्षमता वृद्धि की ओर इशारा करती है (चार्ट IV.11ए)। 2022-23 की दूसरी तिमाही से कार्यशील पूंजी ऋण में गिरावट आ

रही है, जो निजी कॉरपोरेट द्वारा नकदी प्रवाह के प्रभावी प्रबंधन का संकेत देते हैं (चार्ट IV.11बी)।

मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में संचयी 250 बीपीएस की बढ़ोतरी के प्रतिक्रिया स्वरूप, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंकड बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को उसी परिमाण से ऊपर की ओर संशोधित किया है। मई 2022 से मई 2024



सारणी IV.2: रेपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार बिन्दुओं में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर (बीपीएस)	सावधि जमा दरें		उधार दरें			
		डबल्यूएडी टीडीआर - नया जमा	डबल्यूएडी टीडीआर (बकाया जमा)	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डबल्यूएएलआर -नया रुपया उधार	डबल्यूएएलआर -बकाया रुपया उधार
ढील वाली अवधि फरवरी 2019- मार्च 2022	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्ती वाली अवधि मई -22 से अप्रैल 2024	+250	245	188	250*	175*	204	111

टिप्पण : ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।

* : ईबीएलआर और एमसीएलआर पर डेटा मई 2024 से संबंधित है।

डबल्यूएएलआर : भारत औसत उधार दर। डबल्यूएडीटीडीआर : भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर;

एमसीएलआर : निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर।

स्रोत : आरबीआई।

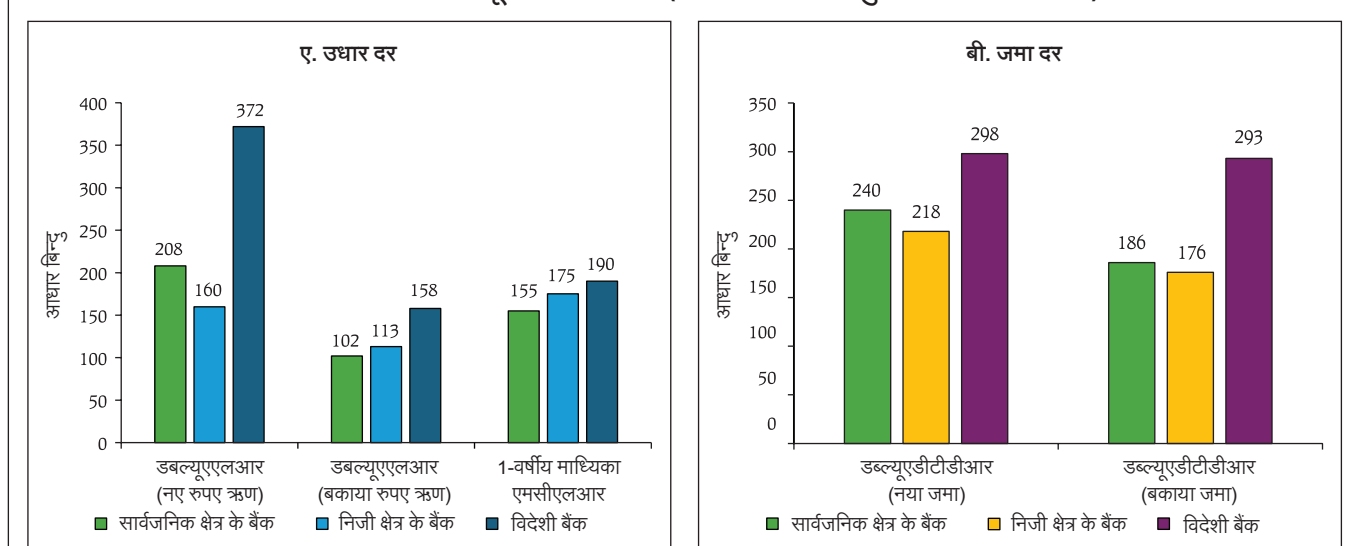
के दौरान 1-वर्षीय औसत सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में 175 बीपीएस की वृद्धि हुई। नतीजतन, नए रुपये और बकाया रुपये के ऋणों पर भारत औसत उधार दर (डबल्यूएएलआर) मई 2022 से अप्रैल 2024 के दौरान क्रमशः 204 बीपीएस और 111 बीपीएस बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान नई जमाराशियों और बकाया जमाराशियों पर भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 245 बीपीएस और 188 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

नये रुपया ऋणों पर डबल्यूएएलआर और नये जमा पर डबल्यूएडीटीडीआर का संचरण निजी बैंकों की तुलना में

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिक था, जबकि बकाया ऋणों पर डबल्यूएएलआर का संचरण निजी बैंकों के लिए अधिक था (चार्ट IV.12)।

नीतिगत दरों का उधार और जमा दरों पर प्रभाव दर्शाते हुए, उच्च ब्याज दर वाले बैंक ऋण और जमा की हिस्सेदारी मार्च 2022 और मार्च 2024 के बीच लगातार बढ़ी है (चार्ट IV.13)। साथ ही, अन्य प्रकार की जमाराशियों की तुलना में बचत जमाराशियों की वृद्धि में कुछ नरमी देखी गई (चार्ट IV.14)।

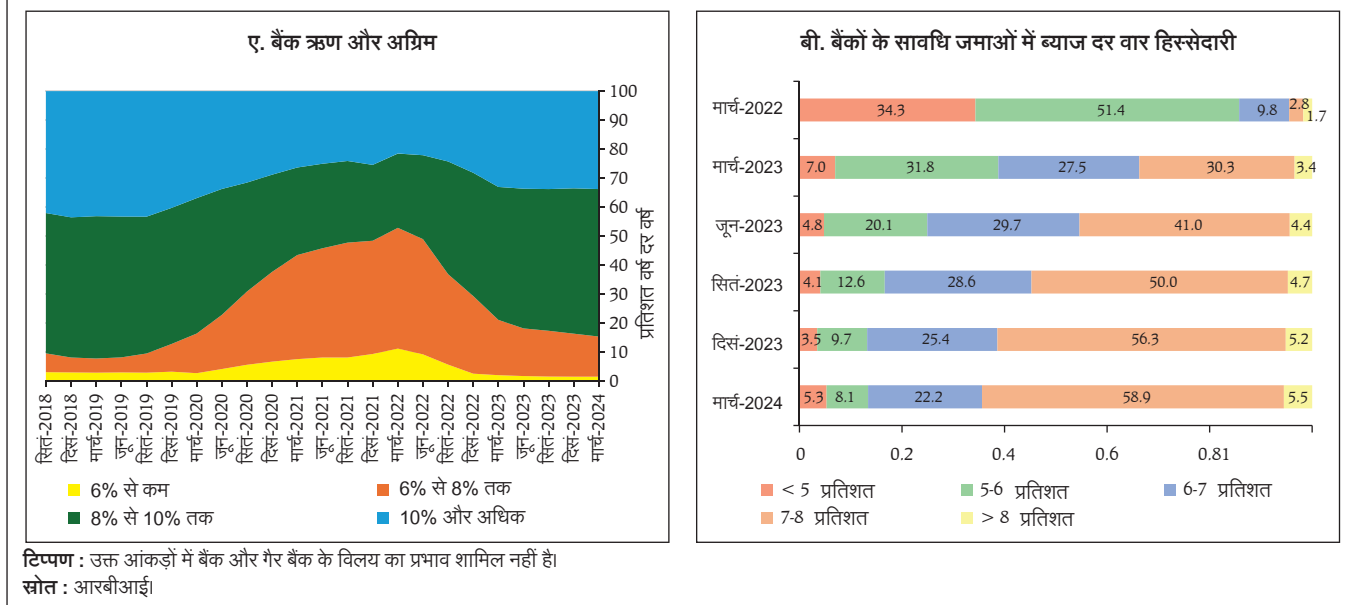
चार्ट IV .12: बैंक समूह वार संचरण (अप्रैल 2024 की तुलना में मई 2024 में)



टिप्पणी : 1-वर्षीय एमसीएलआर से संबंधित आंकड़े मई 2024 तक की अवधि के लिए हैं।

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV .13: ब्याज दर के आधार पर बैंक ऋणों और जमाओं का वितरण



विनिर्माण कंपनियों में कॉरपोरेट लीवरेज, जैसा कि उनके ऋण-से-इक्विटी अनुपात ¹⁶ में परिलक्षित होता है, में गिरावट जारी रही क्योंकि कंपनियों ने अपने उच्च लाभ को पूंजीकृत किया (चार्ट IV.15ए)। वैसे तो कुल आस्तियों में अचल संपत्तियों की हिस्सेदारी मोटे तौर पर स्थिर रही, लेकिन बकाया अचल संपत्तियों में 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान 7.9 प्रतिशत

(वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट IV.15बी)। पूंजीगत व्यय और अन्य गैर-वर्तमान निवेशों के लिए निधियों का एक प्रमुख स्रोत प्रतिधारित उपार्जन बनी रही (चार्ट IV.15सी और IV.15डी)।

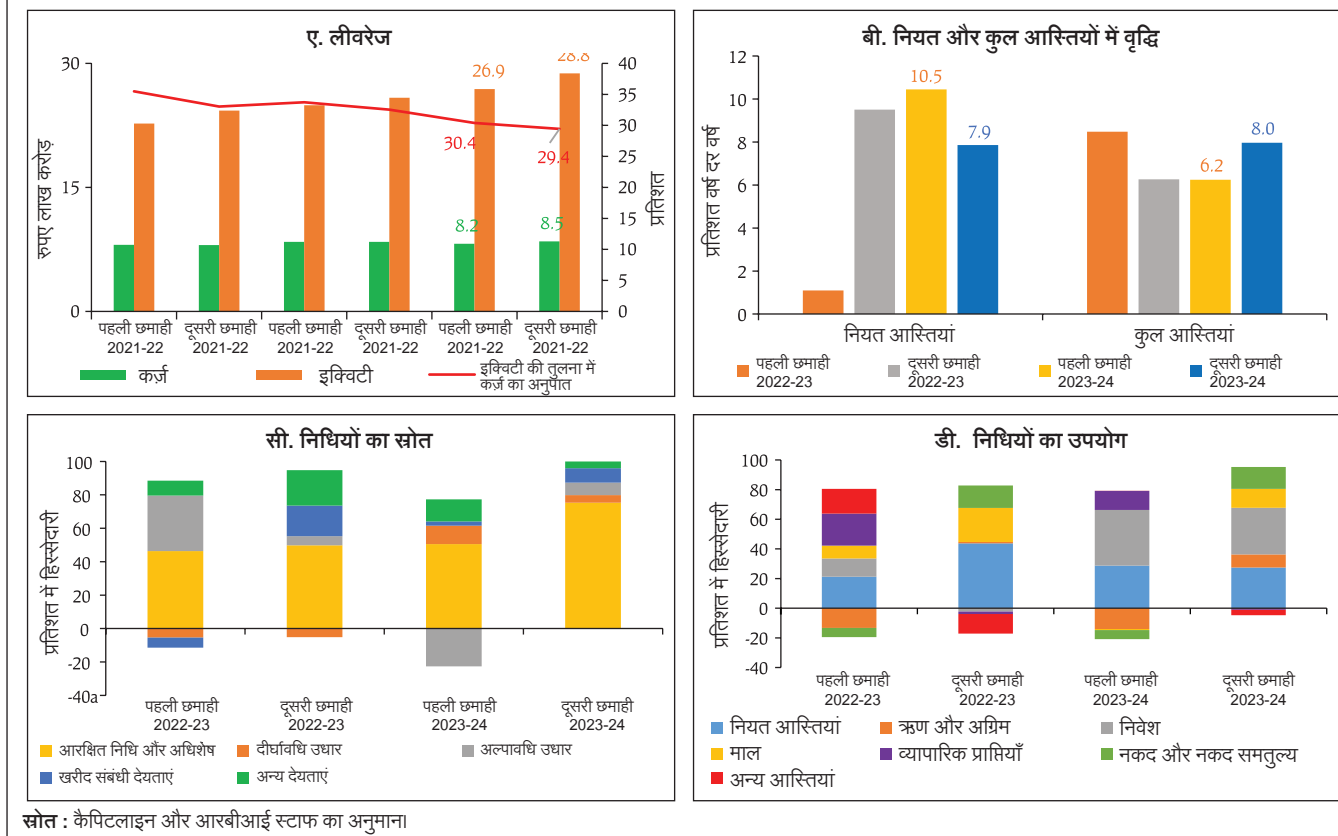
मई-जून 2024 के दौरान अब तक भारतीय इक्विटी बाजारों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। मई 2024 की पहली छमाही में घाटा दर्ज करने के बाद, रिज़र्व बैंक द्वारा रिकॉर्ड लाभांश

चार्ट IV .14: सकल जमा राशि में वार्षिक वृद्धि – जमा का प्रकार



¹⁶ वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान, 1,526 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के संक्षिप्त तुलन-पत्र पर आधारित।

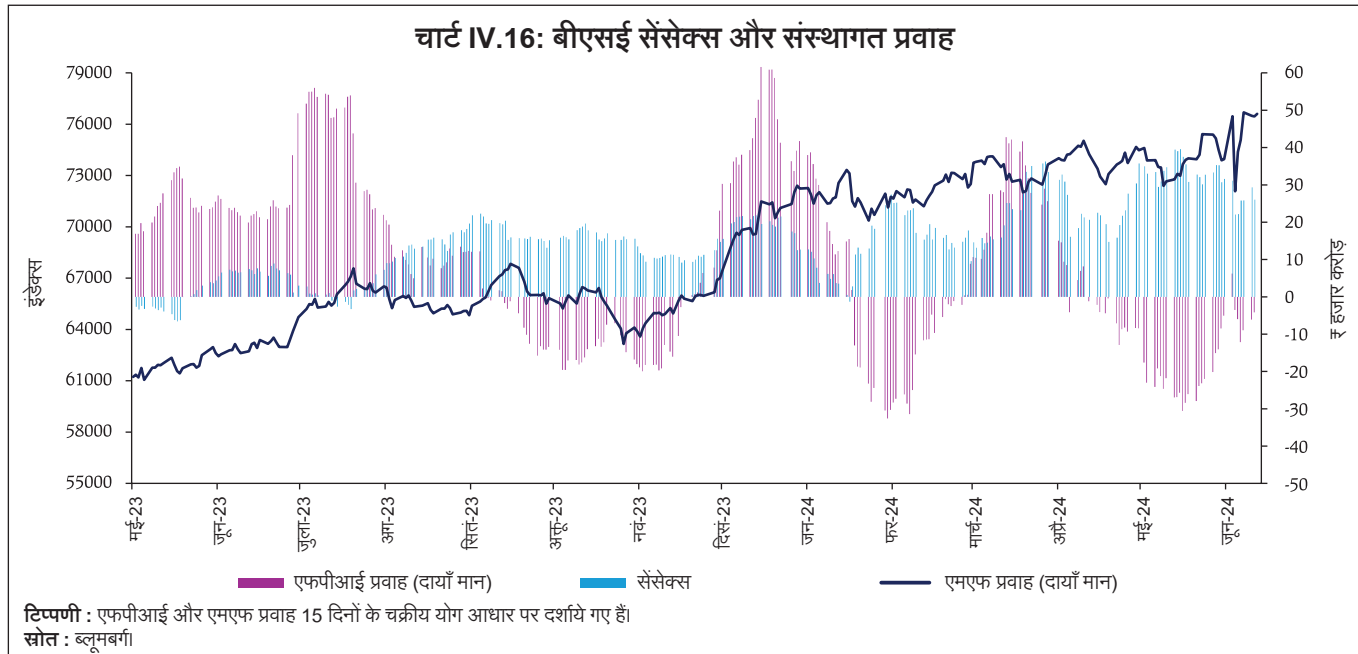
चार्ट IV.15: कुल जमा में वार्षिक वृद्धि - जमा का प्रकार



हस्तांतरण के बाद बाजार में तेजी आई। भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पहली बार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। इसके बाद, कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच मई 2024 के अंतिम सप्ताह में बाजारों में गिरावट आई, लेकिन जून 2024 की शुरुआत सकारात्मक रही, एग्जिट पोल और उम्मीद से बेहतर 2023-24 की चौथी तिमाही में घरेलू जीडीपी डेटा के बाद यह नए शिखर पर पहुंच गई। हालांकि, लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद बाजारों में तेज गिरावट दर्ज की गई, लेकिन नई सरकार के कार्यभार संभालने के साथ ही नीति स्थिरता की बढ़ती उम्मीदों के बीच बाद में इसमें सुधार हुआ (चार्ट IV.16)। कुल मिलाकर, बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स अप्रैल 2024 के अंत से 3.4 प्रतिशत बढ़कर 14 जून 2024 को 76,693 पर बंद हुआ। भारत में बाजार में उतार-चढ़ाव, जैसा कि VIX द्वारा दर्ज किया गया है, 4 जून 2024 को दोगुना से अधिक बढ़कर 26.8 हो गया, लेकिन बाद में 14 जून 2024 को घटकर 12.82 तक आ गया। म्यूचुअल फंड ने मई-जून 2024 में अब

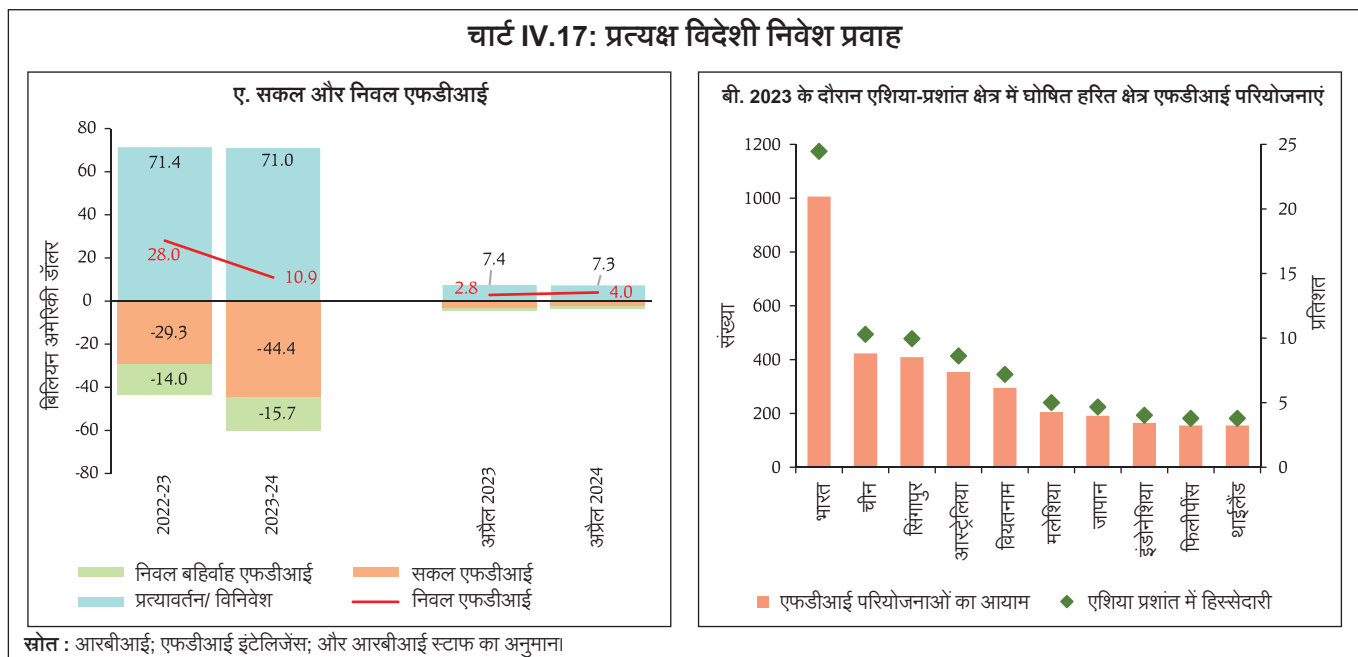
तक 60,048 करोड़ रुपये की निवल खरीदारी की, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 33,272 करोड़ रुपये की निवल बिक्री की।

सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अप्रैल 2024 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (एक साल पहले 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर मजबूत रहा [चार्ट IV.17ए]। विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, बिजली और अन्य ऊर्जा, और कंप्यूटर सेवा क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। प्रमुख स्रोत देशों में सिंगापुर, मॉरीशस, साइप्रस, अमेरिका और नीदरलैंड शामिल थे, जिन्होंने अंतर्वाह में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। भारत द्वारा प्रत्यावर्तन और जावक एफडीआई में संयम के कारण निवल एफडीआई (निवल आवक एफडीआई घटा निवल जावक एफडीआई) अप्रैल 2024 में एक साल पहले के 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।



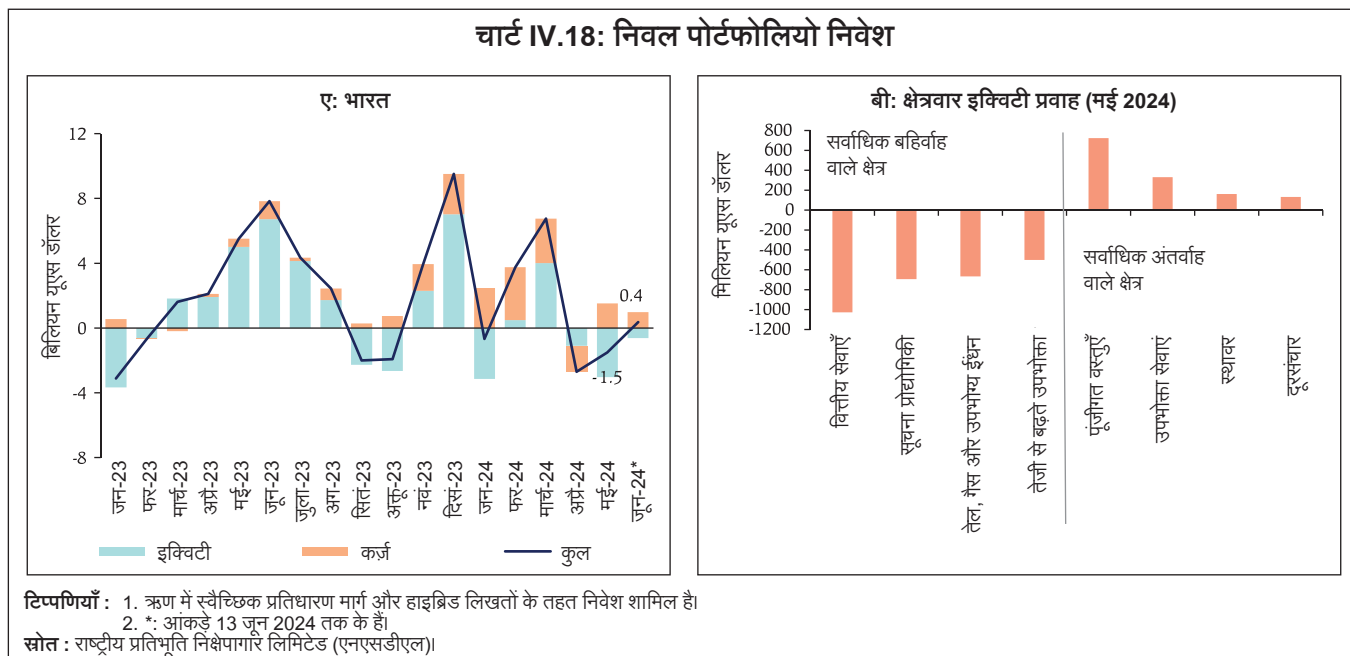
वैश्विक एफडीआई प्रवाह एक संरचनात्मक बदलाव से गुजर रहा है, जिसे भू-राजनीति, डिजिटलीकरण और हरित ऊर्जा संक्रमण की ताकतों द्वारा नया रूप दिया गया है। एफडीआई इंटेलिजेंस¹⁷ के अनुसार, 2023 में वैश्विक स्तर पर 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की लगभग 16,427 ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। भारत ने एफडीआई

परियोजनाओं (एपीएसी में 24 प्रतिशत की हिस्सेदारी) और एफडीआई पूंजी निवेश (एपीएसी में 19 प्रतिशत की हिस्सेदारी) के मामले में एशिया-प्रशांत (एपीएसी) के भीतर एक आकर्षक गंतव्य देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी [चार्ट IV.17बी]। उद्योगों में, नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी, संचार और अर्ध चालक जैसे पूंजी गहन क्षेत्र 2023 में एफडीआई परिदृश्य पर हावी रहे।



¹⁷ फाइनैशियल टाइम्स का एक विशेषज्ञ प्रभाग जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित सेवाओं की व्यापक पेशकश करता है।

चार्ट IV.18: निवल पोर्टफोलियो निवेश



भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मई 2024 में लगातार दो महीनों तक ऋणात्मक रहा। मई 2024 में निवल एफपीआई बहिर्वाह 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें इक्विटी खंड की बहुलता रही (चार्ट IV.18ए)। अधिकांश ईएमई के अनुरूप, इक्विटी ने 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया। हालांकि, 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल प्रवाह के साथ, ऋण खंड ने अप्रैल 2024 के महीने को छोड़कर, अप्रैल 2023 से अपने धनात्मक प्रक्षेपवक्र को बनाए रखा। इक्विटी के भीतर, वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), और तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन ने सबसे अधिक बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता सेवाओं और स्थावर संपदा क्षेत्रों को मई 2024 के दौरान सबसे अधिक अंतर्वाह प्राप्त हुआ (चार्ट IV.18बी)।

अप्रैल 2024 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पूंजीकरण धीमा होकर 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (मार्च 2024 में 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अप्रैल 2023 में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर)। 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूलधन पुनर्भुगतान के समायोजन के बाद, निवल ईसीबी प्रवाह लगातार चौथे महीने धनात्मक रहा (चार्ट IV.19ए)। अप्रैल 2024 में जुटाए गए ईसीबी का उद्देश्य मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी की

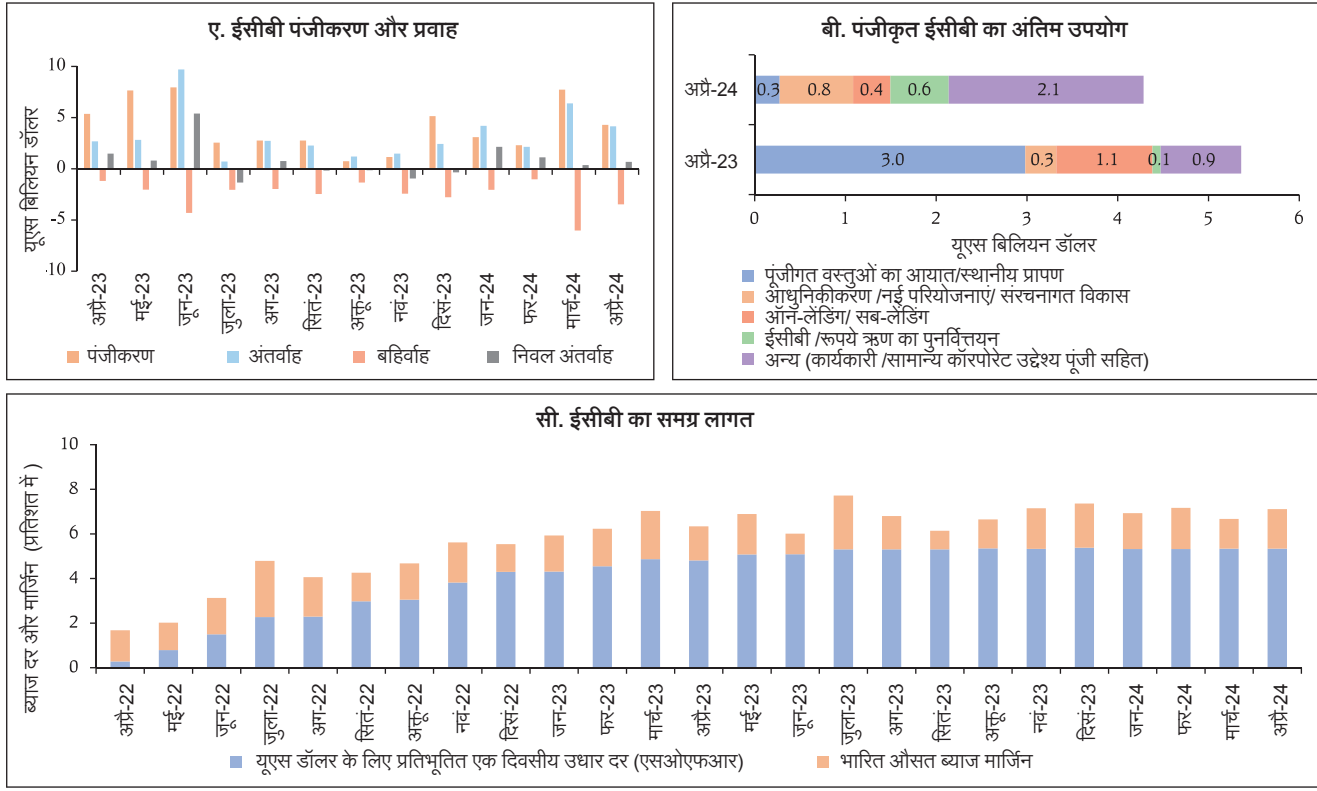
जरूरतों को पूरा करना था (चार्ट IV.19बी)। उनके पास अधिक भारित औसत ब्याज मार्जिन भी था (चार्ट IV.19सी)।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7 जून, 2024 को बढ़कर 655.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2024-25 के लिए अनुमानित लगभग 11 महीनों के आयात के बराबर है और दिसंबर 2023 के अंत में कुल बकाया विदेशी ऋण का 100 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट IV.20ए)। प्रमुख विदेशी मुद्रा रखने वाले देशों में, भारत ने 33.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम भंडार जोड़े, जो कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान 5.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट IV.20बी)।

भारतीय रुपया (आईएनआर) सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक रहा और मई 2024 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसमें 0.02 प्रतिशत (मासिक) की मामूली वृद्धि हुई (चार्ट IV.21)।

मई 2024 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में भारतीय रुपया 1.2 प्रतिशत (मासिक) बढ़ा, जिसे सकारात्मक सापेक्ष मूल्य अंतर और नाममात्र प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपया की वृद्धि का समर्थन प्राप्त हुआ (चार्ट IV.22)।

चार्ट IV.19: बाह्य वाणिज्यिक उधार



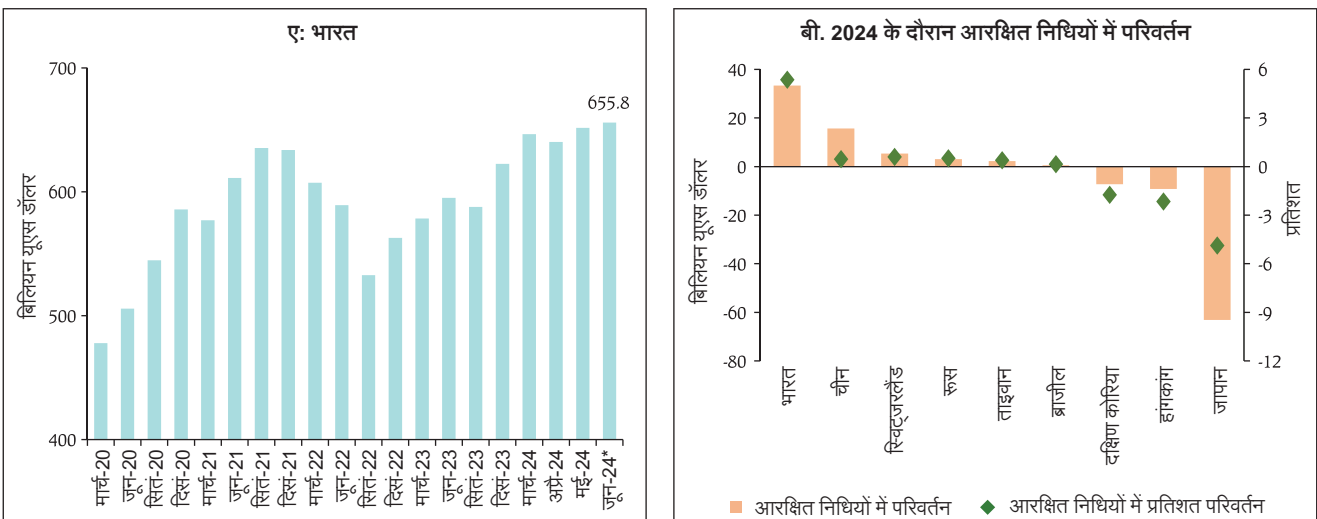
स्रोत : फॉर्म ईसीबी, आरबीआई

भुगतान प्रणालियाँ

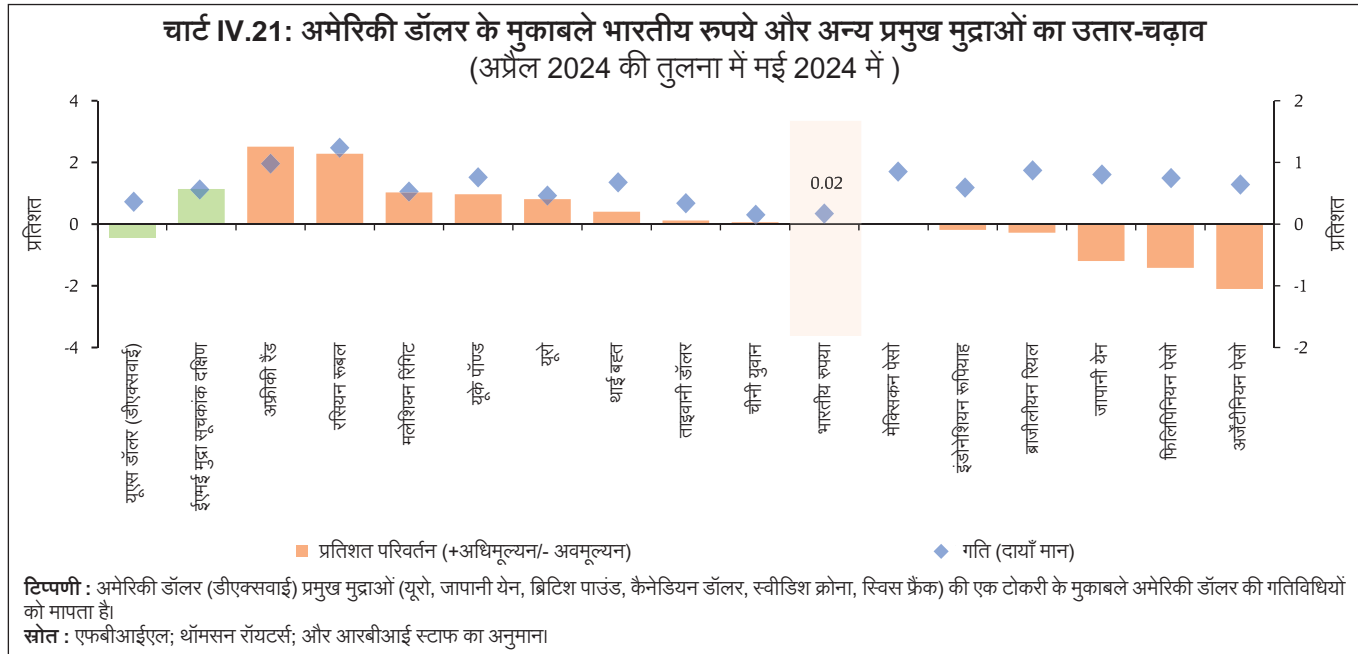
मई 2024 में सभी प्रमुख श्रेणियों में डिजिटल भुगतान प्रणाली संकेतकों ने विकास (वर्ष-दर-वर्ष) बनाए रखा, जिसका

नेतृत्व ज्यादातर खुदरा क्षेत्र ने किया, जिसमें एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) शामिल हैं

चार्ट IV.20: विदेशी मुद्रा भंडार

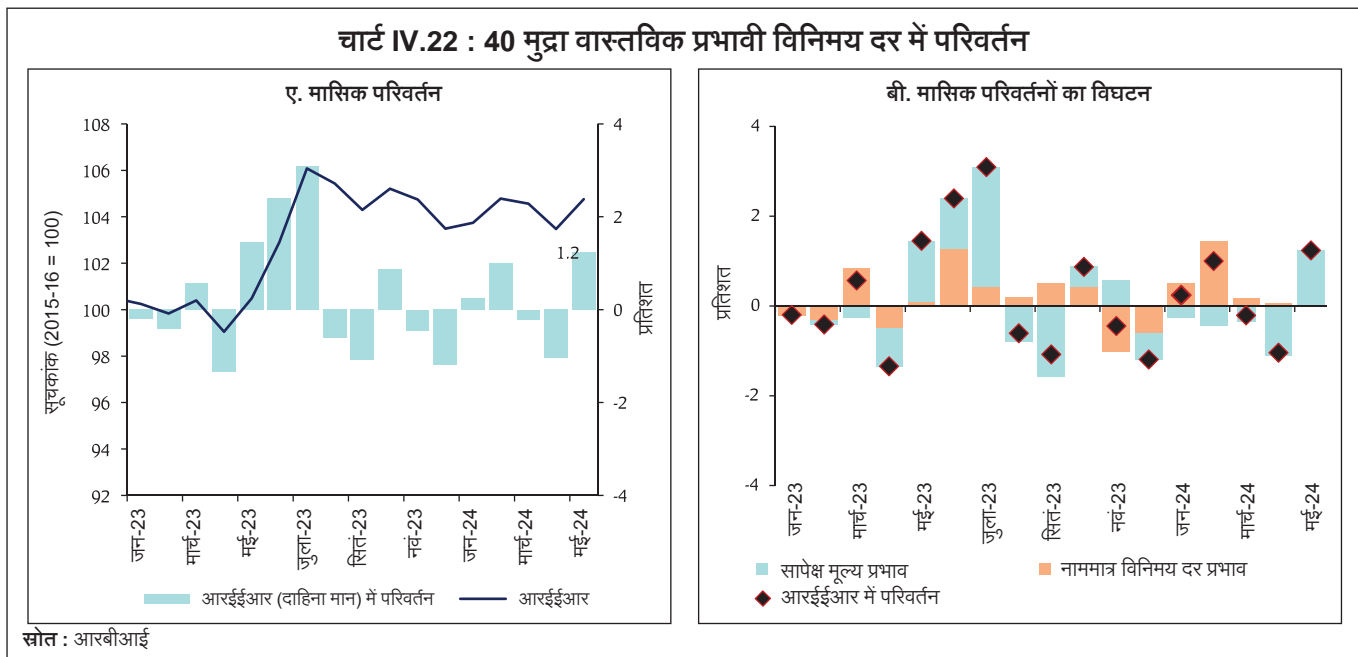


टिप्पणियाँ : 1. *: 7 जून 2024 का डेटा।
 2. भारत और रूस के लिए डेटा 7 जून 2024, स्विट्जरलैंड और हांगकांग के लिए अप्रैल के अंत और शेष देशों के लिए मई के अंत का है।
 स्रोत : आरबीआई; और संबंधित केंद्रीय बैंक वेबसाइटें।



[सारणी IV.3] यूपीआई ने मई 2024 में रिकॉर्ड 14.04 बिलियन लेनदेन संसाधित किए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की पहुंच ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विस्तारित होती रही। बीबीपीएस ने मई 2024 के दौरान लेनदेन में बहुत अधिक विस्तार किया, क्योंकि समय-सीमा अर्थात् 30 जून, 2024¹⁸ के करीब आने के साथ कुछ नई श्रेणियों के बिलर्स को सक्षम करने के साथ-साथ मौजूदा और नई श्रेणियों

(ई-चालान, थोक बिजली भुगतान, कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड, आदि) में ग्राहकों के लिए बिल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) 1.1 संवर्धन के साथ एकीकृत किया गया। अन्य तरीकों के अलावा, एनईएफटी में तीव्र दर (वर्ष-दर-वर्ष) से विस्तार हुआ, जबकि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) की वृद्धि मई 2024 में मात्रा के संदर्भ में धीमी हो गई।



¹⁸ बीबीपीएस परिपत्रा 31 मई 2024।

सारणी IV.3 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

(वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन मात्रा				लेनदेन मूल्य			
	अप्रैल-23	अप्रैल-24	मई-23	मई-24	अप्रैल-23	अप्रैल-24	मई-23	मई-24
आरटीजीएस	3.2	16.9	12.6	13.3	7.0	21.5	15.2	17.9
एनईएफटी	29.1	45.9	28.4	52.5	10.5	13.4	18.8	14.3
यूपीआई	58.7	50.1	58.3	49.1	43.9	38.8	43.2	37.3
आईएमपीएस	5.1	11.0	3.5	11.2	17.2	13.7	16.6	14.9
एनएसीएच	-3.7	50.5	-14.3	12.7	18.4	23.7	19.5	20.7
एनईटीसी	14.9	7.6	17.4	3.7	22.1	8.6	24.3	8.7
बीबीपीएस	33.5	45.1	28.4	47.8	51.2	107.5	44.8	114.8

टिप्पणी : आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान; एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफेस; आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा; एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; और बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।

स्रोत : आरबीआई।

अप्रैल 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, क्रेडिट कार्ड (18.5 प्रतिशत), बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या (12.8 प्रतिशत), भारत त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड (11.5 प्रतिशत) और यूपीआई क्यूआर कोड (22.5 प्रतिशत) की संख्या में (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि हुई, जिससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला। डिजिटल बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ने तीन महत्वपूर्ण पहलों¹⁹ की शुरुआत की: प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक तथा एमटेक रिपोजिटरी। प्रवाह पोर्टल विभिन्न विनियामकीय अनुमोदनों के लिए कुशल तरीके से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है; रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप खुदरा निवेशकों को जी-सेक की ट्रेडिंग के लिए रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का एक सुविधाजनक और आसान तरीका प्रदान करेगा; और अंत में, फिनटेक तथा एमटेक रिपोजिटरी भारतीय फिनटेक क्षेत्र और विनियमित संस्थाओं द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आदि) को अपनाने पर डेटा एकत्र करेंगे, ताकि उपयुक्त नीति दृष्टिकोण तैयार करने में मदद मिल सके।

फिनटेक के लाभों को अनुकूलित करने और वित्तीय प्रणाली के लिए उनके द्वारा उत्पन्न विशेष जोखिमों को कम करने के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास में, रिजर्व बैंक ने फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियमन को प्रोत्साहित किया और 30 मई, 2024

को 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-नियामक संगठन(ओं) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा' (एसआरओ-एफटी रूपरेखा) जारी की।²⁰ यह रूपरेखा एसआरओ-एफटी(ओं) को मान्यता देने के लिए विशेषताओं और प्रक्रिया एवं उनके व्यापक कार्यों, अभिशासन मानकों, पात्रता मानदंडों और अपेक्षाओं को रेखांकित करती है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य²¹ में, रिजर्व बैंक ने भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है; आवर्ती भुगतानों को शामिल करना (बिना किसी निश्चित आवधिकता के), उदाहरण के लिए, फास्टैग में शेष राशि की पुनः पूर्ति, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी), और डिजिटल भुगतान की आसानी को बढ़ाने के लिए ई-मैंडेट ढांचे के तहत स्वतः पुनः पूर्ति सुविधा के साथ यूपीआई लाइट वॉलेट। रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता को प्राथमिकता देने के लिए दो थीम अर्थात् 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग अनुकूल होना' के साथ वैश्विक हैकथॉन " हार्बिंगर 2024 - परिवर्तन के लिए नवाचार" के शुभारंभ की भी घोषणा की। वैश्विक डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के संबंध में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने पेरू में यूपीआई जैसी वास्तविक समय भुगतान

²⁰ आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति 30 मई 2024।

²¹ आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति 7 जून 2024।

¹⁹ आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति 28 मई 2024।

प्रणाली को सक्षम करने के लिए पेरू के केंद्रीय रिज़र्व बैंक (बीसीआरपी) के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिससे पेरू विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त यूपीआई तकनीक को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया।

V. निष्कर्ष

इन वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों के बीच, रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वर्ष 2024-25 के लिए अपनी दूसरी द्विमासिक बैठक 5-7 जून, 2024 को की। इसने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया और वृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने के लिए समायोजन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने के अपने रुख को दोहराया।

समिति के आकलन में, घरेलू आर्थिक गतिविधि सुदृढ़ है। गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक विनिर्माण और सेवाओं में निरंतर गति को दर्शाते हैं। सामान्य से अधिक एसडब्ल्यूएम की उम्मीदों और अपने निर्धारित समय से पहले वास्तविक भूस्खलन के साथ कृषि की संभावनाएं उज्ज्वल हो रही हैं। यह ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने और बदले में निजी खपत को बढ़ावा देने के लिए अच्छा संकेत है। एमपीसी ने यह भी उम्मीद बनाई है कि बैंकों और कॉरपोरेट के सुदृढ़ तुलन पत्र, बुनियादी ढांचे पर खर्च पर नीतिगत जोर और बढ़ते कारोबारी आशावाद से निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में अस्थिरता और भू-आर्थिक विखंडन के जोखिमों के

बावजूद, एमपीसी ने उम्मीद जताई कि 2024-25 में वास्तविक जीडीपी 7.2 प्रतिशत से बढ़ेगी, जो पिछले वर्ष हासिल की गई 8.2 प्रतिशत की विकास दर से अधिक होगी। अनुमान है कि मुख्य मुद्रास्फीति 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.5 प्रतिशत हो जाएगी, जिसमें एक ओर प्रतिकूल जलवायु घटनाओं की बढ़ती घटनाओं, इनपुट लागतों के दबाव और कच्चे तेल की कीमतों और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से होने वाले जोखिम और दूसरी ओर खाद्य कीमतों पर मानसून के सकारात्मक प्रभावों के बीच संतुलन बना रहेगा।

एमपीसी के अनुसार, हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है, जो इसके मुख्य घटक में नरमी के कारण है, लेकिन मुद्रास्फीति का मार्ग अस्थिर और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से बाधित है, जो 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान लक्ष्य से नीचे एक अस्थायी गिरावट के बाद इसे उलट सकता है। इसके परिणामस्वरूप, लक्ष्य के साथ मुख्य मुद्रास्फीति के एक टिकाऊ संरेखण के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता खाद्य मूल्य दबावों से लेकर मुख्य मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं तक के स्पिलओवर की सावधानीपूर्वक निगरानी की गारंटी देगी। यह मुद्रास्फीति विरोधी रुख को जारी रखने की आवश्यकता है, जैसा कि आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास के शब्दों में है, "... अभी भी काम किया जाना बाकी है। ... मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से स्थिर करने और समय के साथ निरंतर विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने के लिए मूल्य स्थिरता पर पूरी तरह केंद्रित है।"

²² एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति 5 जून 2024।